• ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिगरा! • उपलब्धियों पर भारी चुनौतियां

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

अबकी बार 24 पर दांव

वर्ष 18, अंक-19 | 1 से 15 जुलाई 2020 | मूल्य 25 रूपये

चीन की चालबाजी और चौतरफा चुनौतियां

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2018-20

मध्यप्रदेश शासन

समाज के सहयोग से कोरोना के विरुद्ध बड़ा कदम

"किल कोरोना अभियान"

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

शुभारंभ

1 जुलाई, 2020

सुबह 11.00 बजे, समन्वय भवन, भोपाल

''मध्यप्रदेश में जनता के सक्रिय सहयोग से कोरोना के नियंत्रण में देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी सफलता मिली है। कोरोना वायरस को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम सामुदायिक सहभागिता से बड़ा अभियान ''किल कोरोना अभियान'' प्रारंभ कर रहे हैं।
आइये, हम सभी इस अभियान को सफल बनाकर प्रदेश को कोरोना मुक्त करें।''

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

1 से 15 जुलाई 2020 तक चलेगा अभियान

डोर-टू-डोर सर्वे कर कोविड संदिग्ध व्यक्तियों की होगी पहचान

प्रत्येक परिवार का होगा सर्वे

लाइव

CMO Facebook
@CMMadhyaPradesh
Jansampark Facebook
@Jansampark.madhyapradesh
Health Facebook
@healthservicesdeptmp
CMO Twitter
@CMMadhyaPradesh
Jansampark Twitter
@JansamparkMP

- सर्दी-खांसी, जुकाम, इंफ्लूएंजा और श्वसन संबंधी बीमारियों के संदेहास्पद मरीजों के अलावा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के संदेहास्पद मरीजों का भी होगा चिन्हांकन।
- प्रत्येक टीम को दिये जायेंगे नॉन कॉन्टेक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर एवं आवश्यक सुरक्षा सामान।
- चिन्हांकित मरीजों की सैम्पलिंग के बाद RTPCR तथा TRUNAT के माध्यम से होगी टेस्टिंग।
- महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे शामिल।
- प्रतिदिन होंगे लगभग 21 हजार टेस्ट। प्रदेश भर से 3 लाख सैम्पल लेने का लक्ष्य।
- किल कोरोना अभियान के बाद प्रदेश की प्रति मिलियन टेस्ट क्षमता 4022 से बढ़कर 7747 होना अपेक्षित। यह राष्ट्रीय औसत से अधिक।

Virus Covid-19

11 हजार से अधिक टीम करेंगी सर्वे

स्वैच्छिक रूप से कार्य करेंगे 'कोविड मित्र'

सामुदायिक सहभागिता होगी सुनिश्चित।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

इस अंक में

चौसर

9 | विकास की सौगात

मप्र में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 22 वे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां के विधायकों ने विकास कार्य नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है।

राजपथ

10-11 | अबकी बार 24 पर दांव

राज्यसभा चुनाव में जोर आजमाइश के बाद अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। मप्र में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी भी तरह से 230 सीटों पर हुए विधानसभा...

भर्राशाही

16 | अधर में ग्राम युवा शक्ति समिति

पचायतों में अब ग्राम युवा शक्ति समिति नहीं बनेंगी। कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 11 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया था। इसे गांव में नशामुक्ति को बढ़ावा देने से लेकर विभिन्न योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाने का जिम्मा सौंपा...

स्वास्थ्य

18 | 'किल कोरोना' अभियान

मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है। इसे किल कोरोना अभियान नाम दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान चलाने...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

पड़ोसी से अच्छा कोई मित्र नहीं और पड़ोसी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इस लोकोक्ति को भारत से अधिक और कौन जान सकता है। क्योंकि इन दिनों भारत अपने पड़ोसी देश चीन की चालबाजी और अन्य पड़ोसियों की दखल अंदाजी से घिरा हुआ है। चौतरफा चुनौतियों के बीच भारत को अपने पड़ोसी देशों से भी जूझना पड़ रहा है। आखिर हमारी विदेश नीति में ऐसी कौन-सी खामी आ गई है, जिसके कारण पड़ोसी देश हमें दुश्मन समझने लगे हैं।

राजनीति

30-31 | राहुल गांधी रिटर्न्स!

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए।

सियासत

32-33 | उपलब्धियों पर भारी चुनौतियां

वर्तमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मेहरबान हो सकता है लेकिन इतिहास उनके प्रति बहुत निष्ठुर रहेगा। मोदी अपने तमाम अनुचित फैसलों को लेकर बचते आ रहे हैं, जिनमें बड़ी भूलें भी शामिल हैं और आने वाले सालों में भी शायद वो यही करते रहेंगे क्योंकि दयालु मतदाता अपने सम्मान से उन्हें...

राजस्थान

35 | बढ़ रही खाई

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला राज्यसभा चुनावों को लेकर विधायकों की हुई बाडेबंदी से जुड़ा है। सचिन ने बिना नाम लिए फिर मुख्यमंत्री...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

मीडिया को मंडी बनाते धंधेबाज

मशहूर फिल्म कहानी लेखक सलीम खान की ये पंक्तियां गौर करने वाली हैं...

आज कलम का कागज से मैं दंगा करने वाला हूं,
मीडिया की सच्चाई को मैं नंगा करने वाला हूं।

सवाल उठता है कि हमेशा सामाजिक उत्थान वाली फिल्मों की पटकथा लिखने वाले सलीम खान ने ये पंक्तियां क्यों लिखी हैं? दरअसल, इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आज मीडिया धंधेबाजों की मंडी बन गया है। बड़े-बड़े धंधे करने वाले अपने काले कारनामों को प्रवाह देने मीडिया हाउस स्थापित कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में दीमक लग गया है। जुगाड़ संस्कृति हावी है। पांव पसारती अखबारी-बनियागिरी ने पत्रकारिता को चौपट कर दिया है। ऐसे उदाहरण हमारे सामने कई आए हैं, लेकिन ताजे मामले मप्र की व्यावसायिक राजधानी में सामने आए हैं। यहां के दो मीडिया हाउस अपनी काली करतूतों के कारण पत्रकारिता जैसे पावन कार्य पर कालिख पोत चुके हैं। एक ने ब्लैकमेलिंग, गुंडई, दबंगई और तस्करी को संरक्षण देने के लिए मीडिया को सहारा बनाया। वहीं दूसरे ने अपने जहरीले कारोबार को संरक्षण देने के लिए मीडिया को सहारा बनाया। हद तो यह है कि सबकुछ जानते हुए भी शासन-प्रशासन ने इनको संरक्षण दिया। यही नहीं एक महाशय को तो राज्य स्तरीय अधिमान्यता भी दे दी गई थी, जबकि कलम घिस-घिसकर बूढ़े हो चले कई पत्रकार आज भी अधिमान्यता के लिए तरस रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी प्रदेश के बड़े शराब व्यावसायियों को राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की गई थी। दरअसल, मीडिया को मंडी बनाने वाले इन धंधेबाजों ने पैसे के दम पर वह हर रसूख पाने की कोशिश की है, जो बड़े-बड़े लिखक्कड़ पत्रकार भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इससे मीडिया की साख में गिरावट आ रही है। मीडिया की नैतिकता का क्षरण हो रहा है। मीडिया की नैतिकता में आ रही गिरावट को अगर रोकना है तो एक छोटा सा कदम ये हो सकता है कि धंधेबाजों को धंधेबाजों के तौर पर ही पहचाना जाए। अखबारों और न्यूज चैनलों का धंधा करने वालों के लिए भी कड़े नियम बनाए जाएं ताकि वे पत्रकारिता का इस्तेमाल अपने दूसरे धंधों को चमकाने में न कर सकें। इस लिहाज से क्रॉस मीडिया होल्डिंग और क्रॉस बिजनेस होल्डिंग पर लगाम लगाना जरूरी है। यानी ऐसा न होने पाए कि एक व्यक्ति फिल्म बनाए और अपने समाचार माध्यम में उसका प्रचार भी करे या कोई धन्ना सेठ अपने दो नंबर के धंधों को चलाने और सत्ता की दलाली के लिए मीडिया का मालिक बनकर उसका मनमाना उपयोग करे। और यह एक कटु सत्य है। पत्रकारिता अब आदर्श नहीं, सेवा भाव नहीं बल्कि धंधा है जैसे कोई दूसरा धंधा होता है। यही कारण है कि आज धंधेबाज पत्रकारिता को अपनी ढाल बना रहे हैं। ऐसे ही लोगों के कारण अब पत्रकार 'वॉचडाग' नहीं, 'लैपडॉग' कहलाने लगा है। आदर्श और सत्य सब ताक पर, धंधेबाज अपने हिसाब से पत्रकारों से काम कराता है। सत्ता और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली मीडिया राज्य सरकारों के समक्ष नायक और निर्णायक की भूमिका में रही है, लेकिन पिछले दो दशकों के दौरान मीडिया से जुड़े ज्यादातर पत्रकारों के बीच उपजी लालसा ने उसकी गरिमा को खासी चोट पहुंचाई है। सरकारी लाभ लेने से लेकर अवैध उगाही में लिप्त कथित धंधेबाज पत्रकारों ने मीडिया के दायित्वों और उसके मिशन को अर्श से फर्श पर ला पटका है। मीडिया को मंडी बनाने पर तुले ऐसे धंधेबाजों को शासन-प्रशासन अगर महत्व न दे तो निश्चित रूप से मीडिया की पावनता बरकरार रह सकती है।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 19, 1 से 15 जुलाई, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अस्पतालों में व्यवस्था हो

प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अभी पूरे प्रदेश के कुल अस्पतालों में करीब 1200 आईसीयू हैं। प्रदेश की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और अस्पतालों में व्यवस्था को और दुरुस्त करना चाहिए।

● **विमलेश साहू,** भोपाल (म.प्र.)

गेहूं खरीदी में नंबर–1

मप्र में इस बार जो गेहूं खरीदी हुई है, उतनी पहले नहीं हुई। इस बार गेहूं खरीदी के मामले में मप्र ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश ने इस बार ऑल टाइम रिकॉर्ड बना है। कोरोना संक्रमणकाल और लॉकडाउन के इस दौर में भी प्रदेश ने नंबर–1 का रिकॉर्ड बना लिया है।

● **राजेश सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

चुनाव की तैयारी

आगामी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी हैं। सभी पार्टियों ने इन क्षेत्रों में प्रभारियों को तैनात कर दिया है। मुख्य मुकाबला तो भाजपा–कांग्रेस के बीच का है, लेकिन अन्य पार्टियां भी इसका फायदा उठाएंगी।

● **अनिकेत शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

लोगों को हो रही परेशानी

लॉकडाउन के कारण प्रदेशभर में बंद हुई बसें अब तक नहीं चल पाई हैं। इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में लोग पैदल या लिफ्ट लेकर ऑफिस आने–जाने के लिए मजबूर हैं। एक तो पहले ही लॉकडाउन के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लोगों को दोहरी तंगी की मार झेलनी पड़ रही है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी लोगों को टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीबी में आटा गीला हो रहा है। प्रदेश की सरकार को लोगों को बारे में कुछ सोचना चाहिए। और बसों का संचालन शुरू कराना चाहिए। जिससे लोगों को परेशानी न हो।

● **निरंजन चौहान,** सीहोर (म.प्र.)

अर्थव्यवस्था आएगी पटरी पर

कोरोनावायरस के कारण पूरे देश में किए गए लॉकडाउन से उद्योगों को भारी झटका लगा है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन और अच्छे प्रयासों की जरूरत है। पिछले कुछ समय में सरकार की ओर से जो राहत और प्रोत्साहन पैकेज जारी किए गए हैं, उससे यह उम्मीद तो बंधी है कि कारोबार फिर से पटरी पर लौटेगा, लेकिन यह सरकार और उद्योगों दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। लघु उद्योग के लिए भी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है।

● **शिव सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

सपना साकार होगा

प्रदेश में पुलिसकर्मियों के होनहार बच्चों को पुलिस विभाग की तरफ से स्कॉलरशिप देने का फैसला काबिले तारीफ है। प्रदेश के डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के बच्चों के बारे में सोचा है। कई बार आर्थिक तंगी के कारण पुलिसकर्मी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन अब विभाग की तरफ से उन्हें मदद मिलेगी तो उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार हो सकेगा।

● **अभिनव राजपूत,** शिवपुरी (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

सस्पेंस अभी भी कायम

पहले भाजपा में रहे नवजोत सिंह सिद्धू इस समय कांग्रेस में हैं। लेकिन वे कब किस पार्टी में चले जाएं इसको लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सिद्धू पाजी के जाने की अटकलें पंजाब के 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी खूब चली थी। जानकारों का कहना है कि सिद्धू की 2016 में आम आदमी पार्टी से सौदेबाजी हो नहीं पाई थी क्योंकि वे पार्टी की तरफ से चुनाव में खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराना चाहते थे। भाजपा से उनका मन खट्टा होने की बड़ी वजह शिरोमणि अकालीदल की सरकार के प्रति उनका आलोचनात्मक रुख भी था। चूंकि विकल्प था नहीं सो थक-हार कर विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे और अमृतसर पूर्व की विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए थे। हसरत तो उनकी उपमुख्यमंत्री बनने की बेशक थी पर कैप्टन ने मंत्री पद से ज्यादा कुछ न दिया। पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय निकाय मंत्री बन तो वे जरूर गए पर कैप्टन से उनकी ज्यादा पट नहीं पाई। नतीजतन पिछले साल जुलाई में कैप्टन ने स्थानीय निकाय विभाग उनसे छीन लिया था। नाराज सिद्धू ने इसके बाद मंत्री पद से ही अपना इस्तीफा तब के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दिया था। उसके बाद से वे सियासी दुनिया से दूर हो गए। अब एक बार फिर उनके पार्टी बदलने के कयास लगने लगे हैं।

चक्रव्यूह में रामदेव

स्वामी रामदेव की स्थिति शोले फिल्म के किरदार सांबा जैसी हो गई है। गब्बर सिंह ने उसका जिस अंदाज में मजाक उड़ाया था, वह हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। गब्बर बोला था- अरे ओ सांबा। तुमने क्या सोचा था कि सरदार खुश होगा और शाबाशी देगा। स्वामी रामदेव ने गत दिनों जब अपनी दवा कोरोनिल लांच की और दावा किया कि कोविड-19 के उपचार में यह अचूक और रामबाण साबित होगी। बड़े खुश थे रामदेव। होना स्वाभाविक भी था। सारी दुनिया आज जिस रहस्यमय बीमारी से त्राहि-त्राहि कर रही है, उसकी दवा ईजाद हो जाए तो चमत्कार ही माना जाएगा। रामदेव ने सोचा था कि यश तो मिलेगा ही पतंजलि योग फार्मेसी का कारोबार भी अरबो-खरबों में पहुंच जाएगा। दुनिया के तमाम विकसित देश जिस बीमारी की दवा अब तक न खोज पाए हों,

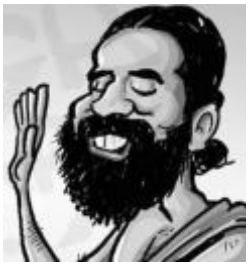

उसका निदान रामदेव ने खोजने का न केवल दावा किया बल्कि अनेक कोरोना संक्रमितों पर उसके परीक्षण का दावा भी कर डाला। पर कुछ घंटों के भीतर ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने उनकी खुशफहमी की हवा निकाल दी। न केवल रामदेव के दावे को अनुचित बताया बल्कि कोरोनिल के प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगा दी। ऊपर से नोटिस अलग थमाया कि रोगियों पर परीक्षण से पहले सरकार से इजाजत क्यों नहीं ली? अब बाबा सफाई देते फिर रहे हैं।

दूर की कौड़ी

उत्तराखंड छोटा सूबा जरूर है पर सियासी उठापटक के मामले में बेहद सक्रिय है। तभी तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल यों तो फरवरी 2022 तक है और सदन में सत्तारूढ़ भाजपा का बहुमत भी दो तिहाई से ज्यादा है। यही तो पेंच भी है कि सरकार को तो कोई खतरा नहीं और विपक्ष को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह निश्चिंत हैं। टांग तो उनकी गैर नहीं अपने ही खींच रहे हैं। अनुभव और वरिष्ठता को मापदंड मानें तो भाजपा में ज्यादातर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत से वरिष्ठ हैं। सतपाल महाराज हों या विजय बहुगुणा, मदन कौशिक हों या रमेश पोखरियाल निशंक, सब कद्दावर ठहरे। बीमार न पड़े होते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तो अनिल बलूनी ही भारी पड़ जाते। राज्यसभा सदस्य हैं बलूनी। पार्टी के भरोसेमंद। नई भाजपा के ब्राह्मण चेहरे। दिल्ली दरबार और संघ के गलियारों में माहौल बनाया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से सूबे के लोग खुश नहीं हैं। उन्हें आलाकमान ने हटाया नहीं तो अगले चुनाव में कांग्रेस की बल्ले-बल्ले तय है। मुख्यमंत्री विरोधी खेमा तो दावा कर रहा है कि कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ होता तो अब तक रावत की छुट्टी हो चुकी होती।

पेच फंसा है जात का

हरियाणा में भाजपा का नया सूबेदार कौन होगा, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दिल्ली-दौरे के बाद चर्चा गरम रही कि जेपी नड्डा इस बाबत फैसला जल्द करने के मूड में हैं। पार्टी आलाकमान तय नहीं कर पा रहा है कि सूबेदारी किसी जाट नेता को सौंपे या गैर जाट को। जाटों की आबादी सूबे में करीब 27 फीसदी है। जाट लॉबी का तर्क है कि गैरजाट मनोहरलाल को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ। जहां 2014 में पार्टी किसी चेहरे के बिना चुनावी जंग में उतरी थी तो उसे 90 में से 47 सीटों पर सफलता मिली थी। जबकि 2019 में मनोहरलाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो कामयाबी महज 40 सीटों पर मिल पाई। पर इसी नतीजे का विश्लेषण भाजपा को बराला की जगह फिर किसी जाट को ही सूबेदार बनाने से रोक रहा है। पार्टी को लगता है कि जाट मतदाता या तो कांग्रेस के साथ हैं या दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ।

पथरीली राह

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस के संख्या बल के अनुरूप ही रहे। क्रॉस वोटिंग का हल्ला तो खूब मचा पर हुई नहीं। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनियोजित रणनीति के तहत यह आरोप लगाया था कि भाजपा उनके विधायकों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा के अपने 72 और बेनीवाल की पार्टी के तीन विधायकों का उसे समर्थन है। खरीद-फरोख्त का शोर मचा दोहरा लाभ हासिल किया। एक तरफ अपना लोहा मनवाया, दूसरी तरफ पार्टी में अपने विरोधी सचिन पायलट को दिखा दिया कि हर फन में माहिर हैं। लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। सचिन पायलट से पार्टी की सूबेदारी लेकर अपने किसी भरोसेमंद को दिला पाना और डेढ़ साल से मंत्री पद की बाट जोह रहे पूर्व बसपाई व निर्दलीय विधायकों के असंतोष पर नियंत्रण रख पाना। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भाजपा ने सचिन पायलट को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चलाने के जतन छोड़े नहीं है।

समाज का पदाधिकारी होना जरूरी

कोई कितना भी दावा करे, दम भरे, लेकिन यह बात सत्य है कि शासन और प्रशासन में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद चरम पर रहता है। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तो इस समय कुछ लोग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आप अमूक समाज के किसी पदाधिकारी के नाते-रिश्तेदार हैं तो आपको कलेक्टर और एसपी आसानी से बनाया जा सकता है। आलम यह है कि अब तो कुछ नौकरशाह उक्त समाज के पदाधिकारियों से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए हैं। उनकी दाल गलेगी कि नहीं यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उक्त समाज के एक पदाधिकारी के एक रिश्तेदार ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले के एसपी बन गए हैं। तब से ही ये हवा चल पड़ी है कि अगर आप अमूक समाज के पदाधिकारी के नाते-रिश्तेदार हैं तो आपके लिए किसी भी जिले की कलेक्टरी और कप्तानी आसानी से मिल जाएगी। गौरतलब है कि जिस समाज की बात हो रही है, वह समाज प्रदेश की राजनीति में पिछले 10-12 सालों में तेजी से उभार पर है। इस समाज की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मप्र की ही हैं। ऐसे में इस समय प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में भी इस समाज का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में इस समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, वे भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने समाज के अफसरों को नातेदार बनाकर आगे बढ़ाया जाए।

सरकार चलाए पप्पू, संघ चलाए चप्पू

शीर्षक पढ़कर हैरान होने की जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह सत्य है। दरअसल, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में यह प्रचलित है कि भाजपा के शासनकाल में सत्ता का संचालन ऐरा-गैरा कोई भी करे, लेकिन सत्ता की नाव का चप्पू तो संघ ही चलाता है। यही कारण है कि भाजपा शासन में संघ हमेशा ही शक्ति संपन्न रहता है। इसकी वजह भी है। दरअसल, भाजपा को चुनावी रण में विजय दिलाने के लिए संघ ही मैदानी जमावट करता है, साथ ही चुनाव जिताने की जिम्मेदारी उठाता है। प्रदेश में इस समय 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में संघ भाजपा संगठन से अधिक सक्रिय नजर आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि संघ की सक्रियता के बीच भाजपा के रणनीतिकारों ने संघ से चुनाव वाले क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त करने की इच्छा जताई है। लेकिन संघ ने सिरे से उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि संघ ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि इन सीटों पर जीत दिलवाने की जिम्मेदारी हमने उठाई है। इसलिए यहां राजनीतिक प्रपंच की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि चुनावी दौर में नेताओं की कोशिश रहती है कि वे चुनाव वाले क्षेत्रों में अपनी सक्रियता दिखाकर सरकार और संगठन की आंख का तारा बने। लेकिन संघ ने ऐसे नेताओं की मंशा पर पानी फेर दिया है। भाजपा के रणनीतिकार भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि सरकार भले ही पप्पू चलाए, लेकिन चप्पू तो संघ को ही चलाना है।

स्थानांतरण के लिए तीन नोटशीट

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक महिला पुलिस अधिकारी की खूब चर्चा है। वैसे तो उक्त महिला अधिकारी की चर्चा अन्य अधिकारी चटखारे लेकर करते रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय है कि सभी लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। यही नहीं एक मंत्री ने तो उनके स्थानांतरण के लिए तीन नोटशीट तक लिख डाली है। उक्त महिला अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि वे एक जिले में एडीशनल एसपी के पद पर पदस्थ हैं। वे राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। उनका चाल-चलन कुछ ऐसा है कि जहां उन्हें कुछ लोग पसंद करते हैं तो अधिकांश उनसे खार खाए रहते हैं। उक्त महिला अधिकारी के खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। इसको देखते हुए एक मंत्रीजी ने गृह विभाग को उनका स्थानांतरण करने की नोटशीट लिखी है। हद तो यह है कि एक नहीं बल्कि मंत्रीजी ने तीन नोटशीट लिखी हैं। उधर, गृह विभाग के बाबू से लेकर अधिकारी तक जानते हैं कि मैडम किस पानी की हैं। वैसे तो हर अधिकारी की यही कोशिश रहती है कि मैडम का सानिध्य उन्हें मिले। लेकिन जो इसमें सफल नहीं होता है वह उनसे जलता है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में उक्त मैडम चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब देखना यह है कि मंत्रीजी द्वारा लिखी गई नोटशीट का क्या असर पड़ता है। अगर उनका तबादला होता है तो क्या वे अपनी कार्यप्रणाली को सुधार पाएंगी, ताकि फिर कोई उन पर कोई आक्षेप न लगा सके।

क्या गुल खिलाएगा शतक

मप्र में सरकार के साथ ही कोरोना का भी शतक पूरा हो गया है। पहले दिन से लेकर आज तक जहां सरकार हिचकोले खा रही है, वहीं कोरोना लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी उसका मंत्रिमंडल अधूरा है। इस अधूरे मंत्रिमंडल को पूरा करने के लिए जोर-आजमाइश चरम पर है। वहीं कोरोना सरकार की सारी पाबंदियों को तोड़कर निर्वाध आगे बढ़ रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के सबसे सुरक्षित स्थल यानी मंत्रालय में भी कोरोना का प्रवेश हो चुका है। पहले कोरोना दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसको रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए गए। तमाम प्रबंध के बाद भी वह तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। इससे और हड़कंप मचा। लेकिन वह यही नहीं रुका और अब पांचवी मंजिल पर पहुंच गया है। 100 दिन में जहां सरकार कुछ कदम आगे बढ़ी है, वहीं कोरोना मंत्रालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया है। कुछ लोग इसके लिए मंत्रालय के वास्तु-दोष को दोषी मान रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद सरकार का गठन सही मुहूर्त पर नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार और कोरोना का शतक क्या गुल खिलाता है।

एक करोड़ का सवाल

प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए हुए चुनाव में जिस तरह का माहौल इस बार दिखा वैसा शायद ही पहले कभी दिखा हो। पहले तो दोनों पार्टियों ने 2 सीटें जीतने का दम भरा। उसके बाद शिकवा-शिकायत का दौर चला। फिर वोट खरीदने के आरोप-प्रत्यारोप लगे। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच अपने-अपने विधायकों को वोट डालने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए सबसे अधिक तैयारी भाजपा ने की थी। लेकिन भाजपा के ही एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व मंत्री रहे एक पूर्व विधायक को मतदान की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया था, लेकिन वे भी अपने कार्य में विफल रहे। अब क्रॉस वोटिंग को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने सपा-बसपा और निर्दलियों का वोट पाने के लिए एक-एक करोड़ रुपए पर सौदा किया था। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने भी भाजपा विधायक को एक करोड़ रुपए क्रॉस वोटिंग के लिए दिए हों। हकीकत क्या है, यह तो यही लोग जानें।

चीन से तनाव के बीच में भारत हमारे देश पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम भी जवाब देंगे। भारत हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंदरूनी तैयारी कर रहा है। हम बता देना चाहते हैं कि हमारा देश किसी से कमजोर नहीं है।

● **शाह महमूद कुरैशी**

मैं अमेरिका के उस फैसले से निराश हूं, जिसके तहत उसने एच-1 बी सहित कई वर्क वीजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। मेरी कंपनी गूगल प्रवासियों के साथ खड़ी है। इससे अमेरिका को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसके एक निर्णय से विदेशी प्रतिभाओं का लाभ अमेरिका को नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमेरिका पुन: विचार करे।

● **सुंदर पिचाई**

क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पर रोक तभी लग सकती है, जब भारत इसके लिए कठोर कानून बनाएगा। फिलहाल इसको लेकर कोई कानून नहीं है। इसके बावजूद भारतीय पुलिस के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। आईसीसी के पास अभी मैच फिक्सिंग रोकने के लिए सीमित संसाधन हैं।

● **स्टीव रिचर्डसन**

कुछ दिनों से सोनू निगम टी-सीरीज और भूषण कुमार के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। टी-सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है, जो बाहरी हैं। सोनू निगम ने कितनों को ब्रेक दिया है। वे खुद 5 रुपए में दिल्ली की रामलीला में गाना गाते थे।

● **दिव्या कुमार खोसला**

सेक्सी और बोल्ड जैसे टैग मिलने पर मुझे बहुत गंदा महसूस होता था। जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ये टैग मिलने शुरू हो गए थे। जब मैं बाहर निकलती थी तो लोग बोलते थे ओह... रिया सेन! शायद उन्हें लगता था कि जैसी मैं फिल्मों में नजर आती हूं, रियल लाइफ में भी वैसी ही हूं। हिंदी फिल्म हीरोइन की इमेज में फिट होना मुझे बहुत परेशान करने लगा था। हर कोई ग्लैमरस होना चाहता है लेकिन मैं बहुत छोटी थी जब यहां आई। मैं वो रोल्स करती थी जिनमें मैं मिनी स्कर्ट, बिकिनी पहने, क्यूट बनकर इधर-उधर घूम रही होती थी। मैं खुद को देखती थी और कहती थी-हि...स्स्स, मैं विश्वास नहीं कर सकती ये मैं हूं। मुझे बहुत खराब और असहज महसूस होता था। तब मैंने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया। वो बॉलीवुड का नुकसान था और बांग्ला सिनेमा अलग ऊंचाइयों पर पहुंच गया।

● **रिया सेन**

वाक्युद्ध

देश कोरोनावायरस की महामारी से जूझ रहा है और केंद्र की भाजपा सरकार चुनावी तैयारी में लगी हुई है। इस समय देश को जरूरत है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उनकी चिंता करें, लेकिन इन दोनों को बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता लगी हुई है।

● **राहुल गांधी**

राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्हें यह भी मालूम नहीं कि सरकार क्या कर रही है। कोरोना संक्रमण हो या चीन की समस्या सरकार दोनों मोर्चों पर मुश्तैदी से जुटी हुई है। राहुल गांधी को फिलहाल अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ही दिशा से भटक रही है।

● **अमित शाह**

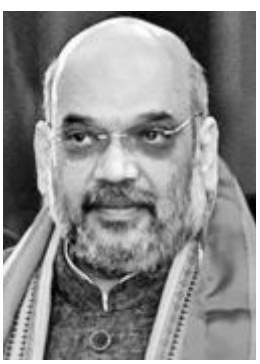

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 15 माह के शासनकाल के दौरान खस्ताहाल हुई मप्र की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए भाजपा सरकार ने खजाना खोल दिया है। खासकर जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, वहां सड़कों के निर्माण कार्य सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात दी गई है।

विकास की सौगात

मप्र में आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 22 वे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां के विधायकों ने विकास कार्य नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इन पूर्व विधायकों का आरोप था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई फंड मुहैया नहीं कराया था। अब भले ही इन नेताओं की विधायकी चली गई है, लेकिन भाजपा सरकार ने इनके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की ठानी है।

यही नहीं इन पूर्व विधायकों को भी डर सताने लगा है कि जब वे उपचुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो जनता उनसे 2018 के चुनाव में किए गए वादों का हिसाब न पूछने लगे। इसलिए अब इन्हें अपने क्षेत्र के विकास की चिंता सताने लगी है। इसलिए इन सभी पूर्व विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में जो बड़े विकास कार्य कराए जाने हैं, उसकी सूची मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को सौंपकर स्पेशल पैकेज की मांग की है। विधायकों की मांग पर सरकार ने उनके क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण के लिए राशि मंजूर कर दी है। कई क्षेत्रों में कार्य भी शुरू हो गए हैं।

लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों हुई प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठकों में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के विकास के लिए राशि मंजूर की गई। जानकारी के अनुसार मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 9.30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसी तरह बदनावर के लिए 15.55 करोड़, सांची में सड़क निर्माण के लिए 6.62 करोड़ तथा पुल निर्माण के लिए 11.73 करोड़, करैरा में सड़क निर्माण के लिए 6.62 करोड़ और पुल निर्माण के लिए 5.20 करोड़, बमौरी में सड़क निर्माण के लिए 3.23 और पुल निर्माण के लिए 5.42 करोड़, सुवासरा में सड़क निर्माण के लिए 13.73 करोड़, हाटपिपल्या में सड़क निर्माण के लिए 15.52 करोड़, पोहरी में सड़क निर्माण के लिए 14.58 करोड़, अशोकनगर में सड़क निर्माण के लिए 10.49 करोड़, अम्बाह में सड़क निर्माण के लिए 15.77 करोड़, ग्वालियर में सड़क निर्माण के लिए 16.34 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

वहीं ग्वालियर पूर्व में सड़क निर्माण के लिए 9.08 करोड़ और पुल निर्माण के लिए 2.64 करोड़, गोहद में पुल निर्माण के लिए 13.59 करोड़, मेहगांव में सड़क निर्माण के लिए 10.40 करोड़ और पुल निर्माण के लिए 3.31 करोड़, सुमावली में पुल निर्माण के लिए 17.56 करोड़, अनूपपुर में सड़क निर्माण के लिए 33.10 करोड़, दिमनी में सड़क निर्माण के लिए 15.42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जौरा और आगर के लिए अभी कोई प्रपोजल नहीं आया है, जबकि मुरैना में सड़क निर्माण के लिए 11.16 करोड़, डबरा में सड़क निर्माण के लिए 3.76 करोड़, सुरखी में सड़क निर्माण के लिए 17.23 करोड़, सांवेर में सड़क निर्माण के लिए 8.33 करोड़ और भांडेर में सड़क निर्माण के लिए 15.23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 310.71 करोड़ रुपए सड़कों और पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही इन क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों के लिए सरकार जल्द ही बड़े पैकेज की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए विकास कार्य करवा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि अगर भाजपा ने अपने 15 साल के शासनकाल के दौरान विकास कार्य कराए होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि भाजपा हमेशा विकास पर जोर देती है। कांग्रेस के 15 माह के शासनकाल के दौरान प्रदेश में विकास की गति पूरी तरह रुक गई थी। अब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार है इसलिए विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। केवल चुनावी क्षेत्रों में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य चल रहे हैं।

● **जितेन्द्र तिवारी**

3500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार

प्रदेशभर में सड़कों के निर्माण, मरम्मत आदि के लिए मप्र सरकार 3500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से चर्चा की है, साथ ही पत्र भी भेजा है। मप्र सरकार की कोशिश है कि वह प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए कम से कम ब्याज दर पर कर्ज ले। इसलिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने इन बैंकों से चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि अभी तक लंबी अवधि के लिए 8.9 प्रतिशत की दर से कर्ज लिया जाता रहा है, लेकिन अब सरकार की कोशिश यह है कि प्रदेश में सड़कों, पुल और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 3 प्रतिशत की दर पर कर्ज लिया जाए। इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से पहले दौर की चर्चा हो चुकी है। जल्द ही यह डील फाइनल हो सकती है।

उपचुनाव के सियासी रण में भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के सामने कम से कम 9 सीटें जीतने की चुनौती है, ताकि सरकार बनी रहे, तो कांग्रेस के सामने बिखरी हुई ताकत समेटने और साख बनाने का मौका है। मैदानी तैयारी में भाजपा कांग्रेस से कहीं आगे है, क्योंकि भाजपा की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कांग्रेस भी धीरे-धीरे चुनाव वाले क्षेत्र में सक्रिय हो रही है।

अबकी बार 24 पर दांव

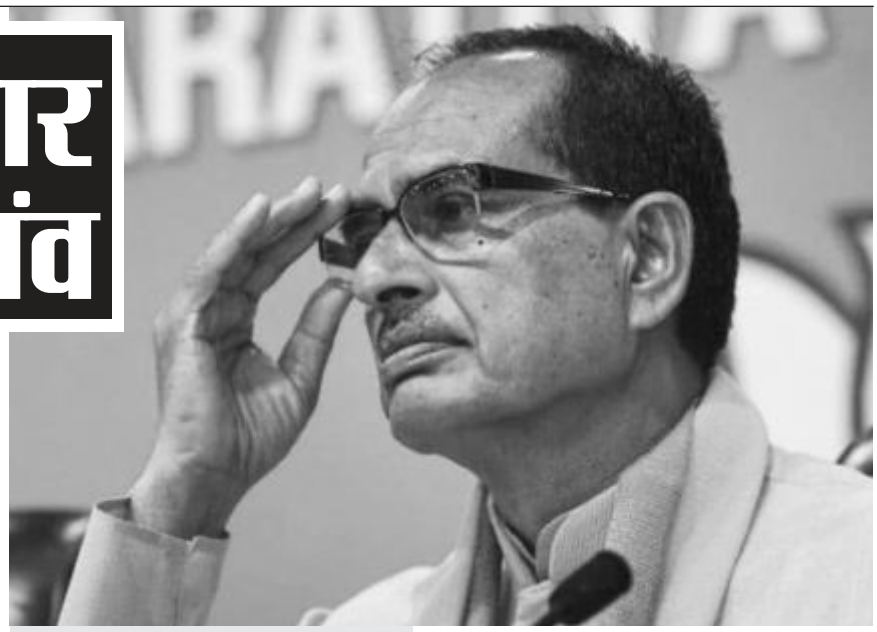

राज्यसभा चुनाव में जोर आजमाइश के बाद अब प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। मप्र में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव किसी भी तरह से 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव से कम नहीं होंगे। असल में इन उपचुनावों के बाद ही सरकार का स्थायी भविष्य तय होगा। मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के चलते भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाए और बचाए रखने के लिए उपचुनावों में जीत का सिलसिला कायम रखना पड़ेगा।

भारतीय राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को समन्वयकारी और संतुलन बनाकर काम करने वाला नेता माना जाता है। यही कारण है कि जब भी मप्र में चुनाव होता है संघ भाजपा के साथ खड़ा हो जाता है। दरअसल भाजपा और संघ परिवार आज इस मुकाम पर है तो निश्चित तौर से इसमें काम करने की **जीजीविषा और दृढ़** इच्छाशक्ति है। शिवराज की नीति का अहम सूत्र यह भी है कि संगठन हो या सरकार, उसमें ठहराव नहीं होना चाहिए बल्कि नदी के बहाव की तरह गतिमान होना चाहिए। इस नीति ने ही मप्र में भाजपा और विचार परिवार की ऐसी संगठनात्मक मशीनरी खड़ी कर दी है कि यहां की जनता शिवराज के आगे किसी अन्य के बारे में सोच नहीं पाती है।

शिवराज की समन्वयकारी राजनीति का ही नतीजा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने का निर्णय लिया और अब सिंधिया समर्थकों को फिर से विधायक और मंत्री बनाने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान ने अपने कंधे पर ली है। शिवराज पर आए इस बोझ को थामने के लिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संघ ने अपना कंधा लगा दिया है। इससे कांग्रेस की रणनीति फेल होने लगी है। भाजपा में जहां सांगठनिक एकता साफ दिख रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी बंटी नजर आ रही है।

24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान वैसे तो मुद्दों की भरमार रहेगी लेकिन मुख्य मुकाबला विश्वासघात बनाम धोखा में होगा। कांग्रेस के विश्वासघात के मुद्दे को जवाब देने के लिए संघ के दिशा-निर्देश पर भाजपा ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा जनता के साथ किए गए धोखे को मुद्दा बनाया है। इन सीटों को बचाना कई मायनों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस उन पूर्व विधायकों को सबक सिखाना चाहती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इसमें सत्ता वापसी का रास्ता देखते हैं। उधर दिग्विजय सिंह भी खुद को नाथ सरकार के लिए संकट बनने के आरोप से मुक्त करना चाहते हैं। वहीं भाजपा हर हाल में सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। इसलिए भाजपा के नेता और संघ के पूर्णकालिक विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच प्रचारित कर रहे हैं कि 15 माह के शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने किस तरह उन्हें धोखा दिया है। खासकर किसान कर्जमाफी को सबसे बड़े हथियार बनाया गया है। वहीं भाजपाई प्रवासी श्रमिकों और किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं और सहूलियतों को प्रचारित कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक माह में विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है।

विधानसभा का गणित

मध्यप्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, इनमें से 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे देने और दो विधायकों का निधन होने से 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है। भाजपा के पास फिलहाल 107 विधायक हैं, वहीं निर्दलीय, सपा और बसपा के 7 विधायक भी भाजपा के साथ खड़े हैं। उधर, कांग्रेस के पास 92 विधायक हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बहुमत से काफी दूर है। पार्टी के पास इस समय भाजपा को चुनौती देने वाले प्रत्याशी और नेता की भी कमी है। फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का दावा है कि उनकी पार्टी 18 से 20 सीटें जीतेगी। गौरतलब है कि 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस की कमान कमलनाथ और ज्योतिरादित्य दोनों ने मिलकर संभाल रखी थी। अब ज्योतिरादित्य के भाजपा में जाने के बाद चुनाव की कमान कमलनाथ के हाथ में है। हालांकि दिग्विजय सिंह इसमें निर्णायक रणनीतिकार माने जा रहे हैं। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता के साथ विश्वासघात करने वाले शख्स के रूप में प्रचारित कर रही है। ज्योतिरादित्य के साथ भाजपा में आए कांग्रेस के 22 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने यही अभियान चला रखा है।

उपचुनाव जीतने में शिवराज को महारत

उपचुनावों को लेकर भाजपा में संतोष नजर आ रहा है। इसकी एक वजह यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव जीतने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। मप्र में शिवराज सिंह चौहान के सत्ता संभालने से अब तक हुए उपचुनावों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस के लिए मुश्किलों का अंदाजा सहज लगता है। वर्ष 2004 से 19 तक हुए 30 उपचुनावों में 19 भाजपा जीती है, यानी 63.33 प्रतिशत। भाजपा ने अपनी 13 सीटें बचाई, तो कांग्रेस की 6 सीटें छीन ली। हालांकि उसे 6 सीटें गंवानी भी पड़ीं। जबकि कांग्रेस 10 सीटें जीत सकी यानी 33.33 प्रतिशत। वह 4 सीटें छीनने में कामयाब रही। ऐसे में कांग्रेस को अपने खाते की सीटें बचाने के लिए भाजपा से कड़ी चुनौती मिलना तय है। वहीं भाजपा हर हाल में 24 में से कम से कम आधी सीटें जरूर जीतना चाहेगी। ऐसे में भाजपा ने इसकी जिम्मेदारी अपने संकटमोचक यानी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी है। मिश्रा ग्वालियर दौरे पर वहां के दिग्गज नेताओं से वन-टू-वन बात कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर 22 विधायकों के लाव लश्कर के साथ महाराज गए तो उसमें से 16 ग्वालियर-चंबल के ही थे। अब इन सबके भाजपा में शामिल हो जाने के बाद भाजपा के पुराने और स्थापित नेताओं में बेचैनी है। उन्हें अपने राजनैतिक भविष्य पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, उनके नाराज और रूठने की खबरें सरकार और संगठन तक पहुंच रही हैं।

यही नहीं संघ की सलाह के बाद भाजपा उपचुनाव के लिए हर सीट का अलग घोषणा-पत्र (संकल्प-पत्र) बनाएगी। संकल्प-पत्र में संबंधित क्षेत्र के विकास का तीन साल का रोडमैप रहेगा। संकल्प-पत्र बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत और पूर्व मीडिया प्रभारी डॉ. हितेश वाजपेयी को दी गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी क्षेत्रों में जाकर वहां का घोषणा-पत्र जारी करेंगे। भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति हर सीट पर प्रबंध समिति का गठन करेगी। वहां का संकल्प-पत्र तैयार करने के लिए भी टीम रखी जाएगी। कांग्रेस में विधायक पद छोड़कर आने वाले भाजपा के भावी उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कि वे अपने क्षेत्र में क्या काम कराना चाहते हैं। इसके साथ ही उस जिले के अधिकारियों से भी चर्चा करके रुके हुए और निकट भविष्य में हो सकने वाले कार्यों की सूची ली जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस के पूर्व विधायकों के साथ वन-टू-वन चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने हर विधायक से उनके क्षेत्र में रुके हुए जरूरी कामकाज की सूची लेकर अधिकारियों को दी थी। सूत्रों के मुताबिक यह काम लगभग एक हजार करोड़ रुपए के हैं, जो शुरू हो चुके हैं। संकल्प-पत्र में इन कार्यों का भी हवाला दिया जाएगा।

उपचुनाव जीतने में माहिर हो चुके शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ नई पारी शुरू करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये उपचुनाव चुनौतीपूर्ण है। दोनों नेताओं की साख दांव पर है। भाजपा का दामन थामने वाले कांग्रेसी विधायक सिंधिया के समर्थक हैं। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे सीधे सिंधिया की ताकत बताएंगे, वहीं सीटों के गणित से सरकार बरकरार रही तो शिवराज और मजबूत होंगे। इधर, कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थक पूर्व विधायकों को जयचंद, गद्दार आदि कहकर लगातार कोसती रही है। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी सरकार जाने को इंटरवल बताकर उपचुनाव बाद वापसी का दावा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी इन उपचुनावों में जीत के जरिए उन आरोपों को गलत साबित करना चाहेंगे, जिसमें उन्हें नाथ सरकार के जाने का जिम्मेदार बताया जाता है। हालांकि इन सीटों पर प्रत्याशी तय कर उसे जीत दिलाने का संघर्ष दोनों दलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। कांग्रेस को नए सिरे से प्रत्याशी तय करने हैं, तो भाजपा को सिंधिया कोटे और अपने पुराने नेताओं के बीच से प्रत्याशी तय करना है।

इसमें संदेह नहीं है कि ये उपचुनाव बड़े सीमित मुद्दों पर लड़े जाएंगे। कांग्रेस सिंधिया समर्थक विधायकों को बिकाऊ बताकर घेरेगी। वह कमलनाथ सरकार के कामों को भी इस अंदाज में रखेगी, जिससे स्पष्ट हो सके कि एक बेहतरीन सरकार गिराकर इन विधायकों ने अपने क्षेत्र की जनता को **धोखा दिया** है। उधर, भाजपा के पास कोरोना से निपटने की उपलब्धि के साथ ही अपने पूर्व के 15 साल के शासनकाल की उपलब्धियां हैं। यही नहीं वर्तमान में शिवराज सरकार ने जिस तरह प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने का कदम उठाया है उससे उनकी साख एक बार फिर जम गई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शिवराज और सिंधिया की जोड़ी इतिहास जरूर रचेगी।

ये उपचुनाव कई मायने में ऐतिहासिक होंगे। प्रदेश के इतिहास में पहली बार एकसाथ 24 सीटों पर उपचुनाव होंगे। यही नहीं इन उपचुनावों के लिए सबसे अधिक समय तैयारी के लिए मिला है। वहीं अपनी तरह के सबसे अलग इस उपचुनाव में वोटों का समीकरण भी अलग होगा। हर सीट पर पार्टी, उसके किसी शीर्ष नेता और प्रत्याशी का अलग-अलग वोट बैंक होता है। भाजपा के टिकट पर जो सिंधिया समर्थक प्रत्याशी उतरेगा, उसके साथ अपने वोट बैंक के अलावा सिंधिया, भाजपा और शिवराज समर्थकों का वोट होगा। दूसरी तरफ 22 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी नए होना तय है, जिनके पास अपने वोट बैंक के अलावा कांग्रेस, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समर्थकों का वोट होगा। यानी वोटर्स भी बड़े पैमाने पर इस बार पाला बदलेंगे। ऐसे में जीत उसी के खाते में जाएगी, जिसका अपना वोट बैंक मजबूत होगा। ऐसे आंकलन के बीच निश्चित तौर पर दोनों दल तटस्थ रहकर ऐन वक्त पर रुख तय करने वाले वोटर्स को अपने पक्ष में करने के प्रयास अभी से कर रहे होंगे। इस बार के उपचुनाव में सरकार का बरकरार रहना या पुरानी सरकार की वापसी की संभावनाओं के साथ कई दिग्गजों का सियासी भविष्य भी दांव पर लगना तय है।

● **कुमार राजेन्द्र**

ज्योतिरादित्य का जिगरा!

आपातकाल की हर बरसी पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करना भाजपा के लिए बरसों से एक रिवाज बन गया है। इमरजेंसी की 45वीं बरसी पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के ज्यादा आक्रामक होने की वजह है राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों का ढंग से जवाब देने के लिए भाजपा को 25 जून का इंतजार जरूर रहा होगा। अमित शाह, रविशंकर प्रसाद से लेकर जेपी नड्डा तक, भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस को चैन की सांस लेने का कोई मौका देने के मूड में नहीं दिखे। चीन के साथ संबंधों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को दिल्ली में तो घेरा ही, मध्यप्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंच पर बिठा कर तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की और जैसे ट्विटर पर अमित शाह ने कांग्रेस नेता संजय झा के बहाने कांग्रेस को निशाना बनाया, कुछ-कुछ ऐसा लगता है जैसे भाजपा कांग्रेस के नाराज नेताओं को न्यौता दे रही हो।

ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना को मात देने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सामने आए। जून में ही कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सिंधिया को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और हाल ही में वो स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। भाजपा के मंच पर तो वो दिल्ली में पहले भी दिखे थे और फिर जब भोपाल गए तो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हाथों में हाथ डाले देखे गए थे, लेकिन जेपी नड्डा की वर्चुअल रैली सिंधिया को भी लंबे समय तक याद रहेगी। मध्यप्रदेश को लेकर भाजपा की रैली में नड्डा के साथ-साथ शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया का विशेष रूप से स्वागत किया।

अमित शाह के बिहार जनसंवाद से शुरू होने के बाद मध्यप्रदेश में अब तक भाजपा की दो वर्चुअल रैलियां हो चुकी हैं। जेपी नड्डा से पहले हुई रैली को नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया था। गडकरी की रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की कड़ी आलोचना की थी। कमलनाथ ने कहा कि एक तरफ लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, बीमारी से दम तोड़ रहे हैं और भाजपा उत्सव मनाने, उपलब्धि गिनाने और चुनाव लड़ने में जुटी है। जेपी नड्डा और सिंधिया के साथ भाजपा की दूसरी रैली में शिवराज सिंह ने कमलनाथ को उसी लहजे में जवाब भी दिया। दरअसल, मध्यप्रदेश में 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं और दोनों पार्टियां जोर-शोर से उसी की तैयारी में जुटी हैं। भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां होने की भी यही वजह है।

कमलनाथ को टारगेट कर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'कोरोना काल में जब हमने सत्ता संभाली और मैं वल्लभ भवन गया, तब कमलनाथ ने कोरोना से बचाव के लिए एक बैठक तक नहीं की थी, क्योंकि वो आईफा के आयोजन में व्यस्त थे। अगर कमलनाथ और कांग्रेस होती तो मप्र तबाह और बर्बाद हो जाता। शिवराज सिंह चौहान बर्बादी से मध्यप्रदेश को बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वैसे भी अगर सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन नहीं थामा होता तो शिवराज सिंह को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तो मिलने का संयोग भी नहीं बनता।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा- राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिखाया है।

सिंधिया ने मध्यप्रदेश में सार्वजनिक तौर पर भाजपा की तरफ से इस कदर तारीफ बटोरी है कि कांग्रेस में उनके साथी हाथ मल रहे होंगे। वैसे जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया को हाथों हाथ लेकर कांग्रेस के नाराज नेताओं को लगता है जैसे कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हों। मतलब, मध्यप्रदेश कांग्रेस के और भी नेता चाहें तो भाजपा में आने का संकेत समझकर कोशिश कर सकते हैं और दिल्ली में भी वे सभी जो कांग्रेस नेतृत्व के मौजूदा रवैए से घुटन महसूस कर रहे हों।

● **रजनीकांत पारे**

नाराज कांग्रेसियों को न्यौता दे रही भाजपा?

भाजपा भले ही चाल, चेहरा और चरित्र वाली पार्टी है, लेकिन पार्टी ने बाहरियों के लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं। मप्र में सिंधिया सहित 22 पूर्व विधायकों की भाजपा में एंट्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही नहीं इसके बाद भी भाजपा ने दूसरी पार्टियों के नाराज नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। कई वाकयों के पीछे संयोग भी होता है, लेकिन राजनीति में जब ऐसे संयोग नजर आते हैं तो आगे चलकर मालूम होता है कि वे महज संयोग नहीं बल्कि एक खास रणनीति का हिस्सा होते हैं। ये तो रोजाना देखने को मिल रहा है कि कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस नेता कभी कोरोना वायरस तो कभी अर्थव्यवस्था और अब चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से काउंटर अटैक तो वैसे भी स्वाभाविक है। कोई काउंटर अटैक भी तब ज्यादा असरदार होगा जब भाजपा सिंधिया जैसे किसी नेता को अपने पाले में मिला ले। सिंधिया जैसे नेता से मतलब कांग्रेस के राहुल ब्रिगेड से हो सकता है। जेपी नड्डा ने सिंधिया की तारीफ और अमित शाह ने कांग्रेस के संजय झा जैसे असंतुष्ट नेताओं के सामने एक तरीके से चारा ही फेंका है, ऐसा लगता है। असलियत तो आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगी, लेकिन अभी तो ऐसा ही लग रहा है जैसे भाजपा नाराज कांग्रेसियों को न्यौता दे रही हो!

रेड जोन में फंसी कांग्रेस

कमलनाथ व दिग्विजय सिंह में से कौन

इसमें कोई दो मत नहीं कि दिग्विजय सिंह डेढ़ दशक तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन उनकी महत्वकांक्षा राजनीति में सिंधिया राजघराने की तरह अपना वर्चस्व स्थापित करने की है। दूसरी तरफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में खुश थे। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने के बाद उनके मन में टीस है और वह भी प्रदेश के सर्वमान्य नेता बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसलिए दिग्विजय के साथ कमलनाथ की रूचि भी ग्वालियर-अंचल में बढ़ गई है। क्योंकि उन्हें राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी मात यहीं मिली है।

कोरोना संक्रमण के इस दौर में कांग्रेस अपने रेड जोन की पहचान कर रही है। ये वो इलाके हैं जहां कांग्रेस कमजोर है। लक्ष्य है रेड को ग्रीन में बदलने का और फोकस है ग्वालियर-चंबल पर। यही वो इलाका है जहां 16 सीटें महाराज और राजा के बीच नाक का सवाल बनेंगीं। कांग्रेस यहां बूथ स्तर तक जाकर ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करना चाहती है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब उन बूथ पर फोकस तेज कर दिया है जहां पार्टी कमजोर है। पार्टी इन इलाकों को रेड जोन मानकर चल रही है। उसने कमजोर बूथ को रेड पॉइंट बनाकर उसे ग्रीन में तब्दील करने की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री और विधायकों को दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ विधायकों के साथ मंथन भी कर चुके हैं।

कांग्रेस सबसे पहले ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों में कमजोर बूथ की पहचान कर रही है। विधानसभा वार नियुक्त पूर्व मंत्री और विधायकों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वह विधानसभा स्तर पर कमजोर बूथ की पहचान कर उन्हें मजबूत करें। साथ ही मंडल और सेक्टर स्तर पर संगठन की इकाइयां गठित करने की भी तैयारी है। ग्वालियर-चंबल इलाके में कांग्रेस का चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने के बाद पार्टी की मुश्किल वहां नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई है कि ग्वालियर-चंबल इलाके के कई इलाकों में कांग्रेस बूथ स्तर पर बेहद कमजोर हो गई है। कई जगह तो कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बचे ही नहीं हैं। सर्वे के बाद कमलनाथ ने अब उन पर फोकस करना तेज कर दिया है, जहां कांग्रेस को उपचुनाव में हार का अंदेशा है। इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वह खुद अपने स्तर पर बूथ में पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के सर्वे में कमजोर बूथ की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी चौकन्ना हो गई है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कमजोर बूथ को लेकर तैयार होने वाली रणनीति की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके लिए वह हर एक बूथ पर विधानसभा के प्रभारी विधायक और पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। कमजोर बूथ को मजबूत बनाने के लिए पार्टी नेताओं को 1 हफ्ते का समय दिया है। विधानसभा प्रभारी मौके पर पहुंचकर बूथ वार बैठक कर संगठन को मजबूत करेंगे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे।

24 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव केवल हार-जीत का ही चुनाव नहीं है। बल्कि इस चुनाव में कई नेताओं का वजूद दांव पर होगा। खासकर ग्वालियर-चंबल अंचल में यह समय कांग्रेस में नए नेतृत्व के उदय का भी है। इसके लिए करीब आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में बचे नेता यह मान रहे हैं कि उन्हें महल की गुलामी से मुक्ति मिल गई है। बदले हुए समीकरणों में अंचल के कांग्रेस नेताओं में गॉडफादर की महत्वकांक्षा जागने लगी है। जिसके कारण कांग्रेस में गुटबाजी का पौधा फिर से पनपने लगा है। सिंधिया के कारण सीमित दायरे में रहने वाले पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, अशोक सिंह, केपी सिंह, लाखन सिंह व विधायक प्रवीण पाठक की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। बालेंदु शुक्ला भी अपने गुजरे कल को लौटाने के लिए जोर लगाने लगे हैं। इन क्षत्रपों के बीच गॉडफदर बनने की जंग शुरू हो गई है।

तीन माह पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया गॉडफदर माने जाते थे। कांग्रेस में संगठन में नियुक्ति से लेकर टिकट वितरण तक में महल का फैसला अंतिम माना जाता था। जब तक दिल्ली से कोई सीधे फेरबदल नहीं हो। जिसके कारण गिनती के दिग्विजय सिंह समर्थकों को छोड़कर कांग्रेसी महल के सामने नतमस्तक नजर आते थे। सिंधिया के पार्टी छोड़ते ही यह नेता फ्री हैंड हो गए हैं।

क्षत्रपों के बीच मूल झगड़ा ग्वालियर को लेकर है। यहां अशोक सिंह अपना वर्चस्व बनाने में लगे हैं। ग्वालियर में डॉ. गोविंद सिंह भी अपना दखल रखना चाहते हैं। चूंकि दोनों दिग्विजय सिंह खेमे के हैं, इसलिए दोनों के बीच कैमेस्ट्री जम सकती है। लेकिन विधायक पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी यहां अपना दखल रखना चाहते हैं। इसलिए वह जिले की नियुक्तियों में रूचि दिखा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ की मौजूदगी में हुई मीटिंग में रामनिवास रावत को विधायक प्रवीण पाठक व अशोक शर्मा के खुले विरोध का सामना करना पड़ा। प्रवीण पाठक ने यहां तक कह दिया कि मैं आपके श्योपुर में दखल दूं तो कैसा लगेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपने क्षेत्र में किसी तीसरे की दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉ. गोविंद सिंह भिंड में रामनिवास रावत मुरैना-श्योपुर, केपी सिंह गुना-शिवपुरी देखें किसी को ऐतराज नहीं है। मुश्किल यह है कि ग्वालियर में स्वीकार्यता के बिना कोई गॉडफादर नहीं बन सकता है। इसलिए क्षत्रपों के बीच खुली जंग शुरू हो गई है।

● **अरविंद नारद**

मप्र विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरु होगा। इस सत्र के दौरान मप्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट में कोरोना का इफेक्ट दिखेगा। सरकार इस बार कई योजनाओं पर कैंची चला सकती है। वहीं संबल, सामाजिक पेंशन, कन्यादान सहित कई योजनाओं के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अधिकारी खाका तैयार करने में जुट गए हैं।

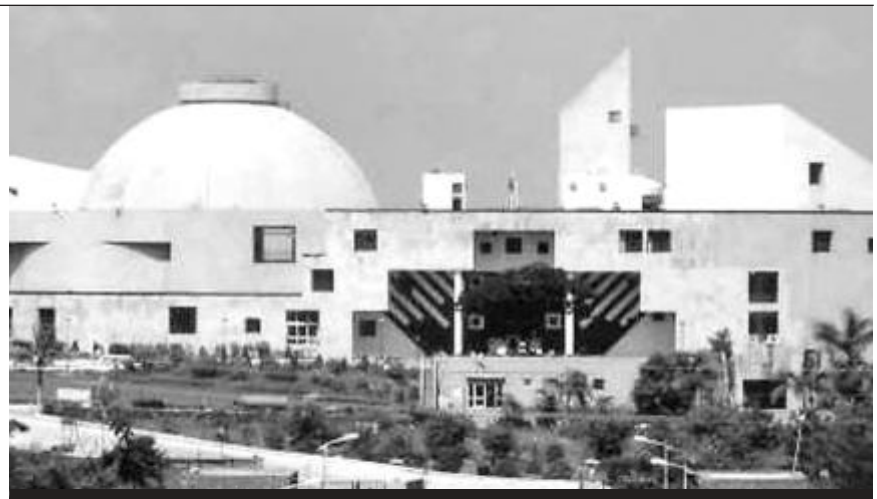

बजट पर कोरोना इफेक्ट

मानसून सत्र में मप्र सरकार बजट पेश करेगी। इस बार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पांच दिवसीय सत्र में महत्वपूर्ण विधि विषयक और वित्तीय कार्य संपादित होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की विशेष परिस्थितियों की वजह से सत्र संक्षिप्त अवधि का रखा गया है। मानसून सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद सदन की कार्यवाही औपचारिक रूप से शुरू होगी।

प्रदेश में शिवराज सरकार के पहले बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में शिवराज सरकार का पहला बजट पास किया जाएगा। सरकार सवा दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य विभाग ने मानसून सत्र बुलाने की फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी है। अब इसके बाद सत्र कब बुलाया जाएगा इसका अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री राज्यसभा चुनाव के बाद लेंगे। बताया जा रहा है कि इस बजट में प्रदेश के एसजीडीपी का 5 प्रतिशत तक कर्ज लेने का प्रस्ताव भी मंजूर कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के कारण विभागों को मिलने वाले बजट में कटौती तो होगी ही कुछ योजनाएं भी बंद की जाएंगी।

बता दें कि प्रदेश में सियासी उठापटक के चलते तत्कालीन कमलनाथ सरकार बजट पेश नहीं कर पाई थी। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल का गठन न होने के कारण 31 मार्च से पहले शिवराज सरकार भी बजट सत्र नहीं बुला पाई। वेतन-भत्ते सहित जरूरी खर्चों के लिए राज्यपाल लालजी टंडन की अनुमति से 28 मार्च को एक लाख 66 करोड़ 74 लाख 81 हजार रुपए का लेखानुदान अध्यादेश लाया गया। बता दें कि मध्यप्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक राशि का लेखानुदान है।

बजट भाषण में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे गए राशन, संबल योजना की वापसी, प्रवासी श्रमिकों के जॉबकार्ड बनाने के लिए चलाई गई श्रम सिद्धी योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए शुरू किए गए रोजगार सेतु पोर्टल, बिजली उपभोक्ताओं को दी गई रियायत, श्रम कानूनों में किए गए संशोधन, मंडी अधिनियम में किए गए बदलाव, निजी मंडी की व्यवस्था, रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइडलाइन और निर्माण दर में छूट देने जैसे फैसलों का प्रमुखता से जिक्र किया जाएगा।

20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। यह दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहेगा। सत्र की कम अवधि को देखते हुए बजट पर सामान्य और विभागों की अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी। बिना चर्चा ही विभागों का बजट पारित होगा। विपक्ष कटौती प्रस्ताव रखेगा तो भी इस पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। दरअसल, सत्र में बजट के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा अन्य संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनका पारित होना जरूरी है। मानसून सत्र के दौरान सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम वर्ष 2020-21 के लिए बजट पारित कराना होगा। कोरोना की वजह से बजट सत्र पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार को एक लाख 66 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेखानुदान अध्यादेश लाना पड़ा था। इसकी अवधि 31 जुलाई तक है। इसके पहले विनियोग और वित्त विधेयक सदन से पारित करवाकर राज्यपाल की अनुमति लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करनी होगी। वित्त विभाग इसी हिसाब से तैयारी कर रहा है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विभागों से वित्त मंत्री के भाषण में शामिल किए जाने वाले

संबल, कन्यादान, सामाजिक पेंशन के लिए पर्याप्त बजट

सूत्रों का कहना है कि शिवराज सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 'संबल' के लिए पर्याप्त बजट रखेगी। कमलनाथ सरकार ने योजना को हाशिए पर डाल दिया था। इसके कई प्रावधानों को समाप्त करने के साथ जांच के नाम पर हितग्राहियों को लाभांवित करना भी रोक दिया था। कांग्रेस सरकार में तीर्थदर्शन योजना का बजट भी नाममात्र हो गया था। काफी विरोध होने के बाद योजना के तहत कुछ ट्रेन तीर्थ स्थानों के लिए भेजी गई थीं। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष योजना में ज्यादा राशि नहीं रखी जाएगी पर स्थिति सामान्य होते ही प्राथमिकता के साथ बजट आवंटन होगा। कन्यादान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पंच परमेश्वर, छोटे कारोबारियों के लिए ब्याज अनुदान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ब्याज अनुदान, शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के लिए ब्याज अनुदान, फसल बीमा योजना के लिए अंशदान, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, बिजली बिलों में राहत के लिए अनुदान सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे।

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए जोर-आजमाइश

विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। इसमें कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसका असर सदन में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में दिखाई देगा। दरअसल, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से भाजपा विधायक का मत लेने में कामयाब होने के कारण कांग्रेस काफी उत्साहित है। लिहाजा, आंकड़ेबाजी में पीछे रहने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में विधायकों को उतार सकती है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के विधायकों डॉ. गोविंद सिंह, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं। सूत्र बताते हैं कि चुनाव में डॉ. गोविंद सिंह और केपी सिंह को कांग्रेस उतारने से बचेगी, क्योंकि इसमें हार सुनिश्चित है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के कार्ड के रूप में कांतिलाल भूरिया या सज्जन सिंह वर्मा को इसके लिए आगे किया जा सकता है। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष में तीन या इससे ज्यादा बार जीते विधायकों हुकुमसिंह कराड़ा, बाला बच्चन, सुखदेव पांसे जैसे नेता के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक सीतासरन शर्मा, विधायक केदारनाथ शुक्ल, विधायक जगदीश देवड़ा व गिरीश गौतम और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम पर विचार किया है। इन्हीं में दोनों पदों के लिए उम्मीदवार तय होंगे। कांग्रेस सरकार के समय हिना कांवरे के मुकाबले भाजपा ने उपाध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री विजय शाह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सूत्रों की मानें तो शाह अब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते।

बिंदु मंगाए जा चुके हैं। मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए नए प्रस्ताव भी सीमित संख्या में ही शामिल किए जाएंगे। उधर, विधानसभा सत्र की अवधि (20 से 24 जुलाई) को देखते हुए बजट पर तीन दिन की सामान्य चर्चा नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि कुछ घंटे में सामान्य चर्चा को पूरा करवाकर विभागों की अनुदान मांगों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इससे ज्यादातर मांगों पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी। सत्र के दौरान कृषि उपज मंडी अधिनियम, श्रम कानून, नगर पालिक और पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाएंगे। केंद्रीय सहायता पर निर्भर करेगा बजट का आकार बताया जा रहा है कि राज्य के करों में आई कमी की पूर्ति वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि में पूरी होने की संभावना नहीं है।

सत्र में बजट के अलावा आधा दर्जन से ज्यादा अन्य संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनका पारित होना जरूरी है। मानसून सत्र के दौरान सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम वर्ष 2020-21 के लिए बजट पारित कराना होगा। कोरोना की वजह से बजट सत्र पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार को एक लाख 66 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेखानुदान अध्यादेश लाना पड़ा था। इसकी अवधि 31 जुलाई तक है। इसके पहले विनियोग और वित्त विधेयक सदन से पारित करवाकर राज्यपाल की अनुमति लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करनी होगी। वित्त विभाग इसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विभागों से वित्त मंत्री के भाषण में शामिल किए जाने वाले बिंदु मंगाए जा चुके हैं। मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए नए प्रस्ताव भी सीमित संख्या में ही शामिल किए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि कुछ घंटे में सामान्य चर्चा को पूरा करवाकर विभागों की अनुदान मांगों को एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इससे ज्यादातर मांगों पर चर्चा ही नहीं हो पाएगी। सत्र के दौरान कृषि उपज मंडी अधिनियम, श्रम कानून, नगर पालिक और पंचायतराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाएंगे। केंद्रीय सहायता पर निर्भर करेगा बजट का आकार बताया जा रहा है कि राज्य के करों में आई कमी की पूर्ति वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि में पूरी होने की संभावना नहीं है।

सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के कारण करीब 26 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान सरकार को हो चुका है। पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर लगाकर कुछ नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई है, लेकिन इससे भी सालभर में करीब 570 करोड़ रुपए की आय ही होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बजट का आकार केंद्रीय सहायता पर निर्भर करेगा। राज्यों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में सहायता की राशि बढ़ाई है। नई योजनाएं भी शुरू हुई हैं। राज्य सरकार की कोशिश भी है कि अधिक से अधिक केंद्रीय योजनाओं का उपयोग कर राज्य के बजट पर भार कम किया जाए। 45 हजार करोड़ रुपए तक कर्ज लेने की सीमा से मिली राहत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बने हालात को देखते हुए केंद्र सरकार प्रदेश को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) का दो प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने की छूट दी है। इससे सालभर में 18 हजार 983 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे। इसमें चार हजार 746 करोड़ रुपए का कर्ज बिना शर्त लिया जा सकेगा। वहीं, 14 हजार 237 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। कर्ज लेने की अतिरिक्त छूट मिलने से प्रदेश सरकार अब सालभर में लगभग 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगी।

वर्ष 2020-21 का बजट 31 जुलाई के पहले विधानसभा से पारित कराया जाएगा। लेखानुदान अध्यादेश जुलाई तक के लिए ही है। इसके बाद सरकार को जरूरी खर्च के लिए विधानसभा की अनुमति की जरूरत होगी। उधर, वित्त विभाग ने बजट प्रस्तावों को तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हालांकि इसमें राज्य नीति एवं योजना आयोग की कोई भूमिका नहीं होगी। कमलनाथ सरकार ने आयोग को मजबूत बनाने के लिए कई शक्तियां दी थीं। इसमें बजट प्रक्रिया में सुझाव देना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग ने बजट तैयार करने का जो कार्यक्रम तय किया है, उसमें राज्य नीति एवं योजना आयोग की कोई भूमिका नहीं रखी गई है।

● **सुनील सिंह**

मप्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार की कई योजनाओं को बंद करने की कवायद भाजपा सरकार ने शुरू कर दी है। दरअसल, प्रदेश सरकार का मानना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थीं उनसे जनता को कोई अधिक लाभ नहीं पहुंचने वाला है। इसलिए कई योजनाएं बंद करने की कवायद चल रही है।

अधर में ग्राम युवा शक्ति समिति

पंचायतों में अब ग्राम युवा शक्ति समिति नहीं बनेंगी। कांग्रेस सरकार ने प्रत्येक पंचायत में 11 सदस्यीय समिति बनाने का फैसला किया था। इसे गांव में नशामुक्ति को बढ़ावा देने से लेकर विभिन्न योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाने का जिम्मा सौंपा जाना था। लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार की इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

कमलनाथ सरकार ने गांव-गांव में युवाओं को जोड़ने के लिए ग्राम युवा शक्ति समिति बनाने का फैसला किया था। इसके पीछे मंशा यह थी कि दो लाख 67 हजार 142 स्थानीय युवाओं का ऐसा तंत्र बनाया जाए, जो सरकार के आंख और कान हों। यही वजह थी कि प्रभारी मंत्रियों को यह जिम्मा सौंपा गया था कि वे स्थानीय विधायकों से समन्वय बनाकर समिति का गठन कराएं, लेकिन यह काम पूरा ही नहीं हो सका। कुछ जगहों पर समितियां बनीं भी पर वे क्रियाशील नहीं हो पाईं। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना में ग्राम युवा शक्ति समिति के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल तय किया गया था। सदस्यों को प्रति बैठक 300 रुपए मानदेय के हिसाब से चार बैठकों के लिए सालाना 1200 रुपए मानदेय मिलता। बेहतर काम करने वाली समिति को दो लाख रुपए का पुरस्कार देने की व्यवस्था भी रखी गई थी। वहीं कमलनाथ सरकार ने जिन 22 नगर परिषदों को फिर से पंचायत बनाने का फैसला किया था, उसे शिवराज सरकार पलटेगी। इसके लिए सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग फिर से नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना एक-दो दिन में जारी करेगा। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अधिसूचना निरस्त होने के बाद पंचायतों के परिसीमन का जो कार्यक्रम जारी किया था, उसे स्थगित कर दिया है।

शिवराज सरकार ने पिछले कार्यकाल में चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 30 नई नगर परिषद के गठन का निर्णय लिया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए 22 नगर परिषदों को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया था। 8 परिषदों के गठन को निरस्त करने पर कांग्रेस विधायक सहमत नहीं थे, इसलिए इन्हें छोड़ दिया था।

समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों का कहना हैं कि ज्यादातर जिलों में समितियों के गठन की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई थी। प्रभारी मंत्री के माध्यम से समिति में मनोनयन के लिए नाम आने थे पर वे नहीं आए। सत्ता परिवर्तन के बाद इस योजना को लेकर अभी तक सरकार के स्तर पर कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि अब योजना आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि, इसके औपचारिक आदेश होने अभी बाकी हैं। उधर, पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि सरकार ने योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कहीं भी समिति के गठन का काम नहीं हो रहा है, जबकि समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य था। इसमें स्थानीय अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को सदस्य बनाया जाना था।

सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब पिछले सरकार के नीतिगत फैसलों की फाइलें बुलाई गईं तो उसमें नगर परिषदों के गठन को निरस्त करने की फाइल भी थी। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के निर्णय को निरस्त करते हुए नगर परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग एक-दो दिन में अधिसूचना जारी करेगा।

उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नगर परिषद क्षेत्र में शामिल की गई पंचायतों को फिर से पंचायत क्षेत्रों में लेने के लिए परिसीमन की जो प्रक्रिया शुरू की थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। संचालक पंचायतराज बीएस जामोद ने हरदा, बैतूल, मंदसौर, शिवपुरी, भिंड, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सागर, सिवनी, खरगोन, बड़वानी और धार कलेक्टरों को पत्र लिखकर परिसीमन की कार्रवाई को स्थगित रखने का निर्देश दिए हैं।

कमलनाथ सरकार ने जिन नगर परिषदों का गठन निरस्त किया था उनमें हरदा की सिराली, बैतूल की घोड़ाडोंगरी व शाहपुर, मंदसौर की भैंसोदा मंडी, शिवपुरी की रन्नौद, भिंड की रौन व मालनपुर, रीवा की डभौरा, शहडोल की बकहो, अनूपपुर की डोलर व डूमरकछार, उमरिया की मानपुर, सागर की बिलहरा, सुरखी, मालथौन, बांदरी, सिवनी की छपारा, खरगोन की बिस्टान, बड़वानी की ठीकरी और धार की बाग व गंधवानी।

● **विकास दुबे**

जनता चुनेगी महापौर

अधिनियम में संशोधन की मंजूरी

सत्ता परिवर्तन के बाद शिवराज सरकार ने पिछली सरकार के जिन फैसलों की समीक्षा कर परिवर्तन करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया था, उसे अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग अमलीजामा पहना रहा है। इसके लिए पिछले दिनों मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दी गई है। इसके मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने संशोधित विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया है।

प्रदेश में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष अब सीधे मतदाता चुनेंगे। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के फैसले का पलटने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है। इसके साथ ही चुनाव से 6 माह पहले तक ही वार्डों का परिसीमन हो सकेगा। गत दिनों मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में जुलाई में संशोधन विधेयक लाने की अनुमति नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस शासनकाल में नगरीय निकाय चुनाव व्यवस्था में जो बदलाव किया था, उसे फिर पुराने स्वरूप में लाने का निर्णय किया है। कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में जनवरी 2020 में संशोधन कर महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के माध्यम से कराने की व्यवस्था लागू की थी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन के साथ मध्यप्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन नियम में भी बदलाव किया गया।

साथ ही चुनाव से दो माह पहले तक वार्ड परिसीमन करने और कलेक्टर को चुनाव के बाद पहला सम्मेलन बुलाने का अधिकार दिया था। भाजपा ने कमलनाथ सरकार के इस फैसले का हर स्तर पर विरोध किया था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश के जरिए व्यवस्था में बदलाव किया और फिर विधानसभा में नगर पालिका अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित कराकर 27 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ सचिव समिति ने पुरानी व्यवस्था फिर लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन के लिए विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दे दी है। अब विभाग संशोधन विधेयक का प्रस्ताव कैबिनेट में रखेगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत चुनाव से 6 माह पहले निकाय व वार्ड की सीमा का परिसीमन रुक जाएगा। इसके बाद न तो नए निकाय का गठन होगा और न ही वार्ड की संख्या बढ़ेगी। कमलनाथ सरकार ने इस अवधि को घटाकर दो माह कर दिया था।

वहीं, चुनाव के बाद पहला सम्मेलन राज्य निर्वाचन आयोग ही बुलाएगा। इससे ही निकाय के पांच वर्षीय कार्यालय की गणना होगी। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराने के अध्यादेश को मंजूरी काफी ऊहापोह के बाद मिली थी। राज्यपाल लालजी टंडन ने पार्षदों द्वारा शपथ-पत्र में गलत जानकारी देने पर जुर्माना और सजा संबंधी अध्यादेश को तो मंजूरी दे दी थी, लेकिन चुनाव प्रणाली में बदलाव का अध्यादेश रोक लिया था। भाजपा इस अध्यादेश को मंजूरी न दिए जाने के लिए लगातार ज्ञापन दे रही थी। मामला लंबा खिंचता देख तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने इस अध्यादेश को अनुमति दी थी। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव होने से अब फिर दो बैलेट यूनिट मतदान केंद्रों में लगेगी। एक बैलेट यूनिट में पार्षद और दूसरे में महापौर के लिए मतदान होगा। कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगी। वहीं जनता को एक बार फिर नगर निगमों के महापौरों और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्षों को वापस बुलाने का अधिकार मिलेगा। तीन चौथाई पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने और उसे विधिसम्मत पाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव कराएगा। इसमें खाली कुर्सी के पक्ष में अधिक मतदान होता है तो फिर महापौर या अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।

पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था। शिवराज सरकार ने फिर से इसमें संशोधन कर व्यवस्था को लागू करने की मंजूरी दे दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के नगर निगम के महापौर और नगर पालिका तथा नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराने की व्यवस्था लागू की थी। इसके साथ ही जनता को मिला वह अधिकार भी छिन गया था, जिसमें उसे महापौर और अध्यक्ष को वापस बुलाने का अधिकार मिला था। हालांकि इससे पहले दिग्विजय सरकार ने नगर निगम अधिनियम-1956 में बदलाव कर राइट-टू-रिकॉल के माध्यम से पार्षदों को यह अधिकार दिया था कि वे आर्थिक अनियमितता सहित अन्य आरोपों के चलते महापौर या अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास ला सकते हैं। कमलनाथ सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी थी कि पार्षदों को महापौर या अध्यक्ष के प्रति अविश्वास हो तो वे अपने में से ही किसी दूसरे व्यक्ति को चुन सकते हैं। विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने कमलनाथ सरकार की इस व्यवस्था का विरोध किया था। कलेक्टर यदि तीन चौथाई पार्षदों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव को परीक्षण में विधिसम्मत पाता है तो शासन को महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। शासन के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव कराता है। यदि खाली कुर्सी के पक्ष में जनता मतदान करती है तो संबंधित को पद छोड़ना पड़ता है। महापौर या अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उनके कार्यरत रहने के दो साल बाद और 6 माह शेष रहने से पहले लाया जा सकता है।

● **लोकेश शर्मा**

मप्र सरकार ने अपनी रणनीतिक जमावट और सक्रियता के कारण कोरोनावायरस को नियंत्रित कर रखा है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेशभर में किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रही है। राजधानी भोपाल में 27 और 28 जून को अभियान के तहत 5 लाख से अधिक लोगों की स्कैनिंग हुई है।

'किल कोरोना' अभियान

मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है। इसे किल कोरोना अभियान नाम दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार की कोशिश प्रदेश के 10 लाख घरों तक पहुंचने की होगी। 10 लाख घरों में सर्वे के लिए 10 हजार टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम कम से कम 100 घरों का सर्वे करेगी। राजधानी में इस अभियान के तहत 27 और 28 जून को सर्वे किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के मुताबिक इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन और स्वेच्छा के तौर पर काम करने वाले लोगों की मदद ली जाएगी। अभियान के तहत पूरे राज्य में सर्वे होगा। घर-घर जाकर सार्थक ऐप पर जानकारी अपलोड की जाएगी। लक्षण के आधार पर संदिग्ध रोगी देखे जाएंगे। साथ ही सर्दी-खांसी, जुकाम के अलावा डेंगू, मलेरिया और डायरिया की भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस अभियान को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से स्थानीय स्तर पर कोविड मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। ये कोविड मित्र स्वतंत्र रूप से सर्वे का काम करेंगे। इनसे 6 महीने तक काम लिया जाएगा, बदले में इन्हें हर महीने 1500 रुपए मेहनताना मिलेगा। इसके साथ ही सरकार इस अभियान को पूरा करने के लिए वालंटियर्स की भी मदद लेगी, जो सर्वे का काम करेंगे और सार्थक ऐप में जानकारी अपलोड करेंगे।

कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने 23 मार्च, मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण से लेकर 22 जून तक कुल 210 घंटे बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की निरंतर समीक्षा की है। प्रदेश में करीब 3 लाख लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत जांच, उपचार, क्वारेंटाइन, सर्वेलांस, संक्रमित क्षेत्र के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षित लोगों में चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। कोविड से संबंधित कार्यों की इस ट्रेनिंग में आशा वर्कर्स और वालंटियर्स भी शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर नियंत्रित किया गया है। इस समय 9 हजार की क्षमता हो गई है। प्रतिदिन बढ़ती जांच क्षमता के कारण पॉजीटिव रोगियों के सामने आने और उन्हें उपचार के बाद स्वस्थ करने के कार्य में आसानी हुई है। इसलिए मध्यप्रदेश रिकवरी रेट में काफी आगे है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने जानकारी दी कि प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों के नए उपकरणों के स्थापित होने से शीघ्र ही 16 हजार से अधिक टेस्टिंग की सुविधा विकसित हो जाएगी।

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश की ग्रोथ रेट 1.43 है। यह सभी राज्यों से बेहतर है। वैसे तो प्रदेश में गत 5 सप्ताह से वायरस के नियंत्रण में तेजी आई है, लेकिन निरंतर प्रत्येक स्तर पर किए गए प्रयासों से प्रदेश की स्थिति बेहतर बन सकी है। देश की आबादी में कभी मध्यप्रदेश के 6 प्रतिशत रोगी होते थे जो आज मात्र 1.3 प्रतिशत ही हैं। इंदौर नगर से देश के कुल कोविड रोगियों में 6.3 प्रतिशत शामिल थे, जो अब मात्र 1 प्रतिशत हैं। भोपाल और उज्जैन नगरों में भी नियंत्रण के प्रयास काफी सफल हुए हैं। एक्टिव प्रकरणों में जहां भारत का प्रतिशत 40 है वहीं मध्यप्रदेश में सिर्फ 19 प्रतिशत एक्टिव प्रकरण ही शेष हैं। इसका अर्थ है वायरस की तीव्रता भी कम हो रही है और मध्यप्रदेश संक्रमण का प्रकोप रोकने में अधिक सफल है। प्रदेश के 33 जिलों में 10 से कम एक्टिव केस हैं। कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मिशन की प्रबंध संचालक छवि भारद्वाज ने प्रजेंटेशन में बताया कि सार्थक ऐप की उपयोगिता बढ़ रही है। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सर्वे में यह ऐप महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कोविड मित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समुदाय आधारित प्रयासों से सर्विलेंस आसान होगा। जिला प्रशासन ऐसे स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मित्र का दायित्व दे सकता है, जो 45 वर्ष की आयु से कम हों। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठन भी जुड़ेंगे।

● **नवीन रघुवंशी**

प्रदेश में किए गए प्रबंध आवश्यकता से अधिक

कोरोना पॉजीटिव रोगियों को कोविड केयर सेंटर में दाखिल करने के लिए प्रदेश में जो उपलब्ध बिस्तर क्षमता है उसका 20 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में कुल 24 हजार 235 जनरल बेड, 8 हजार 924 ऑक्सीजन बेड और एक हजार 105 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। शासकीय और निजी अस्पतालों में प्रदेश में वायरस के प्रसार की आशंका के कारण यह क्षमता विकसित की गई। इसका एक चौथाई से कम ही उपयोग में आ रहा है। प्रदेश के जिला अस्पतालों में जुलाई माह के अंत तक कुल 956 आईसीयू बेड उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज में इनकी संख्या 777 हो जाएगी। जिला और मेडिकल कॉलेज में मिलाकर अगले माह के अंत तक करीब 12 हजार ऑक्सीजन बेड उपलब्ध होंगे। प्रदेश में तीन माह में मिले करीब 12 हजार पॉजीटिव प्रकरणों में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी पूर्ण हो गया है। यह इंदौर और ग्वालियर में 99 और 98 प्रतिशत तथा भोपाल, उज्जैन और बुरहानपुर में 100 प्रतिशत है। प्रदेश में 22 जून की स्थिति में 912 फीवर क्लीनिक कार्य कर रही हैं। इन क्लीनिक्स में आए रोगियों में से 77 प्रतिशत रोगियों को घर में आइसोलेट रहने का परामर्श दिया गया। प्रदेश में औसतन प्रति क्लीनिक 3019 रोगी पहुंचे हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल के नागरिक जागरूक हैं, जो प्रति क्लीनिक औसतन 304 की संख्या में जाकर परामर्श प्राप्त कर चुके हैं।

लोकल से वोकल

सीमा पर चीन की कायराना हरकत से पूरे देश में रोष है। इस रोष में वे व्यवसायी भी शामिल हैं जिनका धंधा पानी चीन के माल पर चलता है। ऐसे ही व्यवसायियों में मप्र के बुरहानपुर के बुनकर और व्यापारी शामिल हैं। कोरोना महामारी, ढाई माह के लॉकडाउन और पड़ोसी चीन की सीमा पर हरकतों से नाराज बुरहानपुर के बुनकरों और व्यापारियों ने चीनी माल से तौबा करने का मन बना लिया है। उद्योगपति और बुनकरों ने सूत खरीदना तो पहले ही बंद कर दिया है, अब चीनी पावरलूम और मशीनरी भी नहीं खरीदेंगे, भारत में निर्मित पावरलूम पर ही कपड़ा तैयार करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा बन भारत में बने देसी पावरलूम पर कपड़ा बनाकर बेचेंगे। चीनी पावरलूम की खरीदी का नया ऑर्डर भविष्य में नहीं दिया जाएगा।

बुरहानपुर में वर्षों पुराने पावरलूम संचालित हो रहे हैं। इनमें हाथों से संचालित देसी पावरलूम और बिजली से चलने वाले आधुनिक पावरलूम भी शामिल हैं। करीब 70 हजार बुनकर और मजदूर पावरलूम पर काम करते हैं। करीब दो लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़े हैं। ऐतिहासिक शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही पावरलूम व्यवसाय है। लॉकडाउन के कारण ठप रहे इस व्यवसाय ने हाल ही में धीमी रफ्तार से फिर चलना शुरू किया है। लेकिन यहां के लोगों ने संकल्प लिया है कि चीनी पावरलूम पर कपड़ा नहीं बनाने के साथ वहां के किसी कलपुर्जे का भी उपयोग उद्योग में नहीं किया जाएगा। चीन से कच्चा माल (कई तरह का सूत) मंगाना तो करीब एक महीने पहले ही बंद कर दिया गया था। अब सूरत, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से सूत और मशीनरी मंगवाई जाएंगी।

देश का पैसा देश में रहने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। बुरहानपुर टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया मित्तल और सचिव गोपाल दरगड़ ने बताया कि चीन की वजह से फैली महामारी, लॉकडाउन और हाल ही में भारतीय सैनिकों पर हमले से उद्योग से जुड़े सभी लोग नाराज हैं। सभी ने निर्णय लिया है कि भविष्य में चीनी मशीनरी का नया ऑर्डर नहीं देंगे। पैंडिंग ऑर्डर भी निरस्त कर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़कर देसी पावरलूम पर ही काम करेंगे। मेड इन इंडिया कपड़ा भारतीय इंडियन पावरलूम पर ही बनाएंगे। यहां के व्यवसायियों का कहना है कि अब स्वदेशी पावरलूम और मशीनरी खरीदेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान या लोकल को वोकल बनाने के मिशन में भागीदार बनेंगे।

गौरतलब है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावरलूम सेंटर है। यहां का सूती कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। यहां 50 हजार पावरलूम हैं जिस पर बुनकर रोजाना 40 लाख मीटर कपड़ा तैयार किया जाता है। यह कपड़ा पूरे देश के कोने-कोने के साथ-साथ विदेशों में भी निर्यात होता है। इन पावरलूम पर करीब 70 हजार बुनकर और मजदूर अपना रोजगार हासिल करते हैं। वहीं करीब 2 लाख की आबादी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से इसी पावरलूम उद्योग से जुड़ी है। यानी यह कह सकते हैं कि पावरलूम उद्योग बुरहानपुर की रीढ़ की हड्डी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण इस उद्योग की कमर ही टूट गई। कोरोना लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1.0 में धीमी गति से ही सही लेकिन पावरलूम उद्योग रफ्तार पकड़ रहा है। इस बीच पड़ोसी देश चीन की सीमा पर की गई हरकत से बुरहानपुर के टैक्सटाइल व्यवसायी और बुनकर खासे नाराज हैं। वैसे तो यहां बड़ी संख्या में पारंपरिक पावरलूम हैं लेकिन बदलते वक्त के साथ अब धीरे-धीरे आधुनिक पावरलूम भी आ गए हैं।

ये चीन से आयात होते हैं। काम आसान होने के कारण इनकी डिमांड भी तेजी से बढ़ी। लेकिन अब पहले कोरोना और फिर सरहद पर चीन की हरकतों से नाराज टेक्सटाइल कारोबारियों और बुनकरों ने चीन के बहिष्कार का फैसला कर लिया है। इन लोगों ने चीनी पावरलूम और मशीनरी को ना कहने का फैसला किया है। इसके स्थान पर ये देश में ही बने आधुनिक पावरलूम लगाएंगे। स्व. राजीव दीक्षित के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े राजेश बजाज ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा- राजीव दीक्षित ने छोटे से उत्पाद से लेकर बड़े उत्पादों के लिए यह अभियान चलाया था जो आज सार्थक हो रहा है। उन्होंने कहा देश में बनने वाले पावरलूम और कपड़े काफी महंगे होते थे इसलिए टेक्सटाइल उद्योगपति चीन से पावरलूम और कपड़ा आयात करते हैं। लेकिन अब आयात बंद होगा तो देश में आधुनिक पावरलूम और कपड़े की मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है लागत भी घटेगी और उनका दाम भी कम होगा। इससे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सफलता मिलेगी।

● **प्रवीण कुमार**

देसी पावरलूम पर ही काम करेंगे

आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़कर देसी पावरलूम पर ही काम करेंगे। मेड इन इंडिया कपड़ा भारतीय इंडियन पावरलूम पर ही बनाएंगे। देसी उत्पाद को बढ़ावा बुरहानपुर टेक्सटाइल्स व प्रोसेस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश बजाज का कहना है कि देशहित में देश में बनने वाली मशीनरी और सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा तैयार कर इसकी ब्रांडिंग के साथ व्यापार करेंगे और देसी उत्पाद को बढ़ावा देंगे। बुरहानपुर पावरलूम बुनकर संघ के अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी के अनुसार शहर के बुनकर अब भारत में बने पावरलूम पर ही कपड़ा तैयार करेंगे। देशी मशीनरी और सामान को बढ़ावा देंगे। बुरहानपुर शहर में वर्षों पुराने देसी पावरलूम पर भी हाथ से कपड़ा आज भी बनाया जाता है। शहर में कई घरों में भी छोटे पावरलूम कारखाने संचालित हैं, जिनमें भारतीय पावरलूम पर कपड़ा बनता है।

मनरेगा ने दी संजीवनी

कोरोना संकट के समय में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में मप्र पांचवें स्थान पर है। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मनरेगा के साथ ही अन्य योजनाओं का सहारा लिया है। लेकिन सबसे अधिक मनरेगा में रोजगार दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है। देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 18 फीसदी रही जो कि किसी भी राज्य से ज्यादा है। वहीं राजस्थान दूसरे स्थान पर है।

एक तरफ मनरेगा जहां प्रवासी श्रमिकों का सहारा बनकर उनकी जीविकोपार्जन का साधन बनी है, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। मनरेगा के तहत गांवों के दिहाड़ी मजूदरों को इस महीने जून में पिछले साल के मुकाबले 84 फीसदी ज्यादा काम मिला है। महामारी के मौजूदा संकटकाल में यह योजना न सिर्फ रोजगार देने वाली बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संचालक भी बनने वाली है। मनरेगा के तहत पूरे देश में इस महीने औसतन 3.42 करोड़ लोगों को रोजाना काम करने की पेशकश की गई है जो कि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 83.87 फीसदी अधिक है। मप्र में वर्तमान में 25 लाख से अधिक श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला हुआ है।

मप्र में मनरेगा के अंतर्गत लगभग दो लाख कार्यों में 25 लाख 16 हजार 24 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष से यह संख्या लगभग दोगुनी है। गत वर्ष 14 जून को 12 लाख 51 हजार 680 श्रमिक मनरेगा में कार्यरत थे। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान में 8 लाख 38 हजार 243 श्रमिकों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। गत वर्ष इसी अवधि में बनाए गए नवीन जॉबकार्डों की संख्या मात्र 1 लाख 84 हजार थी। कोरोना संकट के समय में मनरेगा में रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे निकल गया है। राज्य में 15 जून तक 57 लाख 12 हजार मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। देश में मनरेगा के तहत कुल रोजगार में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 18 फीसदी रही जोकि किसी भी राज्य से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान रहा जहां 53.45 लाख मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। राजस्थान ने मनरेगा रोजगार में कुल 17 फीसदी की भागीदारी अब तक दी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर 12 फीसदी भागीदारी के साथ 36.58 लाख मजदूरों को रोजगार देने में आंध्रप्रदेश रहा। इसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश चौथे और पांचवें स्थान में हैं, दोनों ही राज्यों ने क्रमशः 26.72 और 25.16 लाख मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया।

रोजगार सेतु का उपयोग

मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। स्किल मेपिंग के लिए रोजगार सेतु का उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों में कार्य करने वाले श्रमिक सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक 44 हजार 988 श्रमिक इससे जोड़े गए हैं। आत्मनिर्भर भारत में एक लाख 24 हजार 552 प्रवासी मजदूरों को खाद्यान दिया गया। विभिन्न बिल्डर्स, कॉन्ट्रेक्टर्स और कारखाना प्रबंधन से जानकारी एकत्र कर श्रमिकों के रोजगार के लिए श्रेणी वार संभावनाओं को देखा जा रहा है। संबल पोर्टल पर भी 3 लाख 24 हजार 715 लोग पंजीबद्ध हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में इन प्रयासों का विशेष महत्व है। विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा कार्यों से जोड़कर आर्थिक सहारा दिया गया है।

मौजूदा महामारी के दौर में जब मजदूरों और श्रमिकों के हालात समाज और सरकार के सामने जाहिर हैं, तब यह सवाल सहज ही हमारे सामने आता है कि आखिर किन परिस्थितियों ने उन्हें इन हालातों तक पहुंचाया है? गांवों से उखड़ते हुए ये लोग आखिर कौन हैं? क्यों तमाम अनिश्चितताओं के बीच भी कमाने-खाने के लिए ये सब हजारों मील दूर पलायन करते हैं? क्या इनके पास स्थानीय स्तर पर आजीविका के कोई अन्य संसाधन नहीं हैं? इन असहज सवालों का कोई सहज जवाब सरकार और समाज दोनों के पास नहीं है। एक बेहतर कल की तलाश में श्रमिकों को पलायन के लिए प्रेरित या मजबूर करती परिस्थितियां और उसके लगभग अप्रत्याशित परिणाम वास्तव में यह सिखाता और दिखाता है कि उन लाखों श्रमिकों के अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए अभी भी बहुत कुछ बदला जाना शेष है। यह कानून और नीतियां मात्र नहीं, बल्कि उस पूरे दृष्टिकोण को बदलने से शुरू होना होगा जिसके पीछे समाज, सरकार और हम सब खड़े हैं।

बहरहाल, योजनाओं के मानसून में आज 'श्रमिक, ग्रामीण समाज और उनके विकास' के सवालों का केंद्र में होना एक प्रासंगिक पहल तभी साबित होगा, जब इसे ग्रामीण समाज के अपने जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के इतिहास, और पलायन के वर्तमान के वास्तविकताओं की समग्रता में देखा जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो इसे एक बार फिर ग्रामीण भारत को विकास की प्रयोगशाला में बदलने का प्रयास मान लिया जाएगा। ग्रामीण भारत के विकास का आधा-अधूरा दृष्टिकोण अब तक सुलझे-उलझे आसान प्रयोगों की प्रयोगशाला ही साबित होती रही है। अन्यथा आजादी के सात दशकों में बेहिसाब योजनाओं, नीतियों और प्रयोगों के परिणाम आज इतने अनिश्चित, अप्रासंगिक और अर्थहीन नहीं होते। पलायन की अनिश्चित परिस्थितियां और निश्चित त्रासदी इन अपूर्ण प्रयोगों का ही लगभग पूर्ण उदाहरण है। नई नवेली 'गरीब कल्याण योजना' के राजनैतिक दर्शन को व्यवहार में बदलने के लिए आखिर जिन रास्तों का प्रयोग किया जाएगा। वास्तव में, वही उसके प्रभाव अथवा अभाव का पैमाना बनेगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

भाजपा और 'मजबूत' हुई

राजग ने राज्यसभा में 100 सीटों को पार कर लिया और अपने 40वें वर्ष में भाजपा भारत के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में और मजबूत हो गई। राज्यसभा में उसकी सदस्य संख्या 86 पहुंच गई है। अपने गठन से लेकर अब तक भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। भाजपा का गठन अप्रैल 1980 में किया गया था, जब उसके सदस्यों को जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, उस संयुक्त विपक्षी दल से, जिसका निर्माण 3 साल पहले इंदिरा गांधी का मुकाबला करने के लिए किया गया था। जनता पार्टी के घटकों में से एक भारतीय जनसंघ भी था, जिसे 1951 में बनाया गया था। भारत के शुरूआती चुनावों में जनसंघ को केवल कुछ ही सीटें मिलीं और यह स्थिति 1970 के दशक तक बनी रही जब वाजपेयी के नेतृत्व में बाकी विपक्ष के साथ इसका जनता पार्टी में विलय हो गया।

जब 1980 में संघ के सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया और उन्हें एक नई पार्टी बनानी पड़ी, तो वाजपेयी ने दोबारा इसका नाम भारतीय जनसंघ रखने के आव्हान को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बड़े समूह का हिस्सा बनकर मिले अनुभव से उन्हें काफी सीख मिली है। इससे आए दो बदलावों में से पहला था, भारतीय जनता पार्टी (जैसा कि इसका नाम वाजपेयी ने रखा था) ने अपने कैडर का विस्तार किया और पार्टी में गैर-आरएसएस व्यक्तियों को लिया। दूसरा, भाजपा का संविधान जनसंघ से अलग हो गया और यह भारत की धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति निष्ठा का वादा करता है। भाजपा के संविधान और शपथ दोनों में अभी भी यह अनूठी विशेषता है कि यह अपने सभी सदस्यों को हस्ताक्षरित करने को कहता है।

इस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और 1984 के उन चुनावों में उसे केवल 2 सीटें मिलीं जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विपक्ष को ध्वस्त कर दिया। पार्टी की किस्मत में बदलाव तब आया जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा बाबरी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगते हुए आंदोलन शुरू किया गया, जहां दिसंबर 1949 में राम और सीता की दो मूर्तियां रखी गई थीं। नए अध्यक्ष आडवाणी के तहत धर्मनिरपेक्षता की शपथ को नजरअंदाज किया गया और पार्टी ने विहिप की मांग को अपनाया, हालांकि अयोध्या योजना न तो मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखे जाने के कुछ महीने बाद ही बनाई गई जनसंघ के घोषणापत्र पर थी और न ही उस समय तक भाजपा के।

अयोध्या योजना को आगे बढ़ाने के अपने निर्णय से आडवाणी ने भारतीय समाज में जो ध्रुवीकरण पैदा किया, उसने आखिरकार आरएसएस को वह सफलता दिलाई जिसकी उन्हें तलाश थी और भाजपा ने 1989 में 85 सीटें जीत लीं। वह जनता दल नामक एक अन्य गठबंधन का हिस्सा बनी लेकिन इस बार बाहर से ही इसका समर्थन किया।

जब सरकार गिरी तो आडवाणी बाबरी मुद्दे पर लौट आए और आखिरकार दिसंबर 1992 में उस भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने इसे ध्वस्त किया और इसके बाद हुए दंगों में 2000 भारतीय मारे गए। विध्वंस और हिंसा के बाद पार्टी ने अपनी लोकप्रियता में और वृद्धि की और वापस प्रभारी बन चुके वाजपेयी के नेतृत्व में 1998 के चुनाव में इसने अपनी संख्या दोगुनी करते हुए 182 कर ली। 1999 में हुए अगले चुनावों में 180 सीटें जीतकर इसने अपनी यही स्थिति कायम रखी और फिर 2004 में 138 पर फिसल गई।

सत्ता में रहते हुए भाजपा अपने अयोध्या और मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण से दूर चली गई। बदलाव 2002 के गुजरात दंगों में आया जिसके बाद वाजपेयी ने मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की असफल कोशिश की। वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा धीरे-धीरे मजबूत होती गई और केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्तारूढ़ भी हुई। उसके बाद 2014 में ऐसा मोड़ आया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई और उसके बाद से देशभर में भाजपा की लहर इस कदर छाई कि भारत का पूरा नक्शा भगवा नजर आने लगा। हालांकि इस दौरान कई राज्यों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर भाजपा ने अपनी मजबूती और मजबूत कर ली है।

● **राजेश बोरकर**

86 पर पहुंची भाजपा

भाजपा ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद अब राज्यसभा में भी बड़ी बढ़त हासिल की है। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा के पास इस सदन में 86 सीटें हैं। यह कांग्रेस की 41 सीटों के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा हैं। इतना ही नहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अब 245 सीटों वाले इस सदन में करीब 100 सीटें हो गई हैं। अगर इसमें भाजपा का साथ देने वाली पार्टी एआईडीएमके (9 सीट), बीजद (9 सीट), वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (6 सीट) और अन्य सहयोगी पार्टी और नामित सदस्यों की संख्या को जोड़ लिया जाए, तो मोदी सरकार के पास राज्यसभा में नंबर्स को लेकर कोई खास चुनौती नहीं है। गौरतलब है कि भाजपा ने इस राज्यसभा चुनाव के लिए अलग-अलग राज्यों में अपने बहुमत पर भरोसा दिखाया। इसके अलावा दूसरी पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों का फायदा भी भाजपा को ही मिला है। खासकर कांग्रेस के बागी एमएलए का। ऐसे में 2014 से 2019 के बीच जिन कानूनों और नियमों को पास कराने में भाजपा को संख्याबल की कमी से जूझना पड़ता था, अब उन्हें पूरा करने के लिए पार्टी के पास पर्याप्त नंबर हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 61 सीटों पर द्विवर्षीय चुनाव का ऐलान किया था। इनमें 55 वो सीटें शामिल थीं, जिनपर मार्च में ही चुनाव हो जाने थे, हालांकि कोरोनावायरस महामारी के चलते इनमें देरी हुई।

मप्र की गिनती देश के सबसे हरे-भरे प्रदेश में होती है। इसकी वजह यह है कि यहां हर साल करोड़ों पौधों का रोपण किया जाता है। लेकिन इस बार प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे वाले जिलों में पौधारोपण नहीं हो रहा है।

इस बार पौधारोपण नहीं

नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) वाले 16 जिलों में इस बार पौधरोपण नहीं होगा। वन विभाग ने आर्थिक तंगी और कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने हाथ खींच लिए हैं। विभाग और वन विकास निगम मिलकर इस बार 3.64 करोड़ पौधे लगा रहे हैं। पहली बारिश के साथ ही प्रदेश में पौधरोपण अभियान भी शुरू हो चुका है, जो जुलाई में भी जारी रहेगा। राज्य सरकार की माली हालत का असर इस बार वन विभाग पर भी पड़ा है। सरकार ने विभाग के लेखानुदान (बजट) में करीब 35 फीसदी की कटौती कर दी है। आमतौर पर विभाग का बजट 1200 करोड़ रुपए के आसपास होता है।

इस कटौती का असर विभाग की कई गतिविधियों पर पड़ा है। उन्हीं में से एक पौधरोपण अभियान भी है। यही कारण है कि विभाग ने इस बार लक्ष्य कम कर दिया है। औसत 5 करोड़ पौधे लगाने वाला विभाग इस बार 3.64 करोड़ पौधे लगाएगा। वह भी लगेंगे या नहीं इसमें भी संदेह है, क्योंकि कई जगह कोरोना संक्रमण के कारण समय से पौधरोपण की तैयारी यानी गड्ढ़ों की खुदाई नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि विभाग की नर्सरियों में सात करोड़ पौधे तैयार हैं। पौधरोपण के लिए गड्ढ़े मार्च में खोदे जाते हैं, ताकि गड्ढ़ों में तीखी धूप लगे और उनमें मौजूद पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु खत्म हो सकें। इस बार ज्यादातर जिलों में मई में गड्ढ़े खोदे गए हैं, जो मापदंड पर खरे नहीं उतरते।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरू (आईआईएससी) के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की वर्ष 2016 में आई रिपोर्ट में हमें चेताया गया था कि भोपाल शहर का ग्रीन कवर एरिया तेजी से घट रहा है और वर्ष 2018 के अंत तक यह घटकर महज 11 प्रतिशत रह जाएगा। तीन साल पहले मिली इस चेतावनी को न तो प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया और न ही शहर से जुड़ी जिम्मेदार संस्थाओं ने। यही कारण है कि शहर की हरियाली सिर्फ 9 प्रतिशत ही रह गई है। इसी रिपोर्ट में अपनाए गए पैरामीटर और बीते 10 साल की गूगल इमेजरी का सहारा लेते हुए ग्लोबल अर्थ सोसायटी फॉर एनवायरोमेंट एनर्जी एंड डेवलपमेंट संस्था ने यह दावा किया है। संस्था के रिसर्च एसोसिएट अभय शर्मा ने राजधानी को हराभरा रखने के लिए भोपाल नगर निगम और राजधानी परियोजना प्रशासन के उन दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जो हर साल राजधानी में लाखों पौधे रोपने के नाम पर करोड़ रुपए खर्च करते आ रहे हैं।

दो साल पहले नवीन विधायक विश्राम गृह के लिए 1149 पेड़ काटे गए थे। इसकी भरपाई के लिए 3372 नए पौधे रोपने का दावा किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा आरटीआई में पूछे सवाल के जवाब में 1000 पौधे चार इमली स्थित मुख्य सचिव के बंगले के पीछे रोपने का दावा किया गया है, जबकि 1372 पौधे पुरानी जेल से विंध्य कोठी (विधानसभा) परिसर के गैप में रोपने का दावा किया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों ही इलाकों में पहले से ही सघन पेड़ मौजूद हैं, ऐसे में यहां नए पौधे रोपने का न तो कोई औचित्य है और न ही इतनी खाली जमीन है कि 3 हजार से ज्यादा नए पौधे यहां लगाए जा सकें।

प्रदेश में जल सरंक्षण के लिए वन विभाग कैंपा फंड से 35 से 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके लिए 9 जिलों में 10 हजार हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। बड़ी बात ये है कि इसमें से 6 हजार हेक्टेयर जमीन सिर्फ दो जिलों की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का धार जिला। बाकी 7 जिलों में सिर्फ 4 हजार हेक्टेयर जमीन पर फंड खर्च होगा। इस फंड को वाटरशेड, स्टॉपेज डैम बनाने, पौधरोपण करने और कुआं-बावड़ियों का जलस्तर बढ़ाने में खर्च किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) आनंद बिहारी गुप्ता के कार्यालय से 20 मई को क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा फंड) में एपीओ वर्ष 2020-2021 के लिए प्रथम चरण का बजट आवंटित हुआ है। विभाग ने बजट जल ग्रहण क्षेत्र उपचार के लिए एनपीव्ही मद से जारी किया है। टीकमगढ़ जिले में बेतवा नदी के पास 1579 हेक्टेयर में काम होंगे। डीएफओ एपीएस सेंगर ने बताया कि हमने कंजर्वेशन और प्लांटेशन के लिए 21 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा था, जिसमें से प्रथम चरण का बजट आवंटन हुआ है।

● **राकेश ग्रोवर**

पुरानी गड़बड़ी की जांच भी नहीं हुई पूरी

वर्ष 2017 में नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 7 करोड़ पौधों को रोपने की जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 8 बार जांच होने के बाद भी सरकार पौधरोपण में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है। कमलनाथ सरकार में वनमंत्री रहे उमंग सिंघार ने खुद जंगल में जाकर अभियान के दौरान लगे पौधों के जीवित होने की जांच की थी। जिसमें जीवितता का प्रतिशत 18 बताया गया था। मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वनमंत्री को जिम्मेदार माना गया था। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत की अध्यक्षता में बनी समिति ने इस पर निर्णय भी लिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कर पाते, उससे पहले ही सरकार चली गई और मामला अब तक उलझा हुआ है।

पानी का संकट

पूरा देश जहां एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं मप्र और उप्र के बुंदेलखंड के लिए कोविड-19 से बड़ी समस्या है- 'पानी की समस्या।' यहां जल समस्या चरम पर है। ग्रामीण कई-कई किलोमीटर दूर पानी लेने जाने को मजबूर हैं। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों गांव पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई गांव में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई होती है लेकिन पैसे देकर ही पानी मिल पाता है। वहीं टैंकर से पानी लेते वक्त जिस तरह रोजाना भीड़ जुटती है उससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद क्षेत्र में करीब 10 लाख प्रवासी लौट आए हैं। जबकि कोरोनावायरस को लेकर कोई ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 लाख से अधिक लोग पानी से कमी वाले गांवों में वापस आ गए हैं। इस कारण इन गांवों में लोग कोरोना संकट से ज्यादा 'जल संकट' से परेशान हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन गांवों में बड़ी संख्या में श्रमिक वापस लौटे हैं जिससे जल संसाधनों पर तनाव बढ़ गया है। मप्र और उप्र की सरकारों का कहना है कि जलसंकट का समाधान जल्द ही किया जाएगा, यहां तक कि यह भी दावा किया गया कि लॉकडाउन के दौरान संकट से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। पन्ना के एक गांव के रहने वाले 30 वर्षीय युवक अनिल सेन बताते हैं कि गांव के आसपास 20 से अधिक हैंडपंप लगे हैं लेकिन सिर्फ एक या दो हैंडपंप में पानी आता है। वो भी कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी वजह से उन्हें दो से तीन किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता है।

अनिल बताते हैं, 'घर के लिए पानी की आपूर्ति टैंकर से होती है जिसे लोग खरीदकर पीते हैं। जो नहीं खरीद पाते वो कई-कई किलोमीटर रोजाना बर्तन लेकर पानी लेने जाते हैं। लॉकडाउन-1 में भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, क्या करें कोरोना से ज्यादा बड़ा यहां पानी का संकट है।' कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च को लागू किया गया था, बाद में तीन बार और लॉकडाउन की घोषणा की गई। 'अनलॉक-1' के तहत, इस महीने की शुरुआत में अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसी गांव की रहने वाली 42 वर्षीय गीता प्रजापति बताती हैं कि रोजाना कम से कम तीन बार वह बर्तन लेकर 2 किमी दूर पैदल चलकर पानी लेने जाती हैं। गीता ने बताया, ' एक बार में दो या तीन बर्तन से ज्यादा उठाकर लाना आसान नहीं होता। पिछले कई साल से यहां की यही स्थिति है।' गीता आगे कहती हैं, 'लॉकडाउन में कोई सुधार नहीं दिखा। शुरुआत में घर से बाहर निकलने में डर लगता था लेकिन क्या करें मजबूरी है।'

बुंदेलखंड में पानी की कमी तो सालों भर ही रहती है लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही यहां के हालात बदतर हो जाते हैं और यह हाल कई वर्षों से है। झांसी के पास स्थित रक्सा गांव से ही कुछ किमी दूर स्थित पुनावली कला गांव के निवासी 52 वर्षीय रामअवतार बताते हैं, 'गांव का कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। पानी का संकट गहरा गया है। कई बार टैंकर वाला दो रुपए या 2.5 रुपए तक प्रति डिब्बा चार्ज करता है। ऐसे में लॉकडाउन के इस दौर में पानी का खर्च झेल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।' रामअवतार बताते हैं, 'लॉकडाउन में उनके बेटे की नौकरी भी चली गई। ऐसे में पानी खरीदकर पीना बहुत कठिन होता जा रहा है।'

दुनियाभर की सरकारों सहित उप्र सरकार ने भी कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया है। लेकिन इन गांवों में, इसका निरीक्षण करना मुश्किल है। खजराहा गांव की सहूरी देवी का कहना है, 'गांव में लोग कोरोना से बचने के लिए बार-बार हाथ धुलने की बात करते हैं लेकिन जब घर में पानी ही नहीं तो हाथ कैसे धुलें। घर में पैसा ही नहीं तो मास्क, सैनेटाइजर कहां से खरीदें।' सहूरी आगे कहती हैं, 'यहां 3 महीने से अधिक हो गया लॉकडाउन को लेकिन यहां कोई सैनेटाइजर, मास्क लेकर बांटने नहीं आया और न ये सब बांटते हुए दिखा।' इसी गांव की देववती कहती हैं, 'जब टैंकर वाला आता है तो जिस तरह से लोग एक साथ पानी लेने निकलते हैं उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा।' देववती के मुताबिक, 'लोग करें भी तो क्या, उन्हें ये डर लगता है कि अगर टैंकर वाले से पानी नहीं लिया तो क्या पीएंगे।' वह आगे कहती हैं, 'पीने का पानी अधिकतर लोग टैंकर का ही इस्तेमाल करते हैं। हैंडपंप में कई बार गंदा पानी आता है, उसे पीने के इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। कोरोना के डर से लोग पानी लेना तो नहीं छोड़ सकते।'

स्थानीय अधिकारियों ने कहा था कि योजना के तहत बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के अंतर्गत झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट जिले में बेतवा, केन, मंदाकिनी, जामनी व धसान नदी तथा विभिन्न बांधों से पानी लेकर गांवों में पहुंचाया जाएगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कई बार प्रशासन को लिखा पत्र, नहीं हुआ एक्शन

सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह राजपूत पानी की समस्या को लेकर कहते हैं, 'वह पानी की किल्लत को लेकर पिछले कई महीनों से प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।' राजेंद्र बताते हैं, 'गांव के लोग एक रुपए प्रति डिब्बा के हिसाब से पानी लेते हैं। एक आदमी 70-80 रुपए प्रति दिन पानी पर ही खर्च कर देता है जो कि महीने में लगभग 2500 रुपए हुआ।' उन्होंने बताया, 'ऐसे में जिनके पास पैसा नहीं है, खर्च करने को उसकी स्थिति को समझिए। वो रोजाना बाल्टियां लेकर आसपास के उन गांवों में जाता है जहां पर हैंडपंप चल रहे हों।' राजेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक रक्सा गांव के आसपास दो पंप हाउस बनाए गए उसके बावजूद टंकियों में पानी नहीं आता। घरों के बाहर कई लोगों ने मोटर भी लगवाए लेकिन पानी नहीं आया पर पानी का बिल जरूर आ गया। ये हाल केवल रक्सा और पुनावली कला गांव का नहीं बल्कि झांसी जिले के दो दर्जन से अधिक गांवों का है। जल-जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक व बुंदेलखंड के सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह बताते हैं, 'पानी की समस्या यहां नई नहीं है। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी आते-जाते हैं लेकिन जमीनी हालात वैसी ही रहती है।'

R.N.I. NO.HIN 2002 8718 M.P. BPL 642 2018-20

चीन की चालबाजी और चौतरफा चुनौतियां

पड़ोसी से अच्छा कोई मित्र नहीं और पड़ोसी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इस लोकोक्ति को भारत से अधिक और कौन जान सकता है। क्योंकि इन दिनों भारत अपने पड़ोसी देश चीन की चालबाजी और अन्य पड़ोसियों की दखल अंदाजी से घिरा हुआ है। चौतरफा चुनौतियों के बीच भारत को अपने पड़ोसी देशों से भी जूझना पड़ रहा है। आखिर हमारी विदेश नीति में ऐसी कौन-सी खामी आ गई है, जिसके कारण पड़ोसी देश हमें दुश्मन समझने लगे हैं।

● राजेंद्र आगाल

इन दिनों भारत-चीन के बीच तनाव चरम पर है। 45 साल बाद सीमा पर चीनी सैनिकों ने इतने बड़े पैमाने पर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस तरह के विवादों की जड़ जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों में है, वहीं दूसरी ओर इस हालात के लिए जिम्मेवार भारतीय शासक वर्ग की ढुलमुल कूटनीति भी रही है। चीनी विस्तारवाद का सामना जिस दृढ़ता से किया जाना चाहिए था, उसमें भारत विफल रहा। पिछले सात दशक के दस्तावेज और सबूत यही बताते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस समय पाकिस्तान के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान भी भारत के खिलाफ हो गए हैं। नेपाल से तो अपना बेटी-रोटी का संबंध है। फिर भी नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। दरअसल, यह चीन की चालबाजी का परिणाम है। चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों पर अपनी मेहरबानियों का बोझ बढ़ाकर उन्हें भारत

के खिलाफ उकसा रहा है।

दरअसल, पिछले 6 साल में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी और यूरोप के देशों के साथ दोस्ती और व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं। यही नहीं उसने भारत के खिलाफ उन्हें उकसाने में भी कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इसका परिणाम यह है कि आज चीन की चालबाजी का जवाब देने के साथ ही भारत को अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है।

रक्षात्मक नीति पड़ रही भारी

यह एक कटु सत्य है कि पाकिस्तान के प्रति आक्रामक भारतीय कूटनीति चीन के सामने रक्षात्मक हो जाती है। वैसे कूटनीति का आक्रामक या दृढ़ होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करेंगे। आक्रामकता और दृढ़ता का तात्पर्य और उद्देश्य अपनी सीमा को बचाए रखना भी है। लेकिन भारतीय कूटनीति अभी तक चीनी विस्तारवाद को ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में समझने में विफल रही है। गौर करें तो पाएंगे कि चीन के भौगोलिक विस्तारवाद की नीति में काफी स्पष्टता है। बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण और संधि के भी चीन अपने आसपास के इलाकों पर दावा ठोक सकता है। चीन के भौगोलिक विस्तारवाद का वैचारिक आधार नहीं है। वहीं चीन इतिहास के प्रमाणों को तोड़-मरोड़ कर अपने विस्तारवाद को अंजाम देता रहा है। चीन का भौगोलिक विस्तारवाद चीन की अपनी सुविधा वाले साक्ष्यों पर ही आधारित है। बेशक इन साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं है।

गलवान में हमारे 20 बहादुर जवानों के बलिदान ने समूचे देश को गुस्से से भर दिया है। इस घटना से हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची है। अब भारत चीन के दुस्साहस का जवाब कैसे देता है, यह न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि विश्व व्यवस्था पर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। मौजूदा समय में हमारे पास तीन रणनीतिक विकल्प हैं। पहला, हम दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प के साथ चीन का डटकर मुकाबला करने का निश्चय करें और युद्ध छोड़कर सभी उपलब्ध राजनीतिक एवं कूटनीतिक विकल्पों का उपयोग करें। दूसरा, हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत पर गैर-बराबरी वाले कथित दोस्ताना रिश्तों के झूले पर झूलते रहें और शांत बैठ जाएं। युद्ध में कूदने का तीसरा रास्ता 21वीं शताब्दी के इस परमाणु युग में हमारा अंतिम विकल्प ही हो सकता है। इससे पहले कि हम तीन विकल्पों में से कोई एक चुनें, कुछ मूलभूत बातों को समझना आवश्यक है।

समय आ गया है कि राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ हर मोर्चे पर चीन से मुकाबले की तैयारी की जाए। इसके लिए भावनाओं के ज्वार पर नहीं, बल्कि आर्थिक विकल्पों पर आधारित तार्किक एवं ठोस रणनीति की जरूरत है। चीन में बने टीवी सेट और मोबाइल तोड़ने से हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जरूरी है कि हमारा नेतृत्व ऐसे ठोस रणनीतिक और सामरिक समाधान दे, जिससे चीन का मुगालता दूर हो और उसे सबक मिले कि शांति भंग करने की क्या कीमत हो सकती है? सबसे पहले हमें अपने आस-पड़ोस में समर्थन को मजबूत करना होगा। हमें क्वॉड जैसी पहल को भी तेज करना होगा। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ 2007 में क्वॉड की शुरुआत की थी। इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हमें क्वॉड को नाटो की तरह सामूहिक रक्षा ढांचे पर संगठित करना होगा, जिसमें एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है और सदस्य देशों की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी होती है। क्वॉड की सदस्यता भी बढ़ाई जानी चाहिए। वियतनाम इसमें शामिल होने का इच्छुक है। मलेशिया की भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है।

चीन की सोची समझी रणनीति

कोरोना महामारी के दौरान चीन ने एकाएक अपने कई पड़ोसियों के साथ तनाव क्यों बढ़ाया, यह बड़ा सवाल है। ताइवान सीमा पर चीन की नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां तेज हैं। दक्षिण चीन सागर में भी चीन आक्रामक बना हुआ है। इस साल अप्रैल में चीन के समुद्री जहाज ने वियतनाम के समुद्री इलाके में

कोरोना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा चीन

ऐसे समय में, जब भारत और चीन समेत पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित कर कोरोना संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, कोरोना को चीनी वायरस कहा जा रहा है, क्योंकि यह वायरस चीन के वुहान शहर स्थित लैब से निकला है। ऐसे में चीन पर पूरी दुनिया की उंगली उठी है। चीन अब इससे ध्यान भटकाने के लिए अपने सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। साथ ही विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, चीन बौखलाया हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर है कि कोरोना संकट की वजह से बाकी दुनिया उन्हें अलग-थलग न कर दे। साथ ही हाल के महीनों में विभिन्न देशों से व्यापार घाटे ने भी चीन की साम्यवादी सरकार की नींद उड़ा दी है। अमेरिका कोरोना संकट के बाद तो चीन पर लगातार हमलावर है। अब चीन की शी जिनपिंग सरकार भारत से सीमा विवाद को तूल देकर अपनी कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर कर रही है और इसी कोशिश का नतीजा है लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी। दरअसल, चीन की अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय से डगमगाई है। अन्य देशों से व्यापार के मामले में भी चीन का एकाधिकार कम हुआ है। भारत को ही लें तो भारत में समय-समय पर चीनी उत्पादों के बहिष्कार से जुड़ी मुहिम चलने से सरकार पर दबाव भी बढ़ा है इस वजह से कई करार कैंसल हुए और इसका परिणाम ये हुआ कि चीन से भारत का व्यापार प्रभावित हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है। कम कीमत की वजह से दुनियाभर में चीनी उत्पाद पहुंचते हैं। अगर अन्य देश चीनी प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। गलवान घाटी को लेकर चीन की जो अकड़ दिख रही है, वह एक तरह से चीन की रणनीति है और चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि बीते कुछ महीनों से जो व्यापार प्रभावित हुआ है, वह पहले जैसा हो जाए।

वियतनामी मछुआरों की नाव तोड़ दी थी। मई में दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाज और चीन के सर्वे संबंधी समुद्री जहाज का टकराव हो गया। कोरोना संकट के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर इंडोनेशिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन इंडोनेशिया के विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इधर चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। मौजूदा दौर में चीन के इस उकसावे वाली रणनीति के कारण तो अपनी जगह हैं ही, वैश्विक परिस्थितियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के कारण चीन को कई देशों ने घेरा है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ताइवान आदि देशों के बीच बढ़ते तालमेल से चीन खासा नाराज है। चीन की सरकार के मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स' ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकियों पर चेतावनी भरी टिप्पणियां की हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस समय ताइवान वियतनाम जैसे देशों को चीन के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक सच्चाई यह भी है कि इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोधी सक्रिय हैं। जिनपिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की कोशिश की है। कईयों को जेल भेजा, मौत की सजा दिलवाई। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक गुट जिनपिंग के खिलाफ मौके की तलाश में है। कोरोना महामारी फैलाने को लेकर चीन की वैश्विक घेरेबंदी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है, फैक्ट्रियों में उत्पादन घटा है, निवेश और निर्यात भी गिरा है। दूसरी ओर, हांगकांग संकट ने भी जिनपिंग की मजबूत छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर स्थिति मजबूत करने और लोगों का ध्यान बांटने के लिए पड़ोसी देशों की सीमाओं पर सैन्य आक्रामकता दिखा रहे हैं।

दूर हो रहे पड़ोसी देश

अब भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध पर बात करें तो पिछले 5-6 सालों में हम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में कामयाब नहीं रहे हैं। इसका फायदा चीन ने भरपूर उठाया है। चीन भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक रक्षा निर्यातक देश बनने में मदद कर रहा है जिससे वह म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों को हथियार बेच सकेगा। चीन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर पाकिस्तान अपने दम पर सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन शुरू कर सकेगा। यही नहीं चीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को लगातार आधुनिक हथियार देता रहा है। पाकिस्तान के अलावा चीन ने नेपाल के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं। नेपाल की वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है इसलिए भी चीन से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। जबकि चीन को इससे दोतरफा लाभ है- एक, उसे नेपाल में बढ़िया बाजार मिला और दूसरा, नेपाल के जरिए वह भारत पर कूटनीतिक व रणनीतिक दबाव बनाने में कामयाब हो रहा है। इसका असर यह हुआ है कि नेपाल ने भारत की सीमा पर चौकियां बनानी शुरू कर दी हैं। वहीं नेपाल ने नया नक्शा भी जारी किया है, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं।

सैन्य शक्तिः भारत बनाम चीन

भारत और चीन महाशक्ति माने जाते हैं। दोनों ने समय के साथ खुद को सैन्य और सामरिक दृष्टि से ताकतवर करने की कोशिश की है। देखते हैं कि हरेक क्षेत्र में दोनों देशों की क्या स्थिति है? सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के रक्षा बजट की। अमेरिका के बाद दुनिया में चीन का ही रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। इस समय चीन का रक्षा बजट 179 अरब डॉलर के करीब है। इसके मुकाबले फरवरी में पेश किए बजट के गणित में रक्षा क्षेत्र का खर्चा करीब 70 अरब डॉलर है; जो चीन से कहीं कम और जीडीपी का महज 2.1 फीसदी है। थल सेना की बात करें, तो भारत के पास जवानों की संख्या 14.44 लाख है; जबकि 21 लाख रिजर्व सैनिक भी भारत के पास हैं। चीन के पास 21.83 लाख सैनिक हैं। हालांकि उसकी रिजर्व ताकत 5.10 लाख जवान ही हैं। इसके बाद बात नौसेना की शक्ति की। भारत के पास एक युद्धपोत है, जबकि 18 विमान वाहक युद्धपोत हैं। भारत के पास 10 विध्वंसक युद्धपोत हैं; जबकि लड़ाकू युद्धपोतों की संख्या 15 है। इसके अलावा 135 गश्ती युद्धपोत भी हैं। भारत के पास 20 लघु जंगी जहाज के अलावा 14 पनडुब्बियां, 295 समुद्री बेड़े भी हैं। भारत के पास 22 मंजिल की इमारत जैसा ऊंचा आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत है, जिसमें कामोव-31, कामोव-28, हेलीकॉप्टर, मिग-29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टर, 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं; जो एक हजार किलोमीटर के बड़े दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आईएनएस चक्र-2 भी है, जो नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। चीन की बात करें, तो उसकी नौसेना में भारत की तरह एक युद्धपोत है; जबकि विमान वाहक युद्धपोत 48, विध्वंसक युद्धपोत 35, लड़ाकू युद्धपोत 51, गस्ती युद्धपोत 220, छोटे जंगी जहाज 35, पनडुब्बियां 68 और 714 समुद्री बेड़े हैं। अब बात वायुसेना ताकत की। भारत की वायुसेना में करीब 1.40 लाख सैनिक हैं। हमारे पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 10 सी-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और फ्रांस से आने वाले 36 राफेल फाइटर जेट जुड़ने वाले हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल की है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स का नाम दिया गया है। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को एचएएल से खरीदा है। उधर चीन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और उसके पास 3.25 लाख के करीब सैनिक हैं। इसके अलावा चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 192 एडवांस्ड लॉन्चर, जमीन से हवा में मार करने वाले एस-300 मिसाइल भी हैं।

उधर, चीन ने भूटान को भी अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। चीन और भूटान के बीच डोकलाम जैसे सीमा विवाद के अतिरिक्त कोई गतिरोध नहीं है। डोकलाम पठार में चीन के सैन्य दखल को अनदेखा कर भारत ने जिस तरह अपना रणनीतिक हित देखा उसने थिम्पू को बेहद निराश किया है। आज बीजिंग सॉफ्ट पावर डिप्लोमैसी और बेहतर भविष्य के वादे के जरिए भूटान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत अपनी जमीन खोता नजर आ रहा है। 1990 के दशक के बाद, चीन आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण में बांग्लादेश का बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। यही नहीं, बांग्लादेश बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव का भागीदार देश है जो भारत के कोलकाता के बेहद करीब से होकर गुजरेगा।

वहीं एक तरफ जहां रोहिंग्या मामले में पूरी दुनिया म्यांमार की आलोचना कर कर रही है वहीं दूसरी तरफ चीन चुपचाप म्यांमार के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने में लगा हुआ है। राखिने राज्य की स्थिति पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के नए खतरे ने एक बार फिर कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर म्यांमार में चीन की भागीदारी की आवश्यकता को उजागर किया है। म्यांमार के साथ चीन के रिश्ते अतीत की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है।

उधर, अफगानिस्तान, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का साझीदार देश है। चीन ने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में अपनी भागीदारी में लगातार वृद्धि की है। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ चतुर्भुज समन्वय और सहयोग तंत्र (क्यूसीसीएम) स्थापित कर बदख्शां प्रांत में एक आधार का निर्माण कर रहा है। साफ है कि पहले आतंकवाद और फिर अमेरिकी सेना की मौजूदगी से पीड़ित अफगानिस्तान को चीन का यह सहारा किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसके अलावा चीन मालदीव और श्रीलंका से भी नजदीकी बढ़ा रहा है। वहीं भारत अपने पड़ोसी देशों से लगातार दूर होता जा रहा है। यह चीन के लिए फायदे की नीति साबित हो रही है।

पंगे करता रहा है चीन

मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी हैं, जिनके बीच बॉर्डर पर हलचल तो बनी रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं की जाती। चीन की विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप की कोशिश करती रहती है, जिसका सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने-सामने आ जाती हैं, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता था। गलवान घाटी की घटना ने इस करार को तोड़ दिया है और दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई है। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया है कि जब भारत-चीन सीमा पर जवानों की मौत होती थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ, जो युद्ध में तब्दील हो गया। 1962 में चीन को जीत मिली थी। कहा जाता है कि भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके चलते उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, उस लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहें जब भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन 1967 में तो सेना ने चीन को सबक सिखा दिया। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। नाथु ला दर्रे की वो घटना आज भी चीन के लिए बड़ा सबक माना जाती है।

चीनी उत्पादों के बहिष्कार से चीन के होश ठिकाने आएंगे!

केंद्र सरकार ने 59 स्मार्टफोन एप को प्रतिबंधित करके चीन के प्रति अपना सख्त रुख दिखाया है। भारत अगर चीन को सबक सिखाना चाहता है तो एक बार चीनी उत्पादों को पूरी तरह नकार कर देखे, इससे चीन के होश ठिकाने आ जाएंगे। जिस तरह चीन की व्यापार नीति आक्रामक रही है, इससे यूरोप के देश भी घबराने लगे हैं और इस वजह से हाल के महीनों में यूरोपीय देशों से चीन का व्यापार प्रभावित हुआ है। कोरोना संकट के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई है कि विदेशी कंपनियां ही चीन से बाहर निकल रही हैं और भारत को एक बड़े मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। चीन के लिए ये चिंता का सबब है, इसलिए वह भारत पर गलवान घाटी के बहाने दबाव बना रहा है और इसकी आड़ में अपना आर्थिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहा चीन भारत से डरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती आबादी। भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। चीन के लिए उसकी आबादी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। चीन के अनुसार पॉप्युलेशन पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। एशिया में दबदबा बनाने के पीछे चीन की ये कोशिश वर्षों से रंग ला रही है। अब जबकि भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो चीन का डर अलग-अलग रूप से बाहर आ रहा है।

1967 में नाथु ला दर्रे पर हुआ टकराव

1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथु ला से सेबू ला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। 14,200 फीट पर स्थित नाथु ला दर्रा तिब्बत-सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटोक-यातुंग-ल्हासा व्यापार मार्ग गुजरता है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथु ला और जेलेप ला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के जेलेप ला तो खाली कर दिया, लेकिन नाथु ला दर्रे पर स्थिति पहले जैसी ही रही। इसके बाद से ही नाथु ला विवाद का केंद्र बन गया। भारत ने सीमा परिभाषित तो चीन ने आपत्ति की और हाथापाई व टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजिशन बचाकर रखी। चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चो ला में ये घटना हुई थी और ये जगह नाथू ला के पास ही थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे।

1975 में चीन ने भारतीय सेना पर अटैक किया

1967 की शिकस्त चीन कभी हजम नहीं कर पाया और लगातार सीमा पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ऐसा ही एक मौका 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में चार भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने एलएसी क्रॉस कर भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि, चीन ने भारत के इस दावे को नकार दिया। चीन की तरफ से कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी क्रॉस कर चीनी पोस्ट पर हमला किया और पूरी घटना को जवाबी कार्रवाई करार दिया।

1987 में भी टकराव देखने को मिला, ये टकराव तवांग के उत्तर में समदोरांग चू रीजन में हुआ। भारतीय फौज नामका चू के दक्षिण में ठहरी थीं, लेकिन एक आईबी टीम समदोरांग चू में पहुंच गई, ये जगह नयामजंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरंग चू और नामका चू दोनों नाले नयामजंग चू नदी में गिरते हैं। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहां डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंची तो यहां चीनी फौजें मौजूद थीं। समदोरांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था, भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपने सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था।

भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया और जवानों को विवादित जगह एयरलैंड किया गया। जवानों ने हाथुंग ला पहाड़ी पर पोजिशन संभाली, जहां से समदोई चू के साथ ही तीन और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया।

ताकत का नशा और असंतोष

शी जिनपिंग ही चीन में ऐसे नेता हैं, जिनके पास माओ त्से तुंग जैसी असाधारण शक्तियां हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी ताकत का अहसास इस बात से हो जाता है कि मार्च 2018 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जिनपिंग दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति रह सकते हैं। इससे पहले चीन में दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति न बन पाने की बाध्यता थी। इस तरह जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ हो गया है। बशर्ते वह अपनी तरफ से पद न छोड़ दें या कोई हालात उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न कर दें। हालांकि जिस तरह माओ त्से तुंग को अपनी आर्थिक नीतियों के कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी, कुछ वैसा ही जिनपिंग को भी आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। पश्चिम के मीडिया में पिछले कुछ समय से यह खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में असंतोष पैदा हो रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भले जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के सुपर पॉवर बनने की तरफ बढ़ने की बात जनता को बता रही है; देश की आंतरिक स्थिति इसके विपरीत है। चीन में सूचनाएं देश से बाहर देने पर सख्त पाबंदी है। लेकिन हाल के समय में ऐसी सूचनाएं, खासकर पश्चिम में पहुंचने लगी हैं; जो यह संकेत देती हैं कि हालात वैसे नहीं हैं, जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बताती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2010 से 2020 के बीच अपनी अर्थव्यवस्था दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस साल ऐसा हो पाएगा, इसकी दूर-दूर तक संभावना नहीं दिख रही। कम्युनिस्ट पार्टी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन को इस साल 5.6 फीसदी की दर से आगे जाना होगा।

हालांकि, 1987 में हिंसा नहीं हुई लेकिन अब 2020 में आकर एक बार फिर चीनी सेना ने टकराव को हिंसा में बदल दिया है। गलवान घाटी में 15 जून को जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही थी तो चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर अटैक किया।

ठोस रणनीति तय करने की जरूरत

चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए ठोस रणनीति तय करने की जरूरत है। युद्ध से किसी देश का भला नहीं होने वाला। युद्ध न तो भारत के हित में है, न चीन के। देखा जाए तो भारतीय कूटनीति के ढीलेपन ने ही चीन के मनोबल को मजबूत किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि साल 2003 में भारत ने चीन के अधीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को मान्यता दे दी। यह भारत की एक बड़ी भूल कही जा सकती है। भारत और चीन के बीच 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में द्विपक्षीय समझौते हुए। इन समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग, शांति और कूटनीति से सारे विवाद सुलझाएंगे। इसके बावजूद सीमा विवाद आज तक हल नहीं हुआ है, उल्टे भारतीय इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ जारी होती रही। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में छोटे-मोटे अतिक्रमण तो सैकड़ों बार किए हैं। 2013 में चीन-भारत सीमा पर मजबूती के लिए भारत सरकार ने माउंटेन कार्प्स के गठन की मंजूरी दी। लेकिन फिलहाल माउंटेन कार्प्स के गठन में कितनी प्रगति हुई है, यह बताना मुश्किल है।

चीन से सावधान रहने की जरूरत

भारत को चीन से सावधान रहने के साथ ही उसके विस्तारवादी रवैए का प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह राहत की बात तो है कि भारतीय और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच लंबी बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर सहमति बन गई, लेकिन अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि इसी तरह की सहमति 6 जून को भी बनी थी, लेकिन सबको पता है कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में किस तरह धोखे से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया? गलवान में चीनी सेना की धोखेबाजी यदि कुछ बता रही है तो यही कि वह बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। धोखा देना और फिर शांति-सहयोग की फर्जी बातें करना चीन का स्वभाव बन गया है। ऐसे किसी भी मक्कार देश की बातों पर यकीन करने का अर्थ है खुद को खतरे में डालना। चीन केवल भारत के मामले में ही समझौतों और आपसी समझबूझ को धता बताने में माहिर नहीं है। वह दुनिया भर में मनमानी करने के लिए कुख्यात है।

चीन का विकल्प बनें

भारतीय सेना के जवानों पर चीन के निर्दयतापूर्ण, कायरतापूर्ण और पूर्वनियोजित हमले से हमारे 20 बहादुर जवान लड़ते हुए शहीद हो गए और इसे भारत कभी भी भुला नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हमारे महान देश का हरेक नागरिक हमारी सेना के साथ खड़ा हो और सरकार यह सुनिश्चित करे कि विश्व हमारी एकजुटता का संकल्प देखे। चीन का इतिहास विश्वासघात से भरा है। यह हमेशा अन्य देशों की भूमि पर कब्जा करना चाहता है और किसी न किसी बहाने से इसे हथिया लेता है। हालांकि इसने पिछले 30 सालों में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की है, लेकिन राष्ट्र के रूप में इसका दर्जा घटा है और अब राष्ट्रों की वैश्विक समिति के एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दुख की बात है कि चीन जैसी अर्थव्यवस्था और आकार वाले देश ने अपने लगभग हर पड़ोसी पर धौंस ही जमाई है और स्थापित मानकों की जानबूझ कर अवहेलना की है।

भारत के संदर्भ में चीन ने हमारी सीमा के संबंध में लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत द्वारा उठाए गए सतत् और परिपक्व कदमों को मानने से इंकार कर दिया है। इसने बहुत से क्षेत्रों की विवादित सीमा के नक्शे का आदान-प्रदान भी नहीं किया है और इनका उपयोग भारतीय सीमा के भीतर घुसपैठ करने के लिए किया है। इसने भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सहायता की है, उसे हथियार तथा वित्तीय मदद दी। चीनी हथियारों का इस्तेमाल नेपाल के माध्यम से वामपंथी चरमपंथियों द्वारा भी किया गया है और इसने पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल गलियारा खड़ा कर दिया है। इस गलियारे में आने वाले खनिज प्रधान क्षेत्रों को दशकों से बाधित किया गया है, जिसके कारण भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और बेरोजगारी अधिक हो रही है।

ऐसा वर्तमान महामारी में साफ दिख रहा है। अधिकतर प्रवासी श्रमिक इसी गलियारे में रहते हैं और यहां साफ देखा जा सकता है कि इस अशांति से क्षेत्र में बेरोजगारी अधिक बढ़ी है और आर्थिक क्षति हुई है। संक्षेप में चीन ने दोहरा खेल खेला है। एक ओर 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा अपने व्यापार और अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के साथ ही इसने भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उकसावे के माध्यम से हमारे देश को स्थिर करने का प्रयास करता रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंधों पर बहुत अधिक समय दिया है। उन्होंने चीन का कई बार दौरा भी किया और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे संबंध स्थापित करने की लगातार मंशा दिखाई है। भारत के लोगों में चीन के लोगों के लिए कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं है। दोनों राष्ट्रों का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों तथा पारस्परिक जुड़ाव का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय लोग चीन के साथ अच्छे आर्थिक और कूटनीतिक संबंध चाहते हैं। लेकिन यह देखा जा सकता है कि चीन की सरकार और उसके सैन्य-औद्योगिक पारिस्थितिकीय तंत्र भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं।

चीन की रणनीति और मंशा को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने का काम करे। इस बारे में कई उपाय और विकल्प प्रक्रियाधीन हैं, फिर भी विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मदों के आयात सहित चीनी आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए जनता का आव्हान का समर्थन भी किया गया, जिसमें भारत ने पिछले वर्ष लगभग 400 अरब (बिलियन) डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। इनमें से अधिकतर वस्तुओं का निर्माण मूलत: चीन में हुआ था। चीनी कंपनियों ने भारतीय बाजार में मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं का अग्रणी खिलाड़ी (विक्रेता) बनते हुए दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। इस लिहाज से देखें तो 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान या आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम मजबूत विनिर्माण क्षमता का विकास नहीं करते, सेवाओं के साथ वस्तुओं का अधिकतर निर्यात नहीं करते, तब तक हम अपनी जनता की कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत को ऐसे ही आयातित वस्तुओं की बड़ी मात्रा में स्थानीय स्तर पर निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत में घटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए घटकों पर सीमा शुल्क क्रमश: आधार वर्ष से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर चौथे वर्ष तक 40 फीसदी तक करना चाहिए। यह भारत में निर्माण घटक को बढ़ावा देगा।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

भारत सरकार को संप्रभु रेटिंग की जरूरत

दरअसल, भारत सरकार को एक संप्रभु रेटिंग की जरूरत है, जिसे ब्याज दरों और ऋणों को बनाए रखने या घटाने के लिए वरीयता दी जाती है। इससे सरकार और उद्योगों से ज्यादा उधार मिलता है। रेटिंग एजेंसियों का काम निवेशकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों के जोखिम पर विश्वसनीय सूचना देना है, लेकिन ये रेटिंग एजेंसियां भारत में वित्तीय कठिनाई बढ़ा रही हैं। 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पहले संशोधन अधिकार को समाप्त कर दिया था। अगर भारत इसी तरह की नीति बना सके और चीन तथा रूस की तरह स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा दे सके, तो इससे भारत को चीन से वित्तीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार 2017 में एक नीति लेकर आई थी, जिसने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह आंशिक रूप से वित्तपोषित किसी परियोजना के लिए सार्वजनिक क्रय के लिए मदों की रणनीतिक सूची विनिर्दिष्ट की।

राहुल गांधी रिटर्न्स!

कांग्रेस समर्थकों एवं उनके चाहने वालों को 'राहुल गांधी रिटर्न्स' का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने 'गांधी परिवार' की राजनीतिक विरासत को बचाने के साथ-साथ आगे बढ़ाने की चुनौती है। इसके अलावा कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वापस लाने और खुद को साबित करने जैसी बड़ी चुनौती भी है। प्रियंका अपनी राजनीति का सिक्का उप्र में मनवा चुकी हैं और स्थानीय राजनीति में मशगूल हैं जबकि राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से केंद्रीय मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरने की रणनीति पर सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी गहलोत की मांग का समर्थन किया और कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को एक वर्चुअल सेशन बुलाना चाहिए और राहुल को पार्टी प्रमुख बनाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं? क्या पूरी पार्टी उन्हें अध्यक्ष बनता देखना चाहती है? 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस का इस चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन रहा कि पार्टी केवल 52 सीट जीत सकी। खुद राहुल अमेठी से चुनाव हार गए थे। उनके इस्तीफे के बाद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पद छोड़ने के समय राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को उनके साथ मिलकर काम नहीं करने की बात कही थी। बता दें कि वर्तमान में भारत-चीन तनाव के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की काफी आलोचना की है और सरकार से इसे लेकर कई सवाल किए हैं।

माना कि इस समय कांग्रेस का मान और प्रतिष्ठा वो नहीं रहे जो कभी हुआ करती थी लेकिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका के कंधों पर कांग्रेस का वो ही वक्त वापस लाने की जिम्मेदारी है। फिलहाल कांग्रेस के युवराज के पास राजनीति से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है लेकिन उसके बाद भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में उन्हें फिर से कांग्रेस की बागड़ोर संभालते हुए देखा जा सकता है। मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए।

हालांकि कुछ रणनीतिकारों को पूरा विश्वास था कि अमेठी की जनता राहुल गांधी को उसी तरह से स्वीकार करेगी, जिस तरह गांधी परिवार के अन्य सदस्यों सहित सोनिया गांधी को स्वीकार किया था। ये भी माना जा रहा था कि देश के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग्य को पुनर्जीवन देगी। ऐसा ही कुछ हुआ भी, उन्होंने एक लाख वोटों के अंतर से चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा। उनका चुनावी अभियान प्रियंका गांधी

छवि बदलने की चुनौती

राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने छवि को बदलकर एक बार फिर से खड़े होने की। राहुल को अब अपनी छवि से इतर एक छवि बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें एक विजेता बनकर उभरते दिख रहे हैं। कांग्रेस के सामने अपनी विचारधारा को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। राहुल कांग्रेस की विचाराधारा को तय नहीं कर पा रहे हैं। देश में लोग वामपंथी विचारधारा को नकार रहे हैं तो राहुल गांधी उसे स्वीकारते जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी गरीब तबके या अमीर तबके की बात करते हैं लेकिन जो देश का सबसे बड़ा वोटर है 'मिडिल क्लास', उसे अपने से दूर करते जा रहे हैं। पिछले दो लोकसभा चुनावों में भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण ये मिडिल क्लास वोटर ही तो रहा है। मिडिल क्लास से कांग्रेस ने अपना पूरा नाता तोड़ लिया है जबकि एक दौर में पार्टी का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। इसके अलावा कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या ये भी रही है कि न तो पार्टी कठिन निर्णय ले पा रही है और न ही मौकों को भुना पा रही है।

द्वारा संचालित किया गया था।

2006 तक राहुल गांधी केवल एक सांसद बने रहे और न पार्टी में और न ही सत्ता में कोई पद ग्रहण किया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थी कि सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं, जो बात बाद में सच साबित हुई।

जनवरी 2006 में, हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने राहुल गांधी को पार्टी में एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन की मांग की। इस पर उन्होंने कहा, 'मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं आपकी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा।' साथ ही धैर्य रखने को कहा और पार्टी में तुरंत एक उच्च पद लेने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से चार लाख से अधिक अंतर के साथ जीतकर लोकसभा पहुंची।

2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की लेकिन कांग्रेस केवल 22 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। उस समय तक राहुल गांधी को सबने राजनीति का कच्चा नींबू ही समझा लेकिन 2008 के आखिर में राहुल गांधी पर लगी एक स्पष्ट रोक से उनकी शक्ति का पता पूरे देश को चल गया। तत्कालीन उप्र मुख्यमंत्री मायावती ने राहुल गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोक दिया। बाद में राज्य के राज्यपाल टीवी राजेश्वर (जो कुलाधिपति भी थे) ने विश्वविद्यालय के कुलपति वीके सूरी को पद से हटा दिया। गवर्नर राजेश्वर गांधी परिवार के समर्थक और सूरी के नियोक्ता थे। इस घटना को शिक्षा की राजनीति के साक्ष्य के रूप में उधृत किया गया और एक अखबार में एक व्यंग्यचित्र में लिखा गया– वंश संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुलजी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने राहुल गांधी की ताकत का एक ट्रेलर दिखा दिया।

2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने उप्र में 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया और इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ गया लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस तिनके की भांति उड़ गई। पिछले आम चुनावों में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लोकसभा में केवल 44 सीटों पर सिमट गई। हालांकि राहुल और सोनिया ने अपनी सीट सुरक्षित रखी। 16 दिसंबर, 2017 को राहुल गांधी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत किया गया। इसके बाद पार्टी का पूरा दारोमदार राहुल गांधी के हाथों में आ गया लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के हाथ में रही और कमान सोनिया गांधी के।

2019 में हुए लोकसभा चुनावों में उम्मीद थी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मोदी लहर के बावजूद भाजपा को कड़ी चुनौती देगी लेकिन इतिहास फिर दोहराया गया। भाजपा 302 सीटें जीत पूर्ण बहुमत से सदन में पहुंची और कांग्रेस 52 पर सिमट गई। राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। खुद राहुल गांधी अपनी परम्परागत अमेठी सीट से भाजपा की स्मृति ईरानी के सामने हार बैठे। इससे दुखी होकर हार का पूरा दारोमदार उठाते हुए राहुल गांधी ने 3 अगस्त, 2019 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वर्तमान में जो संगठन के हालात हैं, बेहद सोचनीय हैं। मध्य प्रदेश में सरकार गिर चुकी है, गुजरात व गोवा में कांग्रेस विधायक टूट चुके रहे हैं, राजस्थान में संकट बरकरार है, हरियाणा में भी हुड्डा बगावती तेवर दिखा रहे हैं, पंजाब में अंतर कलह चल रही है, उप्र में हालात बेहद सोचनीय हैं, महाराष्ट्र व झारखंड में कांग्रेस सरकार में जरूर है लेकिन सहयोगी बनकर। 18 से अधिक राज्यों में भाजपा का कमल खिला हुआ है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के साथ-साथ आगे बढ़ाने की चिंता है। कुल मिलाकर कांग्रेस की राजनीति अर्श से फर्श पर आ गिरी है। अब कांग्रेस को फिर से खड़ा करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है।

● **इन्द्र कुमार**

नई दिशा मिलने का संकेत

राहुल गांधी जिस तरह से वापसी कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिलती दिख रही है। विपक्ष की अगर बात आती है तो कांग्रेस ही दिखती है। राहुल गांधी के एक बयान पर जिस तरह से भाजपा हमलावर होती है, उससे भी राहुल की राजनीतिक अहमियत का पता चलता है। जिस तरह कोरोना संकट को लेकर उन्होंने तीन महीने पहले ही सरकार को आगाह कर दिया था, जिस तरह वित्तीय संकट को लेकर वे एक्सपर्ट से लगातार वार्ता कर रहे हैं, जिस तरह से चीन से हिंसक झड़प में उन्होंने भारतीय सैनिकों के निहत्थे होने का मसला उठाया है, अपनी छवि से इतर एक अलग छवि बनाने की कवायद जरूर करते दिखे हैं। राहुल अभी जिस तरह की राजनीतिक पहचान बना रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी राह पर चलकर कांग्रेस के खोए हुए जनाधार को वो वापस ला सकते हैं। कोरोना को लेकर अपने रुख को बेहद सियासी समझदारी से तय कर रहे राहुल गांधी के ट्वीट सरकार को घेरते हैं लेकिन उनका लहजा आक्रामक न होकर सुझाव देने वाला होता है। राहुल दूध का जला, छाछ भी फूंक-फूंककर पीने वाली कहावत चरितार्थ करते हुए कोरोना पर अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर सजग हैं। वे जानते हैं कि कोरोना संकट के टल जाने के बाद ये सभी बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्णयों से भले ही एक कुशल प्रशासक बनकर उभरे हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। क्योंकि कमजोर विपक्ष होने के कारण उन्हें अभी तक अपनी गलतियों का अहसास नहीं हो पाया है। उनकी उपलब्धियों पर चुनौतियां भारी पड़ रही हैं।

उपलब्धियों पर भारी चुनौतियां

वर्तमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मेहरबान हो सकता है लेकिन इतिहास उनके प्रति बहुत निष्ठुर रहेगा। मोदी अपने तमाम अनुचित फैसलों को लेकर बचते आ रहे हैं, जिनमें बड़ी भूलें भी शामिल हैं और आने वाले सालों में भी शायद वो यही करते रहेंगे क्योंकि दयालु मतदाता अपने सम्मान से उन्हें नवाजते रहेंगे और उनका दिखावटी अंदाज बाकी हर चीज पर हावी होता रहेगा। लेकिन इतिहास मोदी को एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा, जिसे एक जबर्दस्त जनादेश मिला लेकिन वो राष्ट्र निर्माण में कोई ठोस योगदान देने में नाकाम रहा। जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गलवान पर बयान के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, तो उनका वो मशहूर बयान याद आ गया, जो उन्होंने 2014 में अपने कार्यकाल के अंत की तरफ दिया था- 'समकालीन मीडिया या संसद के विपक्षी दलों के मुकाबले, इतिहास मुझ पर ज्यादा मेहरबान रहेगा।'

मूर्खता भरी नोटबंदी से लेकर अनुच्छेद-370 को कमजोर करने के फैसले को जबर्दस्ती थोपने और उसके बाद कश्मीर में सख्त शिकंजा कसने और विवादास्पद व फूट डालने वाले कानून लाने तक, मोदी ने पूरे राजनीतिक माहौल को खराब कर दिया है और अपने पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों को भी बिगाड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत से मील के पत्थर लगा दिए हैं, जो उनका इतिहास लिखे जाते समय, उनकी चापलूसी करते नहीं देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी का शुमार, सबसे लोकप्रिय नेताओं में होता है। उनके जैसा अनुकरण आजाद भारत में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। चुनावों को कवर करने और दूसरे आयोजनों के सिलसिले में मैंने काफी सफर किया है और उनकी जबर्दस्त लोकप्रियता देखी है। ये लोकप्रियता हर जेंडर, हर जगह और हर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में मिलती है।

जबर्दस्त साख और लोगों के साथ जुड़ने की विलक्षण क्षमता ने ही मोदी को इस स्थान पर बिठाया हुआ है और बिठाए रखेगी। उनकी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष के तीखे हमले उनके कुशल अभिनय के सामने फीके पड़ जाते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि चीजों को घुमाने की उनकी कला, बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर भारी पड़ जाती है। अभी तक किसी भी चीज ने मोदी को क्षति नहीं पहुंचाई है- चाहे वो नवम्बर 2016 को एक ही बार में, नोटबंदी का मूर्खता भरा फैसला हो या उसके कुछ समय बाद ही, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जीएसटी लागू करना हो, दोनों का ही हर वर्ग के मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। और फिर भी, जब भी मोदी पर हमला होता है, वो और मजबूत हो जाते हैं। कोई इस बात को नहीं भूल सकता कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले, कैसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का चौकीदार चोर है और राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप, जो मोदी पर सीधा हमला था, उल्टे पड़ गए।

बिना कुछ सवाल पूछने वाले मतदाता, जो प्रधानमंत्री की कही कुछ भी बात मान लेते हैं और एक बिखरा हुआ, बेमेल और अक्सर डरा हुआ विपक्ष, मोदी की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। इसलिए वर्तमान, प्रधानमंत्री पर मेहरबान है। लेकिन भविष्य में उन्हें किस चीज के लिए याद किया जाएगा और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएंगे? बहुत से प्रतिकूल नीतिगत फैसलों में, खासकर आर्थिक मोर्चे पर, नोटबंदी, और उसके बाद 'त्रुटिपूर्ण' और जल्दबाजी में लाया गया जीएसटी, लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे, जिनके नकारात्मक असर अर्थव्यवस्था में अभी तक देखे जा रहे हैं। जब मोदी ने उन्हें बड़े आर्थिक सुधार बताकर देश के सामने पेश किया, तो उनका उद्देश्य क्रमशः काले धन को कम करना और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को औपचारिक रूप देना था लेकिन सच्चाई ये है कि वो उस अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार थी, जो उस समय तक ठीक से चल रही थी। वो उनका पहला कार्यकाल था। अपने दूसरे कार्यकाल में, जहां वो और भी बड़े जनादेश के साथ लौटे थे,

अगली चुनावी चुनौतियां

महामारी का प्रकोप बढ़ने और लॉकडाउन की तमाम कमियों के बीच भाजपा और मोदी को इसी साल बिहार और अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल जैसे अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों का सामना करना है। बिहार और बंगाल भाजपा के लिए अहम मुकाबले हो सकते हैं और वह वहां की सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। यह इसलिए भी जरूरी है कि भाजपा लगातार कई राज्य हार चुकी है या जैसे-तैसे जीती है या फिर ऑपरेशन कमल के जरिए सत्ता हथियाई है। यह भी गौरतलब है कि दूसरे कार्यकाल में कश्मीर, सीएए जैसी कथित उपलब्धियां महाराष्ट्र और हरियाणा में लोगों को आकर्षित नहीं कर पाई थीं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठजोड़ को अस्थिर करने की सुगबुगाहटें भी तेज हैं। बहरहाल, अब देखना है कि मोदी का करिश्मा कितना काम करता है। लेकिन पहला साल तो उसके लिए मिला-जुला रहा है। जहां तक पार्टी का मसला है तो वहां यह साफ है कि भाजपा में या मंत्रिमंडल में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले ही सुप्रीम हैं। अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की सक्रियता और फैसलों में भागीदारी का आंकलन करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के फैसलों की छाप ही आपको नजर आएगी। यही हाल उनकी पार्टी भाजपा का है। जेपी नड्डा अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन कमान पूरी तरह उनके हाथ में है, यह कहना जल्दबाजी होगी।

मोदी सरकार ने कई ऐसे कानून पारित किए, जिन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने में तनाव पैदा कर दिया और उसमें ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

मोदी को उस बदनामी के लिए याद किया जाएगा कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी की सरकार की अगुवाई की, जिसने तमाम राज्यों में ध्रुवीकरण की राजनीति की। इतिहास नहीं भूलेगा जब अमित शाह ने गैर-कानूनी प्रवासियों की तुलना 'दीमकों' से की और कहा कि उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। उस समय मोदी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। इतिहास मोदी पर मेहरबान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को, जातीय मुद्दे से सांप्रदायिक मुद्दे में तब्दील कर दिया या विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लेकर आए। तीन तलाक कानून, आरटीआई और यूएपीए जैसे कानूनों में संदेहास्पद बदलाव और 'बाहरी' को लेकर कट्टर राष्ट्रवाद- ये सब दर्शाते हैं कि कैसे मोदी सरकार का पूरा जोर, सिर्फ अपने संकुचित विजन को पूरा करने पर रहा है। कोविड संकट अभूतपूर्व भी है और निष्ठुर भी, लेकिन मोदी सरकार का श्रम संकट से निपटना, उसकी लापरवाही और राज्यों के ऊपर हावी होकर, संघीय ढांचे को कमजोर करने की उसकी कोशिश पर, हमेशा सवाल उठते रहेंगे।

सरकार और भाजपा के अंदर प्रतिभा की कमी और दूसरी पीढ़ी के ठोस नेताओं को तैयार करने या योग्य लोगों को रोके रखने की उनकी असमर्थता भी, मोदी की सबसे बड़ी कमजोरियां रही हैं। मोदी ने भारत की विदेश नीति को जिस तरह से संभाला है, वो भी उन्हें एक खराब स्थिति में दिखाता है। चाहे वो चीन के साथ एलएसी पर चल रहा गतिरोध हो, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं या लड़ाकू नेपाल का इकतरफा ढंग से अपना नक्शा बदलकर, भारत के इलाके को उसमें दिखाना हो या फिर कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हो रहे निरंतर हमले हों, भारत को अपने पड़ोसियों से जितनी लगातार चुनौतियां अब मिल रही हैं, उतनी पहले कभी नहीं मिलीं।

सर्वदलीय बैठक में गलवान पर मोदी के बयान

ने हंगामा खड़ा कर दिया, जो इसे और भी दर्शाता है कि वो मतदाताओं को खुश करने में लगे राजनेता की तरह सोचते हैं, बजाय ऐसे लीडर के जो भौगोलिक और सामरिक नजरिए से सोचता हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे ने बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर असर डाला है जबकि राजपक्षा बंधुओं की अगुवाई में, श्रीलंका के रिश्ते भी भारत के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं हैं और वो चीन के साथ निकटता के लिए जाना जाता है।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोदी ने, कुछ भी हासिल नहीं किया है। उनके पहले कार्यकाल में रखी गई कल्याण की बुनियाद- ग्रामीण आवास मुहैया कराने से लेकर कुकिंग गैस कनेक्शंस, गांवों में बिजली, स्वास्थ्य बीमा, स्कीमों को लागू करने में आ रही खामियां को दूर करने के लिए आधार पर जोर और गरीबों तक लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक-आर्थिक जातीय गणना का मजबूती से इस्तेमाल- ये सभी नीतिगत कदम बहुत लोकप्रिय, उपयोगी और ठोस साबित हुए हैं। कूटनीतिक रूप से, भारत-अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्ते, मोदी सरकार की विदेश नीति की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। 2016 में सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हवाई हमले ने भी मोदी की ताकत को बढ़ाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कल्याण और शासन पर मोदी सरकार का फोकस, दूसरे कार्यकाल में गायब ही हो गया है। पिछले एक साल में, ज्यादा अहम मुद्दों को छोड़कर, मोदी सिर्फ बहुसंख्यकवाद और राष्ट्रवाद के अपने संकीर्ण विजन को पूरा करते और उन ऐतिहासिक मुद्दों को खत्म करते दिखाई दिए हैं, जो उनके प्रमुख मतदाता वर्ग के लिए महत्व रखते हैं।

मोदी शायद अभी कुछ और समय तक चुनाव जीतते रहेंगे लेकिन वोट पाने की अपनी कमाल की क्षमता के अलावा, दीर्घकाल में उन्हें किस चीज के लिए याद किया जाएगा? ये वो सवाल है जो मोदी के सामने खड़ा होगा। अगर वो चाहते हैं कि इतिहास उन्हें एक राष्ट्र-निर्माता के रूप में याद रखे, न कि सिर्फ एक चुनाव जीतने वाली और धारा प्रवाह बोलने वाली मशीन की तरह, तो उन्हें अपना अंदाज बदलना होगा। लेकिन तमाम तरह के बदलाव और क्रांतिकारी निर्णय के बाद भी मोदी की छवि राष्ट्र निर्माता की नहीं बन पाई है। अब देखना यह है कि वे आगे किस तरह के कदम उठाते हैं।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

आर्थिक बहाली के उपायों का टोटा

आर्थिक मोर्चे पर जहां सरकार को तेजी से काम करना चाहिए था, वहां उसके फैसले कारगर साबित नहीं हुए। पांच जुलाई को 2019-20 के लिए पूर्ण बजट पेश किया गया और उसमें देश की अर्थव्यवस्था को 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित करने के साथ ही बजट को इसे हासिल करने का रोडमैप बताया गया। हालांकि, यह बजट फरवरी, 2019 में पेश अंतरिम बजट का विस्तार ज्यादा और नया बजट कम था। इसके बाद फरवरी, 2020 में चालू साल (2020-21) का बजट पेश किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने की कोई मजबूत रणनीति नहीं दिखी। इसके राजस्व और विकास दर के लक्ष्यों पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि पिछले वित्त वर्ष से ही आर्थिक विकास दर गिरावट के नए रिकार्ड भी बना रही है। वहीं, 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन ने आर्थिक मोर्चे पर स्थिति को संभालने की नई चुनौती खड़ी कर दी है। रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है कि चालू साल में अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है। एसबीआई रिसर्च के ताजा अनुमान में कहा गया है कि इस सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच फीसदी की गिरावट आ सकती है जबकि पहली तिमाही में यह गिरावट 40 फीसदी की हो सकती है। तमाम रेटिंग एजेंसियां और वैश्विक संगठन इसी तरह के अनुमान जारी कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी से पैदा आर्थिक संकट ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है और तमाम कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं।

'गोबर' पॉलिटिक्स

छत्तीसगढ़ में इन दिनों गोबर को लेकर राजनीति गर्माई हुई है। दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना लॉन्च की गई है। योजना के तहत सरकार अब जैविक खाद बनाने के लिए गोबर भी खरीदेगी। इसी को लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने तो ट्वीट कर योजना पर सवाल उठाते हुए गोबर को राजकीय प्रतीक चिन्ह बनाने का सुझाव दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए चंद्रकार सहित अन्य भाजपा नेताओं को दिमाग में भरे गोबर को इस योजना के तहत बेचकर आर्थिक लाभ कमाने को कह दिया। चंद्राकर के ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने टिप्पणी की। वर्मा ने कहा कि आपकी संघशिक्षा और दीक्षा एकदम दूरस्त है। वो विनायक सावरकर, जिन्हें आप वीर कहते हैं, वो भी गौमाता और गोबर के बारे में ऐसी ही अपमानजनक बात कहते थे।

भाजपा चुनाव में अवसरवादिता का लाभ उठाते हुए हिंदुत्व और गौ सेवा का मुद्दा भुनाती रही है। लेकिन वास्तव में ना तो भाजपा के मन में हिंदुओं के प्रति कभी प्रेम रहा है और ना ही गौ माता के प्रति। गोबर के बाद सरकार गोमूत्र की खरीदी पर भी विचार कर सकती है, तब इस योजना का भाजपा के द्वारा इतना विरोध क्यों? भाजपा तय कर ले या तो वह गौ माता, सनातन हिंदू धर्म और छत्तीसगढ़ वासियों के पक्ष में है या खिलाफ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की जनता के मान-सम्मान और अस्मिता का प्रतीक है। यह प्रतीक चिन्ह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर, फसल उत्पादन, विद्युत उत्पादन और समृद्धि वनों की विरासत से जोड़ता है।

बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार से छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने 5 मंत्रियों की समिति और अधिकारियों की एक अन्य समिति भी बनाई है। मंत्रिमंडल की समिति गोबर खरीदने की दर तय करेगी, जबकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति गोबर से बनी खाद खरीदने की व्यवस्था करेगी। पशु पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी। गौ-पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीद उससे वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाएगी। जिसे बाद में किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन होगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा।

इस योजना से गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे। गोबर की खरीदी निर्धारित दर पर होगी वहीं सहकारी समितियों से वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री होगी। गोबर की खरीदी की दर तय करने 5 सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति गठित की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि गोधन न्याय योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौ-पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने कहा कि गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण किया गया है। राज्य के 2,200 गांवों में गौठान का निर्माण हो चुका है इसके साथ ही 2,800 गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले दो-तीन महीने में लगभग 5,000 गांवों में गौठान बन जाएंगे। इन गौठान को हम ग्रामीण के लिए आजीविका केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां बड़ी मात्रा में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण भी महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि गोबर प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने वाली छत्तीसगढ़ देश की पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार गोमूत्र खरीदने पर भी विचार कर सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

इस योजना को पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आधार पर तैयार किया गया है। इससे अतिरिक्त आमदनी सृजित होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूरा एक सिस्टम काम करेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट के जरिए हम जैविक खेती की ओर बढेंगे। इसका बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से होगी।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

राज्य जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो, इसलिए किसानों से गोबर खरीदने का फैसला किया गया है। किसानों से गोबर खरीदने की दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोबर खरीदी से लेकर उसके वित्तीय प्रबंधन एवं वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव एवं उप सचिव की एक समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं किसानों, पशुपालकों एवं बुद्धिजीवियों से राज्य में गोबर खरीदी के दर निर्धारण के संबंध में सुझाव देने का आग्रह करता हूं।

बढ़ रही खाई

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला राज्यसभा चुनावों को लेकर विधायकों की हुई बाडेबंदी से जुड़ा है। सचिन ने बिना नाम लिए फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिसने जो कहा और कहलवाया गया, सब निराधार साबित हुआ। उसका कोई औचित्य ही नहीं था।

सचिन की मानें तो राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और समर्थक विधायकों की बाडेबंदी का कोई औचित्य ही नहीं था। यह बात उनके दावे के अनुसार कांग्रेस के पक्ष में पड़े 100 फीसदी वोट के जरिए साबित हो गई। पायलट ने कहा कि उनका दावा सही साबित हुआ कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों के 100 फीसदी वोट राज्यसभा प्रत्याशियों को मिलेंगे और वही हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत के भाजपा पर कांग्रेस विधायकों की तोडफोड़ की साजिश रचने के आरोप पर सचिन पायलट ने कहा कि जिसने जो कहा और कहलवाया गया, वह सब निराधार ही साबित हुआ।

वैसे राज्यसभा चुनावों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और प्रदेश संगठन में होने वाले बदलाव पर सबकी नजर है। ऐसे में 21 विधायकों से पार्टी को सरकार में लाने की अपनी कोशिशों को एक बार फिर से गिनाते हुए पायलट ने साफ कर दिया कि विपक्ष में रहते हुए घेराव और धरने करके व भूख हड़ताल के जरिए पार्टी को सरकार में लाने वाले कार्यकर्ताओं के मान-सम्मान की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। ऐसे में चाहे नियुक्ति पार्टी के माध्यम से हो या सरकार में भागीदारी के माध्यम से, सम्मान उन्हें मिलेगा।

सचिन पायलट के तीखे तेवरों और आए दिन दिए जाने वाले बयानों से साफ है कि वे ना तो सरकार के कामकाज से ज्यादा खुश हैं और ही सरकार बनने के बाद सूबे में मिली भूमिका उन्हें अधिक रास आ रही है। शायद यही कारण है कि पार्टी के केंद्रीय नेताओं की तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान कांग्रेस में बनी गुटबाजी भी मौके-बेमौके पर सामने आ ही जाती है। ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के बाद कांग्रेस के इन नेताओं का रुख कैसा रहता है।

राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हैं। एक वर्ग उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही प्रदेश अध्यक्ष पद फिर से मिलने की अटकलें लगा रहा है। ऐसे में सचिन पायलट का इस मामले में बयान आया है। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। किसको क्या काम देना है यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व अच्छी तरह जानता है। किसका कहां उपयोग करना है, उसका उपयोग करते रहते हैं। चाहे संगठन का हो या सरकार में काम देना, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेती आई है और लेती रहेगी। उपमुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने 6 साल में जो काम किया, 21 विधायक थे उससे लेकर आज हम सरकार में बैठे हैं। ये उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अब हम लोगों की उम्मीदों के मुताबिक शासन दें, जिसकी उम्मीद जनता हमसे करती है।

राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है

राजनीतिक नियुक्तियों और फेरबदल को लेकर उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सोनिया गांधी ने कॉर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उस कॉर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से तमाम नियुक्तियां भी होंगी। जिनको जो जिम्मेदारी देनी है, यह इस कमेटी का काम होगा। प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसका पूरा संचालन करने के लिए, यह कमेटी बनाई गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे नियुक्तियां हों या फेरबदल या बदलाव करने की स्थिति हो सब निर्णय कॉर्डिनेशन कमेटी के जरिए ही लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाकर इन सब पर फैसला किया जाएगा। पायलट ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, लाठी खाई अर्थात् जिन लोगों ने रगड़ाई खाई है, उन लोगों के मान-सम्मान की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। चाहे कुछ हो जाए उन लोगों की प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। खून-पसीना बहाकर हम लोग इस पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं, उसका पूरा सम्मान होगा, चाहे नियुक्ति के माध्यम से हो या सरकार में भागीदारी के जरिए हो यह सुनिश्चत करना मेरा पहला दायित्व है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रहे **पॉवर गेम** के बीच एक और उपमुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कसरत तेज हो गई है। गहलोत खुद एक और उपमुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भाजपा में पहली बार सतीश पूनिया के रूप में जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कांग्रेस में जाट समाज में दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के जाट नेताओं ने दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाई है। गहलोत इसी का लाभ उठाते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया में से किसी एक को उपमुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कटारिया मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं, चौधरी वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। दोनों ही गहलोत के निकट माने जाते हैं। चौधरी और कटारिया ने पिछले दिनों दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर जाट समाज को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग रखी है। उधर, दूसरी तरफ गहलोत विरोधी खेमा पूरी तरह से आश्वस्त है कि सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों पदों पर रहेंगे। एक और उपमुख्यमंत्री बनाकर एक तरफ जहां गहलोत पायलट को बैलेंस करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जाट समाज को खुश करने की भी रणनीति पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में जाट समाज भाजपा की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, इसे रोकने के लिए उपमुख्यमंत्री बनाया जाना आवश्यक है। प्रदेश की राजनीति में जाट मतदाता हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहे हैं। शेखावाटी के साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभाग के चुनाव परिणाम काफी हद तक जाट मतदाताओं पर निर्भर करते हैं। भाजपा में जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने से कांग्रेस पर जाट नेता को सत्ता व संगठन में वजन देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

ग्लैमरस रुख

महाभारत धारावाहिक का चर्चित चेहरा रहीं रूपा गांगुली से लेकर टॉलीवुड स्टार लॉकेट चटर्जी और अब फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल, बंगाल भाजपा ने ग्लैमर की दुनिया से आई महिलाओं को महिला मोर्चा के नेताओं के तौर पर नियुक्त करने का चलन शुरू कर दिया है। पॉल ने इसी महीने की शुरुआत में बंगाल महिला मोर्चा के प्रमुख का पद संभाला। भाजपा में आने के बाद वो पिछले एक साल में वरिष्ठ पद पर पहुंच गई हैं। बीते पांच सालों में ये पद गांगुली और चटर्जी के पास था। दोनों ही अब राज्यसभा और लोकसभा से सांसद हैं।

भाजपा के नेताओं ने कहा कि पार्टी में ऊंची रैंक तक पहुंचने में उन्हें बाधा भी आई। वरिष्ठ नेता उनके फिल्म और फैशन के बैकग्राउंड को नुकसान के तौर पर देखते रहे हैं। जबकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने स्वीकार किया कि उनकी ग्लैमर और सार्वजनिक अपील उन्हें सबसे आगे लाने में एक कारक थी, उन्होंने उन्हें पार्टी में खुद को उस राज्य में स्थापित करने में मदद करने का श्रेय दिया जहां पार्टी को अभी भी सत्ता नहीं मिली है। भाजपा का महिला मोर्चा राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसमें धरने, सड़क अवरोध और घेराव में भाग लेना शामिल है। आंदोलन के दौरान, यह रक्षा की पहली पंक्ति की तरह काम करता है।

भाजपा की महिला मोर्चा की भूमिका को विशेष रूप से प्रमुखता तब मिली जब 2018 के पंचायत चुनावों में भाजपा ने 5,779 ग्राम पंचायत सीटों पर 2,500 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। चटर्जी का कहना है कि 2018 के पंचायत चुनावों में 2,500 के करीब महिला उम्मीदवारों के जीतने का यह मतलब है कि बंगाल की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो अब अपने घरों से निकल रही हैं। जबकि इसने सांगठनिक तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मोर्चा को वास्तव में तब प्रमुखता मिली जब गांगुली को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया। गांगुली ने 2015 में भाजपा के बंगाल महिला मोर्चा प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने पार्टी की एक वरिष्ठ नेता ज्योत्सना बनर्जी की जगह ली, जो लगभग पांच साल तक इस पद पर रहीं थी। वह 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद एक साल पहले भाजपा में शामिल हुई थीं।

बंगाल भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दिलीप घोष के चुनाव में महिला विंग की प्रमुख के रूप में चटर्जी की नियुक्ति की घोषणा हुई। चटर्जी को भाजपा में शामिल होने के दो साल बाद जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। 2015 तक, वह तृणमूल कांग्रेस की सदस्य थीं, जिसके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ही राज्य में सेलिब्रिटी राजनेताओं के ट्रेंड को शुरू किया था। चटर्जी ने पार्टी छोड़ दी क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें तृणमूल कांग्रेस में 'घुटन' महसूस हो रही है। अग्निमित्र पॉल के लिए, भाजपा के साथ उनका पहला राजनीतिक कार्यकाल है। वह पिछले साल मार्च में पार्टी में शामिल हुई थीं, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के तहत अपने सामाजिक कार्य पहल के लिए वो पहले भी चर्चा में रही थीं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिला जेल कैदियों के लिए किए गए काम शामिल थे।

गांगुली की नियुक्ति पर, भाजपा के सूत्रों ने बताया, शुरू में वरिष्ठ नेताओं के एक समूह द्वारा विरोध किया गया था जिसने उनके सिनेमा के बैकग्राउंड को नुकसान के रूप में देखा था। सूत्रों ने कहा कि इस बारे में भी चर्चा हो रही थी कि राजनीति में उनका उदय इतनी जल्दी हुआ था। भले ही चटर्जी की महिला मोर्चा प्रमुख के रूप में नियुक्ति पार्टी कार्यकर्ता के रूप में दो साल के कार्यकाल के बाद हुई, लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि संगठन के भीतर इसका विरोध किया गया था। चटर्जी ने स्वीकार किया- 'एक अभिनेता के रूप में मेरे अतीत को लेकर खूब चर्चा की गई', जब वह पार्टी में शामिल हुईं थी। उन्होंने कहा- 'विरोधियों ने भी मुझे बदनाम करने का अभियान चलाया, लेकिन मैंने खुद पर विश्वास किया और अपना काम करना जारी रखा। मैंने वह सब कुछ छोड़ दिया जो फिल्म उद्योग में मेरे कैरियर से जुड़ा था। वो एक अलग ही दुनिया थी। लोगों ने सोचा कि मैं धूप में नहीं जा पाऊंगी, गर्मी और बारिश में काम नहीं कर पाऊंगी और धूल और पसीना भी नहीं सह पाऊंगी।' उन्होंने कहा, 'मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे फैंसी कपड़े, मेकअप जो मैं स्क्रीन पर करती थी। मैं अब उनका हिस्सा हूं और वे जानते हैं।'

पॉल ने कहा- चटर्जी जानती हैं कि उनकी नियुक्ति ने प्रतिरोध को आमंत्रित किया था। फैशन उद्योग में दो दशकों तक काम करने वाली पॉल ने कहा, 'मुझे पता है कि यह एक चुनौती है। मैं सिस्टम में नई हूं। लेकिन मेरे पास न तो कुछ हासिल करने के लिए है और न ही किसी से चोरी करने के लिए। मैं एक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से आती हूं। मैं सिर्फ लोगों के बीच काम करना चाहती हूं।' पॉल ने बताया, 'मेरी पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया है और वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया है। मोदीजी के कारण मैंने भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा की विचारधारा किसी भी अन्य पार्टी से थोड़ी अलग है, लेकिन मोदीजी ने मुझे प्रेरित किया।'

● **मधु आलोक निगम**

कड़ी मेहनत का परिणाम

2014 और 2016 के चुनावों के बाद, तृणमूल कांग्रेस के कई सदस्य भाजपा के साथ जुड़ गए। लेकिन लॉकेट ने इस पद तक पहुंचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। उन्होंने जिलों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। वो गांवों में गईं और लोगों के साथ रहीं, सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों का घेराव किया। 'वास्तव में उन्होंने सबसे मुश्किल संसदीय सीट हुगली में अकेले ही मुकाबला किया।' 2019 में, चटर्जी ने हुगली लोकसभा सीट पर लगभग 46 प्रतिशत मतों के साथ जीत हासिल की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रत्ना डे नाग को लगभग 74,000 मतों से हराया। चटर्जी ने कहा कि उनके तहत महिला मोर्चा लगभग 40,000 सदस्यों के संगठन के रूप में विकसित हुआ। चटर्जी द्वारा 2019 में चुनाव आयोग के समक्ष दायर किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार, वो 14 मामलों का सामना कर रही हैं, जिनमें 59 मामलों में हत्या, दंगा करने, विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, सरकारी सेवकों को बाधित करने, जिनमें से अधिकांश उनके महिला मोर्चा प्रमुख के कार्यकाल के दौरान हुआ कहा जा सकता है, भी शामिल है। पिछले एक साल में उन्होंने दावा किया कि यह संख्या बढ़कर 25 हो गई है।

गठबंधन में गांठ

महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में गांठ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ गठबंधन में शामिल तीनों पार्टियां एकता का राग अलापती हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर वार करने से भी नहीं चूकती हैं। अभी हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। संपादकीय में सामना ने कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और बाला साहेब थोरात को निशाने पर लिया है। संपादकीय में लिखा गया है कि 'कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन समय-समय पर पुरानी खटिया रह-रह कर कुरकुर की आवाज करती है।' सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, 'खटिया (कांग्रेस की) पुरानी है लेकिन इसकी ऐतिहासिक विरासत है। इस पुरानी खाट पर करवट बदलने वाले लोग भी बहुत हैं। इसलिए यह कुरकुर महसूस होने लगी है।'

सरकार को नसीहत देते हुए संपादकीय में लिखा गया है, 'मुख्यमंत्री ठाकरे को आघाड़ी सरकार में ऐसी कुरकुराहट को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात का कुरकुराना संयमित होता है। घर में भाई-भाई में झगड़ा होता है। यहां तो तीन दलों की सरकार है। थोड़ी बहुत तो कुरकुर होगी ही। मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे, थोरात ने ऐसा कहा।' संपादकीय में लिखा गया है, 'उसी खाट पर बैठे अशोक चव्हाण ने भी एक अखबार को साक्षात्कार दिया और उसी संयम से कुरकुराए, सरकार को कोई खतरा नहीं है लेकिन सरकार में हमारी बात सुनी जाए। प्रशासन के अधिकारी नौकरशाही विवाद पैदा कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे।' अब ऐसा तय हुआ कि कुरकुर की आवाज वाली खाट के दोनों मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कहने वाले हैं।

संपादकीय में आगे लिखा गया है, मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या कहना चाहती है। राजनीति की यह पुरानी खटिया क्यों कुरकुर की आवाज कर रही है? हमारी बात सुनो का मतलब क्या है? यह भी सामने आ गया है। थोरात और चव्हाण दिग्गज नेता हैं, जिन्हें सरकार चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह का दीर्घ अनुभव शरद पवार और उनकी पार्टी के लोगों को भी है। हालांकि वहां कुरकुर या कोई आहट नहीं दिख रही।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के खिलाफ सत्तारूढ़ महाविकास आघाडी (एमवीए) सरकार एकजुट होकर लड़ रही है और कांग्रेस और राकांपा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का पूर्ण समर्थन करती हैं। पवार ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि पिछले साल नवंबर में बनी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार यकीनन पांच साल पूरे करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर राज्य में तीनों दल एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वे एक बार फिर सरकार भी बनाएंगे।

वरिष्ठ नेता ने महाविकास अघाडी (एमवीए) को नियंत्रित करने की खबरों को खारिज कर दिया। गठबंधन सरकार में उनकी पार्टी के पास दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीटें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में कोविड-19 की स्थिति गंभीर थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार आया है। पवार ने चैनल से कहा कि उनमें (पार्टियों में) कोई मतभेद नहीं है। सभी दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और राकांपा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व का पूरा समर्थन कर रहे हैं और जो भी काम किया जाए उसमें आपसी समझ होती है। एमवीए शासन को नियंत्रित करने के आरोपों को खारिज करते हुए पवार ने कहा कि सरकार पूरी तरह ठाकरे और उनकी टीम द्वारा चलाई जा रही है। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि तीनों दल एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं और वह निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते।

गठबंधन की राजनीति महाराष्ट्र और देश के लिए कोई अजूबा नहीं है। वर्ष 1967 में देश के अनेक हिस्सों में बनी संयुक्त विधायक दल (संविद) सरकार, 1978 में शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र में बनाई गई पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) सरकार, जनता पार्टी, जनता दल, बसपा-सपा गठबंधन, भाजपा-शिवसेना गठबंधन, महागठबंधन आदि गठबंधनों की राजनीति भारत लंबे समय से देखता आ रहा है। किसी मजबूत सत्तारूढ़ दल को हटाने के लिए ऐसे गठबंधनों का बनना स्वाभाविक भी है। केंद्र में गठबंधन सरकारों के कई सफल दौर भी देश ने देखे हैं। माया, ममता और जयललिता के अनेक झंझटों के बीच कभी गठबंधन सरकारें चली हैं, तो कभी गिरी हैं। ये राजनीतिक गठबंधन कभी चुनाव पूर्व होते रहे हैं, तो कभी चुनाव बाद।

● **मुंबई से बिन्दु माथुर**

दो साल पहले राकांपा से होने वाला था गठबंधन

भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि राकांपा दो साल पहले भाजपा से हाथ मिलना चाहती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह समय महाराष्ट्र में सरकार गिराने या बदलने का नहीं है क्योंकि राज्य कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है। पुणे में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि दो साल पहले शरद पवार नीत राकांपा, भाजपा नीत महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बनना चाहती थी। उन्होंने कहा, 'यह समय सरकार का मूल्यांकन करने का नहीं है। यह समय सवाल खड़े (कोविड-19 महामारी के दौरान प्रबंधन के संदर्भ में) करने का है, यह समय खामियों को बताने का है।' फडणवीस ने कहा, 'यह समय कमियों के आधार पर सरकार का मूल्यांकन करने का नहीं है। यह समय यह कहने का नहीं है कि मुख्यमंत्री बदलो या इस सरकार की जरूरत नहीं है।' उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते भाजपा शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा सरकार की कमियों को रेखांकित कर रही है।

नीतीश मार पाएंगे मैदान

इस समय बिहार की राजनीति में चुनावी रंग धीरे-धीरे घुल रहा है। हर राजनीतिक पार्टी की कोशिश यही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह मैदान मारे। लेकिन सबकी नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। क्योंकि अगर सबकुछ ठीक रहा तो वे चौथी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 100 दिन शेष हैं और मुख्यमंत्री ने खुद को वर्चुअल और फिजिकल दुनिया के अनुकूल बना लिया है। 12 जून तक नीतीश ने अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की 6 दिवसीय मैराथन वर्चुअल कांफ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य के 38 जिलों के 16,000 बूथ लेवल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हमने 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव अपने सुशासन की शक्ति के बल पर जीते। 2020 में भी हम यही करने जा रहे हैं।

जिन लोगों ने इस कांफ्रेंस में भाग लिया उनके मुताबिक, नीतीश आत्मविश्वास से भरे थे और उनमें जरा भी आशंका नहीं थी। उन्होंने जरूरी तौर पर तीन काम किए हैं, जिनमें वापस लौटे प्रवासियों की मदद के लिए उठाए गए कदम, कोरोनावायरस से राज्य पर आ पड़ी इंसानी त्रासदी पर चर्चा और आने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा। उन्होंने कहा कि चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। नीतीश चाहते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएं कि किस नवंबर 2005 में सत्ता में आने के बाद से किस तरह बिहार में बदलाव की इबारत लिखी गई, किस तरह लॉकडाउन के दौरान 8,538 करोड़ रुपए बेहद जरूरतमंद लोगों पर खर्च हुए और विपक्ष के नकारात्मक प्रचार को तथ्यों के दम पर बेदम किया।

जल संसाधन राज्यमंत्री संजय झा कहते हैं, 'हमें याद रखना चाहिए कि जब नीतीश ने पहली बार सत्ता संभाली थी तब बिहार की दशा कैसी थी। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया ने बिहार से उम्मीद छोड़ दी है। अब लोगों में उम्मीदें जगी है क्योंकि वे जानते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कर सकने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी, भवन और निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ये समझाते हैं कि आखिर क्यों एनडीए सरकार की स्थिति मजबूत है। वे कहते हैं, 'जब कोरोना संकट बिहार पहुंचा तो सबसे पहला धक्का प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थाओं से लगा कि उन्होंने अपनी सेवाएं बंद कीं। सोशल सेक्टर मोटे तौर पर मौन था और राजनेता भी लॉकडाउन की वजह से घरों के भीतर रहने को बाध्य थे। केवल राज्य सरकार थी जिसका प्रतिनिधित्व करते हुए- डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी और लोकसेवक फील्ड में थे और इनका साथ सक्रियता से मुख्यमंत्री दे रहे थे। हमने कोरोनावायरस से पहली बार मुकाबला किया है। अब लोगों को दोबारा भरोसा, स्थायित्व और विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे।

सचमुच 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल की जदयू के हाथों हार के बाद से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के मुख्य बिंदु बन गए हैं। तब से 2019 के आम चुनाव तक बिहार ने चार विधानसभा और तीन लोकसभा चुनाव देखे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो नीतीश हमेशा जीतने वाले के पाले में ही रहे हैं। संयोगवश नीतीश ने बतौर मुख्यमंत्री अपना 5,000 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाले वे दूसरे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिन्हा 5,419 दिनों तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे थे।

नीतीश के विकास के अफसाने के अलावा जदयू की चुनावी रणनीति हमेशा ही विकास के साथ वंचित तबके के लिए लक्षित सामाजिक कल्याण की योजनाओं को साथ मिलाकर चलने की रही है। इसी वजह से वे लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम-यादव-दलित वोट बेस के साथ भाजपा के शहरी मध्यवर्ग और ऊंची जातियों वाले क्षेत्रों में आगे निकल सके। ईबीसी (अति पिछड़े वर्ग) में 113 अधिसूचित जातियां हैं जो कि बिहार के वोटरों का 30 फीसदी हैं। इनमें बिंद, मल्लाह, निषाद, चंद्रवंशी और नोना प्रमुख जातियां हैं। करीब 25 अधिसूचित जातियां मुस्लिम समुदाय से हैं और वे हिंदुओं की तरह ही योजनाओं का लाभ लेने की हकदार हैं।

विडंबना है कि विपक्ष की सारी चुनौती 2020 में भी न दिखने वाली सत्ता विरोधी लहर पर निर्भर है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता कहते हैं, 'अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो एनडीए ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 225 में बढ़त हासिल की थी। वोटों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों गठबंधनों के बीच 92 लाख वोटों का अंतर एनडीए के पक्ष में था। अगर हम इसमें से 100 सीटें भी हार जाएं, जो कि संभव नहीं है, तब भी अगली सरकार हमारी ही बनेगी।'

● **विनोद बक्सरी**

महागठबंधन की दरार सुशासन बाबू के लिए शुभ संकेत

विपक्ष के महागठबंधन में दरार दिखने लगी है। मांझी ने 15 जून को पटना में प्रेस कांफ्रेंस कर गठबंधन नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक समन्वय समिति बनाने की मांग करते हुए तेजस्वी को बिहार में अपना नेता मानने से इंकार कर दिया है। वहीं महागठबंधन में शामिल अन्य पार्टियां भी अलग-थलग पड़ रही हैं। अगर नीतीश को ज्यादा चुनौती मिलने की उम्मीद नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ जदयू-भाजपा का बिहार में मजबूत गठबंधन नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राजद की यहां पर भाजपा की तरह ध्रुवीकरण वाली मौजूदगी है। पार्टी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पा रही जो कि अराजकता वाले युग की याद दिलाता है। पार्टी प्रमुख तेजस्वी यादव अक्टूबर में चुनाव में जाने से पहले अपनी छवि में कोई बदलाव नहीं कर सके हैं।

चीन का नया मोहरा बांग्लादेश

दक्षिण एशिया वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन, सौदेबाजी और गुटबंदी के दौर से गुजर रहा है। इसी क्रम में चीन ने हाल ही में बांग्लादेश को व्यापारिक प्रलोभनों से लुभाने की कोशिश की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि मत्स्य संसाधन और लेदर उत्पादों जैसे अन्य 97 प्रतिशत बांग्लादेशी उत्पादों पर चीन द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 97 प्रतिशत बांग्लादेशी निर्यात को चीन द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ से छूट मिलेगी। इसे ढाका और बीजिंग के संबंधों में बड़ी सफलता माना जा रहा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि इस समझौते का विरोध करने वाले और इसे अल्प विकसित बांग्लादेश के लिए खैरात जैसी शब्दावली प्रयुक्त करने वाले संकीर्ण मानसिकता के हैं।

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन लद्दाख जैसे अन्य मुद्दों पर बांग्लादेश को अपने साथ खड़ा करना चाहता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चीन दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देशों को ऐसे लुभावने व्यापारिक प्रस्ताव देकर भारत के साथ एक अप्रत्यक्ष और अघोषित व्यापारिक युद्ध में लगे रहना चाहता है। ऐसे समय में जब भारत के जनमानस के साथ-साथ आर्थिक व सामरिक विशेषज्ञों ने भारत को चीनी उत्पादों के आर्थिक बहिष्कार का सुझाव दिया है, ऐसे में दक्षिण एशिया में एक आर्थिक बढ़त लेने और उससे भी बड़ी बात दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रयासों विशेषकर दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) को असफल बनाने की मंशा के साथ चीन व्यक्तिगत स्तर पर दक्षिण एशिया के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की राह पर चलना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान और मालदीव के बाद अब बांग्लादेश के तीसरे ऐसे दक्षिण एशियाई देश बनने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता जिसके साथ चीन मुक्त व्यापार समझौते की राह पर चल पड़ा है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत 2011 से ही साफ्टा के तहत बांग्लादेशी उत्पादों को (केवल तंबाकू व अल्कोहल छोड़कर) शुल्क मुक्त बाजार पहुंच दे रहा है और हाल के वर्षों में दोनों देशों की सरकारों ने मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र ही मूर्तमान स्वरूप प्रदान करने पर पारस्परिक सहमति भी बनाई है। इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत की आर्थिक संलग्नता को चीन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कुछ दिनों पहले चीन ने अपने फायदे के लिए वन बेल्ट रोड पहल से दुनियाभर के देशों के साथ गुटबाजी की है। चीन ने नेपाल के सामने यह प्रस्ताव भी रखा कि वह अपने स्कूलों में चीनी मंदारिन भाषा पढ़ाना अनिवार्य बना दे और इसे पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन चीन देगा। ऐसे में यह कयास लगाना स्वाभाविक है कि कहीं चीन की मंशा नेपाल और बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों को दूसरा पाकिस्तान तो बनाने की नहीं है। एलायंस, नेटवर्क, ग्रिड बनाना गलत नहीं है, पर चीन का मकसद गलत है।

भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में व्यापारिक संबंधों को विशेष तरजीह दी है और चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को ऊंचाई देने के लिए जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है उनमें वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, बांग्लादेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, विकासात्मक साझेदारी को मजबूती देना, ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर देना शामिल हैं। दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

भारत और बांग्लादेश में द्विपक्षीय स्तर पर कई ऊर्जा परियोजनाओं को भी चलाया जा रहा है जो आर्थिक के साथ ही सामरिक महत्व के भी हैं। भारत के एनटीपीसी के सहयोग से बांग्लादेश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। इसे बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया गया है। यह तापीय विद्युत स्टेशन बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र में लगाया गया है। इसके साथ 1,320 मेगावॉट का रामपाल कोयला चालित विद्युत स्टेशन भी बांग्लादेश में दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच गहरा संबंध है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सभी को बिजली पहुंचाने की राह होगी आसान

बांग्लादेश ने 2021 तक इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे पूरा करने में उसे भारत से लगातार मदद मिल रही है। बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा में भारत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यह काम शुरू भी हो चुका है। सीमा पार ऊर्जा व्यापार भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। बांग्लादेश को भारत की दक्षिण एशिया आधारित पड़ोसी प्रथम की नीति, उसकी ऊर्जा कूटनीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है। सितंबर 2019 में बांग्लादेश ने भारत के रिलायंस पावर के साथ 718 मेगावॉट बिजली खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत अगले 22 वर्षों तक बांग्लादेश इससे बिजली खरीदेगा। 2019 में ही भारत ने बांग्लादेश के साथ एलपीजी खरीदने का समझौता भी किया। इस प्रकार दोनों देश ऊर्जा संबंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के अक्षय ऊर्जा उद्योग से बांग्लादेश लाभान्वित हो सकता है। बांग्लादेश ने सौर ऊर्जा में भी रुचि प्रदर्शित की है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख निकाय अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने बांग्लादेश के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता किया है। इसके तहत विश्व बैंक बांग्लादेश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इससे भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए बड़ी संभावना विद्यमान है।

नहीं चलेगी चीन की दादागीरी

कोरोना महामारी के बीच चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारतीय सैनिकों को जिस तरह छल से निशाना बनाया उससे यह साफ है कि उसके इरादे खतरनाक हैं। बीते कुछ दिनों में चीनी सेना ने लद्दाख के साथ सिक्किम में भी भारतीय सीमा में छेड़छाड़ की जो कोशिश की वह महज दुर्योग नहीं हो सकती। चीन भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करने की कोशिश जानबूझकर कर रहा है, यह इससे पता चलता है कि उसने एलएसी पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनी सहमति का उल्लंघन किया। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चीनी सेना ने योजनाबद्ध तरीके से भारतीय सैनिकों पर हमला किया।

चीन के हमलावर रुख के पीछे कई कारण नजर आते हैं। एक तो यह कि वह कोरोना वायरस फैलाने में अपनी संदिग्ध भूमिका से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। इस वायरस के संक्रमण से न केवल लाखों लोग मारे गए हैं, बल्कि दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में भी आ गई है। कई विकसित देश उसे आड़े हाथ ले रहे हैं। चीन को लगता है कि भारत उसके खिलाफ विकसित देशों संग खड़ा हो रहा है। ध्यान रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल में जहां चीन को कठघरे में खड़ा किया वहीं भारतीय प्रधानमंत्री को जी-7 सम्मेलन में निमंत्रित किया।

चीन से त्रस्त ऑस्ट्रेलिया भी भारत से अपनी निकटता बढ़ा रहा है। चीन की दादागीरी से परेशान जापान पहले से ही भारत के साथ है। चीन इससे भी सहमा है कि क्वॉड के जरिए भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर उसकी घेरेबंदी कर रहा है, लेकिन गलवान में उसकी हरकत से तो भारत इस गठबंधन को मजबूती देना ही पसंद करेगा। अब यह किसी से छिपा नहीं कि विकसित देशों की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और इन कंपनियों के लिए भारत नया ठिकाना बन सकता है। जाहिर है चीन को यह रास नहीं आ रहा है। वह अपनी आदत के मुताबिक विवादों को बातचीत से सुलझाने के बजाय आक्रामकता दिखा रहा है, लेकिन आज के युग में उसका यह रवैया काम आने वाला नहीं है।

चीन इसे लेकर भी परेशान दिख रहा कि भारत दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। बीते छह साल में मोदी सरकार ने चीन से लगती सीमा पर आधारभूत ढांचे के निर्माण में न केवल खासी तेजी दिखाई है, बल्कि यह भी साफ किया है कि यह काम उसकी प्राथमिकता में शामिल है। चीन भारत के साथ अपने अन्य पड़ोसी देशों को जिस तरह तंग कर रहा उससे यही लगता है कि वह विश्व को यह बताना चाह रहा है कि कोविड-19 महामारी को लेकर वह कठघरे में खड़ा होना स्वीकार नहीं करेगा। वह भारत को तंग करके विकसित देशों को यह संदेश भी देना चाह रहा है कि इस देश में निवेश करना ठीक नहीं होगा।

अगर भारत भी अन्य सीमा क्षेत्रों में वैसा ही करे जैसा चीन ने किया है तो चीन को भी अपनी सेनाएं लाकर उसी तरह बैठानी पड़ेंगी जैसे आज गलवान में भारतीय सेना बैठ गई है। युद्ध से चीन को कोई लाभ नहीं होना है, क्योंकि जो अक्साई चिन और वहां से होकर जा रही सिंकियांग-तिब्बत रोड उसे चाहिए थी वह तो उसके कब्जे में 1962 से ही है। चीन की प्रतिक्रिया का एक और महत्वपूर्ण कारण है पीओके से गुजरती हुई बेल्ट रोड इनीशिएटिव योजना के तहत बनी काशगर ग्वादर रोड की असुरक्षा। गुलाम कश्मीर पर भारत की आक्रामक नीति के परिणामस्वरूप उसे इसकी आशंका हो सकती है कि भारत अपने इस क्षेत्र को वापस लेने की सैन्य तैयारियां कर रहा है। इससे चीन का यह महत्वपूर्ण रणनीतिक मार्ग बाधित ही नहीं, निष्प्रयोज्य हो जाएगा। इसी कारण चीन ने सुरक्षा परिषद में अनुच्छेद-370 के समापन को मुद्दा बनाने की असफल कोशिश की। चीनी इससे सशंकित भी है कि भारत अमेरिकी योजना का हिस्सा बन रहा है।

भारत को अमेरिका के साथ जाने के क्या परिणाम होंगे, यह बताने के लिए ही शायद चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद को आधार बनाया है। चीन भारत पर वुहान भावना के विरूद्ध जाने का आरोप लगाता है, लेकिन वुहान भावना का प्रदर्शन एकतरफा नहीं हो सकता। चीन अनुच्छेद-370 और पीओके पर भारत के पक्ष को समझने को तैयार नहीं है। जब भी सीमाओं के चिन्हीकरण की बात आई है वह लगातार टालता ही रहा है। व्यापार में असंतुलन को दूर करने के प्रति भी उसका कोई सकारात्मक रुख नहीं रहा। चीनी-पाकिस्तानी रणनीतिक साझेदारी में कोई कमी नहीं है। भारत को घेरने की चीन की समुद्री नीति भी कहीं से ढीली नहीं पड़ी है। भारत के लिए यह निर्णायक समय है। हिमालय की सरहदों की रक्षा अब भारत की अकेली लड़ाई नहीं रह गई है। आज विश्व चीन की यह असलियत जान चुका है कि वह अपने वर्चस्व के लिए कुछ भी कर सकता है। निरंकुशता की ओर बढ़ रही चीनी शक्ति को नियंत्रित करने के वैश्विक दायित्व का निर्वहन आवश्यक हो गया है।

● **कुमार विनोद**

भारत की बदल रही रणनीतिक धारणा

सीमा पर समस्या खड़ी कर देने के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि प्रश्नगत क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे रक्षा निर्माण कार्यों के विरूद्ध सीमा नियंत्रण की कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां सड़कों-पुलों का निर्माण तो पहले से ही चल रहा है। दरअसल विवाद का लक्ष्य लद्दाख की सड़कें नहीं, बल्कि भारत की बदल रही रणनीतिक धारणा है। 1993 और उसके बाद के समझौतों में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई थी, लेकिन भारतीय प्रयासों के बावजूद चीन युद्धविराम रेखा के चिन्हीकरण पर सहमत नहीं हुआ। सीमा रेखा पर एक चौड़े से क्षेत्र को आभासी सीमा क्षेत्र मान लिया गया जिसमें दोनों पक्ष गश्त करते हैं। इस क्षेत्र में आगे अधिक बढ़ने पर दूसरा पक्ष विरोध करता है, लेकिन अपनी ताजा हरकत से चीन ने सैन्य पेट्रोलिंग के क्षेत्र बाधित कर दिए हैं। इस तरह चीन ने 1993 के समझौते से विकसित हुई आपसी समझ को तिलांजलि दे दी है। चीन सीमाओं के चिन्हांकन से इसीलिए बचता है ताकि विवाद की स्थितियां पैदा कर सके, लेकिन पाकिस्तान को भारत के समानांतर ला खड़े करने वाला चीन अब यह देख रहा है कि डोकलाम के बाद नए भारत की सोच बदल चुकी है।

अक्सर किसी अकेली लड़की या महिला को देखकर लोग उसके बारे में अलग-अलग धारणाएं व्यक्त करते हैं। जबकि एकांकी में रहने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से काफी मजबूत रहता है। इसलिए कभी भी ऐसी महिलाओं के प्रति गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यह भी जीवन जीने की एक कला है।

अकेले हैं तो क्या गम है...

समय बदल रहा है! बदल रहा है जीने का तरीका और सोच। इस बदलते समय और सोच ने कई लड़कियों को जीने का नया ढंग सिखाया है, नए पहलुओं से अवगत कराया है और नया लक्ष्य भी दिया है। यही वजह है कि लड़कियों ने इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ शादी नहीं है बल्कि जीवन इससे कहीं ज्यादा है। अकेले रहने के अपने मजे हैं और लाभ भी। शादी से पहले अपने कैरियर पर ध्यान देना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है, दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती करनी होती है, घूमना होता है और भी बहुत कुछ। अकेली लड़की के जीवन में कई मजे हैं, कई फायदे हैं, जिन्हें सिर्फ वही समझ सकती है जो अकेली हो।

अकेली लड़कियों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने तक ही होती है। चाहे देर रात की पार्टी में जाना हो या फिर दफ्तर में देर तक रुककर काम करना हो, उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि घर पर काम कैसे होगा, खाना कौन बनाएगा या फिर बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। अकेले होने का एक फायदा यह भी है कि अगर आपको देर रात तक जागना है या फिर सुबह देर तक सोना है या फिर घर के काम को किनारे कर पूरा दिन आराम करना है तो ऐसे में किसी का डर नहीं होता कि कौन क्या कहेगा? हो सकता है कि अकेली लड़की को कभी-कभीर ऐसा लगता हो कि वह खाली समय में बोर हो रही है लेकिन वह समय भी तो अपना और अपने लिए ही होता है।

अकेली लड़कियां अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च करने के अलावा किसी भी तरह और कहीं भी खर्च कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें न तो किसी को जवाब देना होता है, न ही पूछना। नृत्य सीखना हो या फिर खूब सारी खरीदारी करना हो या फिर पास या दूर के दोस्तों को महंगा या फिर सस्ता उपहार देना हो या फिर किसी जरूरतमंद की मदद ही क्यों न करना हो, जवाबदेही सिर्फ अपनी है। कहने का मतलब है कि पैसे आपके हैं इसलिए आप जो चाहे इन पैसों का कर सकती हो।

लड़कियों की खुद की पहचान कहां होती है! लड़कियों को उनके परिवार के जरिए ही जाना जाता है। जन्म से उनकी पहचान किसी की बेटी तो शादी के बाद पति की पहचान ही उसकी पहचान बन जाती है। कोई उन्हें फलां की बेटी तो कोई बहू, तो कोई बहन या पत्नी कहकर बुलाता है। लेकिन अकेली कामकाजी होने का फायदा यह है कि समाज उन्हें उनके नाम से ही जानता है। ऐसे में उन्हें खुद को नए सिरे से जानने का मौका मिलता है कि उनकी जिंदगी किस तरह चल रही है? उन्हें किस बात से खुशी मिलती है और किस बात से नहीं? उन्हें अपने लक्ष्य, सपने और जीवन के मुद्दों को समझने का मौका मिलता है। जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए ये सारे बेहद जरूरी सवाल हैं, जिनका जवाब जानना भी बहुत आवश्यक है।

अकेले रहने के कारण वह खुद को बेहतर ढंग से समझ पाती है और इस बात को भी कि उसे किस तरह का जीवनसाथी चाहिए, चाहिए भी या नहीं। खुद पर भरोसा करने और असुरक्षा को दूर करने के लिए भी उनका अकेली रहना फायदेमंद है। जब आप अकेले रहते हैं तो खुद ही सारा काम करने का मौका मिलता है, चाहे कार की सर्विसिंग करानी हो या फिर घर की मरम्मत। कहने का मतलब यह है कि अपनी काबिलियत को अकेले रहने पर ही बेहतरी से समझा जा सकता है।

कई लड़कियां ऐसा कहती हैं कि सिंगल रहने के दौरान जो उनके दोस्त हैं, शादी के बाद भी वे गहरे दोस्त ही रहें। कारण कि अकेली लड़कियों से दोस्ती करना एक-दूसरे पर निर्भर रहने और मजबूत रिश्ते बनाने की कड़ी है। अमूमन देखा जाता है कि महिलाएं एक-दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं लेकिन जब कोई लड़की या महिला अकेली रहती है तो दूसरी महिला से उसके रिश्ते बहन या जान से भी प्यारे दोस्त जैसे बन जाते हैं।

जल्दी शादी हो जाने का अर्थ है कि जीवन में नया परिवार ही प्राथमिकता में रहता है। इस तरह से आपको अपने माता-पिता, भाई-बहनों को सही तरह से समझने और उनकी मदद करने का मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन एक अकेली महिला के तौर पर आपको अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलता है। उन्हें अपनी नजर से समझने का नजरिया भी मिलता है, जो बचपन में संभव नहीं था।

कैसी नौकरी करनी है, नौकरी एक बार बदलना है या फिर दस बार, उन्हें अपने कैरियर को लेकर हर तरह की आजादी मिली हुई होती है। अकेले होने पर अपने कैरियर का चुनाव अपनी मर्जी से किया जा सकता है, जो कि शादी के बाद कम ही संभव है। पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना हो या कैरियर के लिए, इसके लिए उन्हें किसी और के निर्णय की परवाह नहीं करनी होती है। नौकरी छोड़कर पढ़ाई करनी है या फिर घर से ही काम करना है, उन्हें इसमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

घूमने की आजादी

अकेली लड़की जहां चाहे वहां घूमने जा सकती है। वीकेंड हो या वीकडेज, उनकी अपनी मर्जी चलती है, जहां मन हो वे वहां जाएं। घूमने जाने के लिए उन्हें किसी से पूछना नहीं केवल बताना होता है। यही वह समय है, जब नई जगहों पर घूमकर जिंदगी के नए अनुभव बनाए जाते हैं।

जेहि का जेहि पर सत्य सनेहू

रामचरितमानस में एक स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, 'जेहि का जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहिं न कछु संदेहू।' अर्थात् जिसको जिस चीज से सच्चा प्रेम होता है उसे वह चीज अवश्य मिल जाती है। यानी सच्चे मन से चाही गई वस्तु अवश्य प्राप्त होती है।

प्रभु पाने का सबसे बड़ा आधार है प्रेम। प्रेम से हम किसी को पा सकते हैं, अपना बना सकते हैं। इस बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि हम जो चीज पाना चाहते हैं उसे मन की गहराई से अथवा सच्चे मन से चाहें। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज को चाहेंगे तो वह अवश्य ही उपलब्ध हो जाएगी। प्रेम सच्चा हो तो मिलन में देर नहीं लगती। हमारी सच्ची चाहत ही वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को आकर्षित कर उन्हें सुलभ बनाती है। उत्तम स्वास्थ्य अथवा प्रसन्नता भी इसका अपवाद नहीं।

यदि हम अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता की कामना करेंगे तो परिस्थितियां अच्छे स्वास्थ्य व प्रसन्नता के अनुकूल होकर हमारी इच्छापूर्ति में सहायक हो जाएंगी। कहा गया है कि शक्करखोरे को शक्कर और टक्करखोरे को टक्कर मिलती है। हम जो कुछ खाना पसंद करते हैं वही बाजार से खरीदकर लाते हैं। जो खरीदकर लाते हैं उसकी स्पष्ट छवि पहले से ही मन में निर्मित कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो गलत चीज की खरीदारी की संभावना बढ़ जाती है। हम शक्करखोरे बनने की कामना करें न कि टक्करखोरे बनने की। यही चयन हमारी नियति निर्धारित कर हमें योग्य-अयोग्य अथवा सफल-असफल बनाता है। जर्मन भाषी चेक लेखक फ्रांज काफ्का भी लिखते हैं कि उस चीज में शिद्दत से यकीन करना जो है नहीं, पर जिसे बनाना है। सिर्फ वही चीजें नहीं बन पातीं जिन्हें हम शिद्दत से नहीं चाहते।

जिस प्रकार अच्छी फसल पाने के लिए उत्तम किस्म का बीज बोना अनिवार्य शर्त है, उसी तरह अन्य कुछ भी पाने के लिए उस चीज की मजबूत चाहत, यानी मन में दृढ़ इच्छा का बीजारोपण भी अनिवार्य है। जब हम कोई बीज बो देते हैं तो उससे पेड़ उगना स्वाभाविक है। बीज बो देने के बाद उसे उगने से रोकना असंभव है। बिल्कुल इसी तरह से विचार रूपी बीज को वास्तविकता में परिवर्तित होने से रोकना भी असंभव है। यदि किसी भी तरह से अच्छे विचार रूपी बीजों का मन में रोपण कर दें तो उसके परिणाम को कोई नहीं रोक पाएगा। स्पष्ट है कि जैसी चाहत होगी वैसी ही उपलब्धि होगी। जीवन को संवारना है तो अच्छी सोच अथवा शुभ संकल्प अनिवार्य हैं। तभी तो कामना की गई है कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो।

यदि हमारी इच्छाएं सात्विक नहीं हैं तो परिणाम भी सात्विक नहीं होंगे। हम स्वयं के अच्छे होने का संकल्प कर लें तो हमारे अच्छे होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इच्छाएं ही हमारा जीवन है, इच्छाओं से ही हमारे व्यक्तित्व का विकास है और इच्छाओं से ही समाज का निर्माण है। जो भी ये कहते हैं कि इच्छाएं जीवन में परेशानी का कारण बनती हैं, गलत कहते हैं। गलत इच्छाएं जीवन में परेशानी का कारण बनती हैं न कि इच्छाएं। जीवन को संवारना है तो इच्छाओं को संवारना होगा। अस्वस्थ भावों का त्याग करना होगा तथा स्वस्थ भावधारा का चुनाव या निर्माण कर उसे पोषित करना होगा। उसे दूसरे दूषित भाव-बीजों से रक्षित करना होगा।

पौराणिक कथाओं और उनकी सीख को आज के वक्त के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। हम इन कहानियों को पढ़कर पाएंगे कि कलियुग में भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसी कई बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आज के युग में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ईश्वर होता है। एक दिन स्वामी नरहरिदास उनके गांव आए। उन्होंने ही तुलसी को आगे के जीवन की राह दिखाई। यह भेंट उनके लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हो गई। कवि तुलसी ने रामकथा को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने का माध्यम बना लिया। उन्होंने रामकथा में न केवल सुखद समाज की कल्पना की, बल्कि आदर्श जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया।

तुलसी ने गंगा को करुणा, सत्य, प्रेम और मनुष्यता की धाराओं में वर्गीकृत किया, जिनमें अवगाहन कर कोई भी व्यक्ति अपने आचरण को गंगा की तरह पवित्र कर सकता है। उन्होंने मनुष्य के संस्कार की कथा लिखकर रामकाव्य को संस्कृति का प्राण तत्व बना दिया। कविता का उद्देश्य लोक मंगल मानकर विपरीत परिस्थिति को तप माना। भाव भक्ति के साथ कर्म का संगम होने पर विद्या और ज्ञान स्वयं आने लगते हैं। तुलसी के राम सब में रमते हैं। वे नैतिकता, मानवता कर्म, त्याग द्वारा लोकमंगल की स्थापना करने का प्रयास करते हैं।

रामचरितमानस के अलावा, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामलला नहछू आदि अनेक कृतियां रचीं। अनेक चौपाइयां सूक्ति बन गई हैं। तुलसी ने सत्य और परोपकार को सबसे बड़ा धर्म और त्याग को जीवन का मंत्र माना। मानव-तन को सही अर्थों में मनुष्य बनाना मानवता की सार्थकता है। भरत का त्याग, राम की करुणा, जटायू का परहित, शबरी-केवट प्रेम, हनुमान की भक्ति, सुमति जैसे शाश्वत लोकमूल्यों के माध्यम से उन्होंने विषम समस्याओं का समाधान किया। कर्म को सकारात्मक, भाग्य को नकारात्मक मानते हुए असत्य, पाखंड, ढोंग में डूबे समाज को जगाया।

● **ओम**

हिन्दी टीचर

गौरी मैडम के क्लास में आते ही सब बच्चों के मुंह लटक जाते।

लो आ गई अपने भारी भरकम शब्दों के साथ हिन्दी पढ़ाने।

हिन्दी न हो गई, जी का जंजाल हो गई, गौरी गुस्से में बड़बड़ाते हुए क्लास से बाहर आ गई।

क्या हुआ गौरी? इतनीं परेशान क्यों हो, आज फिर बच्चों ने हिन्दी के पीरियड में तुम्हें परेशान किया? प्रतिभा मेम ने सवालों की झड़ी लगा दी।

क्या करूं प्रतिभा मेम, मैं तो इन बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करती हूं पर इनको हिन्दी विषय से न जाने क्या एलर्जी है कि पढ़ना तो दूर एक शब्द भी नहीं लिखते।

उन्हें कैसे बताऊं कि हर विषय की तरह हिन्दी विषय भी महत्वपूर्ण है।

स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, रस, छंद, अलंकार, दोहा, रोला, सोरठा, व्याकरण आदि के बिना हिन्दी पढ़ और समझ नहीं सकते।

पर बच्चे तो इसे बोरिंग सब्जेक्ट मानकर पढ़ना ही नहीं चाहते।

और तो और अगर कोई पाठ पढ़ाऊं तो बोलते हैं कि आप इतने कठिन शब्द क्यों बोलती हो जो हमें समझ नहीं आते।

हमारी भावी पीढ़ी के बच्चे ही हमारी मातृभाषा को पढ़ना और समझना नहीं चाहते। अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करके गौरी मैडम स्टाफ रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी।

– सपना परिहार

दर्द अब हद से

दर्द अब हद से गुजरता जा रहा है।
जख्म भी रूह में उतरता जा रहा है।।
सामने बैठा था तब
तक कुछ नही था।
बाद तेरे तू बहुत याद आ रहा है।।
तेरे कुछ कहने की जरूरत ही कहां।
चेहरा हाल-ए-तिश्नगी
बतला रहा है।।
बिगड़े हुए मौसम से डरो न तुम ये।
अंदाज-ए-मौसीकी
मुझे सिखला रहा है।।
हर बार और हर बात
में बस तू ही तू।
क्यों इतना लाजिमी सा
हुआ जा रहा है।।
है शौक के संग अतिशों
का डर भी 'लहर'।
वो दूर से ही हाथ सेके जा रहा है।।

नींद से बोझिल

नींद से बोझिल तर आंखों में।
सपना कोई धर आंखों में।।
उसे ठिकाना मिला न कोई।
आ बैठा हंसकर आंखों में।।
गुजर गया है वक्त तो देखो।
छोड़ गया मंजर आंखों में।।
कोई छवि तो उभरी होगी।
इन सूखी बंजर आंखों में।।
ज्यूं ही पलकें पलभर झपकें।
चमक उठी झांझर आंखों में।।
जब भी देखूं यहीं दिखे वो।
बना लिया क्या घर आंखों में।।

-डॉ. मीनाक्षी शर्मा

संस्कारों की जीत

शीला दी, आपने तो कमाल कर दिया। सारी सोसाइटी में आपकी ही चर्चा हो रही है।

वह अतीत में खो गई। उसे आज भी अपनी शादी का दिन याद हैं। जब उसने इस सोसाइटी में कदम रखा था। सभी ने उसे देखकर नकार दिया था। वह किसी को पसंद नहीं आई थी। पर उनकी भी क्या गलती थी। हर कोई चाहता है, उसकी बहू पढ़ी-लिखी हो, सुंदर हो।

मैं ना तो पढ़ी-लिखी थी और सुंदरता तो मुझसे कोसों दूर थी। रंग मेरा बहुत काला था, पढ़ना मुझे पसंद नहीं था। बस मेरी सास को मैं पसंद थीं। क्यूं?

मैं अपनी मां के पास जाकर रोया करती थी। तुमने मेरी शादी कहां कर दी। वहां मेरा कोई सम्मान नहीं हैं। पति मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते।

बेटी मान-सम्मान रंग-रूप से नहीं मिलता, ना ही अधिक पढ़ी-लिखी होने से मिलता हैं। मां फिर मान-सम्मान कैसे मिलता हैं? संस्कारों से। ठीक है मां।

उस दिन के बाद मैंने सास-ससुर की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे-धीरे सब कुछ बदलने लगा। मेरे संस्कारों ने मुझे सब कुछ दिला दिया। इसलिए मेरी सोसाइटी मुझे सम्मानित कर रही थी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, शीला मेरी बेटी बधाई हो। मां तुम।

- राकेश कुमार तगाला

सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से एक बहस फिर उठ खड़ी हुई है कि क्या बाहर से आए लोगों या टीवी में काम कर रहे स्टार्स को बॉलीवुड का रुख करना चाहिए या नहीं? इस बारे में टीवी से ही फिल्मों में धीरे-धीरे पैर जमाती जा रहीं ऐक्ट्रेस राधिका मदान ने खुलकर बात की है।

मैं लोगों को सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण देती थीः राधिका

उन्होंने टीवी एक्टर्स को प्रेरित किया...विशाल भारद्वाज की फिल्म पटाखा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली राधिका ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने टीवी में काम करने वाले सभी ऐक्टर्स को प्रेरित किया। राधिका ने कहा कि सुशांत की कामयाबी को देखते हुए ही उन्होंने यह फैसला किया था कि वह टीवी से ब्रेक लेकर बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाएंगी। राधिका ने कहा कि जब भी कोई यह कहता था कि टीवी ऐक्टर्स को कोई फिल्मों में नहीं लेता तो वह हमेशा सुशांत का उदाहरण देती थीं।

नेपोटिजम पर बात करें लेकिन इसे अपना एजेंडा न बनाएं... सुशांत की आत्महत्या के बाद एक बड़े वर्ग का कहना है कि सुशांत बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिजम का शिकार हुए। इस बारे में बात करते हुए राधिका ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि किसी को अपना एजेंडा चलाने के लिए सुशांत को जरिया बनाना चाहिए क्योंकि किसी को भी अभी तक यह ठीक से नहीं पता है कि आखिर हुआ क्या था।

मैंने भी झेला है रिजेक्शन... राधिका से पूछा गया कि क्या उन्होंने भी टीवी से फिल्मों में आने के कारण भेदभाव का सामना किया है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि टीवी से आने के कारण तो नहीं लेकिन इंडस्ट्री से बाहर का होने के कारण ऐसा जरूर हुआ। राधिका ने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिजम मौजूद है और सब लोग इस बारे में जानते हैं लेकिन वह नहीं चाहतीं कि लोग इस मुद्दे पर अपनी जिंदगी गंवा दें क्योंकि इस मुद्दे का सामना करके इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है।

शेखर सुमन बोले– सुशांत पार्टी कर रहे थे, सुसाइड कैसे कर सकते हैं?

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एक ओर जहां फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, वहीं शेखर सुमन लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। शेखर ने सवाल उठाया कि जब सुशांत पार्टी कर रहे थे, प्लेस्टेशन खेल रहे थे, सुबह उठकर जूस भी पिया तो उनकी मनोदशा से साफ है कि वह सुइसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकते। शेखर सुमन ने सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक फोरम भी बनाया है। वह कहते हैं, सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में बहुत-बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी जो मांग है, वही सब की मांग है। सबके दिमाग में ही एक सवाल है, यह जो खुदकुशी हुई है कहीं वह मर्डर तो नहीं?

शांतिप्रिया बोलीं– मेरे सांवले रंग पर अक्षय कुमार ने किया था भद्दा मजाक

रंगभेद के कारण बहन भानुप्रिया ने भी छोड़ा था बॉलीवुड

साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री शांतिप्रिया इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। एक इंटरव्यू में शांतिप्रिया से सवाल किया गया कि क्या कभी अपने सांवले रंग के कारण उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। सवाल सुनकर शांतिप्रिया की आंखों के कोर से लगातार आंसू बहने लगे, रंगभेद का शिकार वह अकेले नहीं हुई थीं, बहन भानुप्रिया को भी गहरे रंग के कारण शर्मिंदा होना पड़ा, आखिरकार भानुप्रिया ने बॉलीवुड छोड़ दिया। शांतिप्रिया बताती हैं कि जब तक वे हिंदी फिल्मों में काम करती रहीं, अपने रंग को लेकर बेहद कॉन्शस रहीं, आज उनका बड़ा बेटा मॉडल है, लेकिन फिर वही गहरा सांवला रंग, बेटे के कैरियर में अड़ंगा बन गया है। शांतिप्रिया ने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर अक्षय के अलावा अभिनेता पंकज धीर, चांदनी, पृथ्वी, राज सिप्पी, स्पॉट दादा, मेकअप

मैन और भी बाकी लोग थे, लगभग 100 लोग रहे होंगे। सबके सामने अक्षय ने कहना शुरू किया कि अरे शांति के पैरों में बड़े-बड़े ब्लड क्लॉट्स हैं, उन्होंने सबको दिखाते और बताते हुए कई बार यह दोहराया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ब्लड क्लॉट्स मेरे पैर में कहां से आ गया। मैंने पूछा कहां है ब्लड क्लॉट्स, अक्षय ने कहा कि अपने घुटनों को देखो।

बेन स्टोक्स पहली बार करेंगे कप्तानी

बेन स्टोक्स को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड का कप्तान नियुक्त किया गया। उन्हें जो रूट की जगह कप्तान बनाया गया है, जो अपने बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। रूट की पत्नी कैरी इस सप्ताह मां बनने वाली वाली है और वह अपने दूसरे बच्चे के जन्म के समय अस्पताल में रहना चाहते हैं।

बेन स्टोक्स पहली बार इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम की अगुवाई करेंगे। उन्होंने अब तक इंग्लैंड की तरफ से 63 टेस्ट मैचों में 4056 रन बनाने के अलावा 147 विकेट भी लिए हैं। स्टोक्स ने इसके अलावा 95 वनडे और 26 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं लेकिन उन्होंने अब तक प्रथम श्रेणी, लिस्ट ए या टी20 मैचों में भी कप्तानी नहीं की है। इस तरह से वह इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में सबसे कम अनुभवी कप्तान बनेंगे।

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बयान में कहा, पिछले साल जुलाई से रूट के साथ उप कप्तान रहे डरहम के ऑल राउंडर बेन स्टोक्स साउथम्पटन में पहले टेस्ट मैच में टीम की अगुवाई करेंगे। बेन स्टोक्स के साथ जोस बटलर को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में रूट के साथ भी यह भूमिका निभा चुके हैं और सीमित ओवरों की टीम में इयोन मोर्गन के साथ उप कप्तान हैं। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच साउथम्पटन में आठ जुलाई से शुरू होगा। स्टोक्स के साथ जोस बटलर उप-कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे।

ईसीबी ने कहा कि अस्पताल से लौटने के बाद रूट सात दिनों तक खुद को पृथकवास में रखेंगे और 13 जुलाई से मैनचेस्टर में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे। दूसरा टेस्ट मैच 16 जुलाई से शुरू होगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 8 से 12 जुलाई के बीच साउथैंप्टन में होने वाले पहले टेस्ट मैच से होगी। सीरीज का दूसरा मैच 16 से 20 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 24 से 28 जुलाई के बीच मैनचेस्टर में ही खेला जाएगा।

नितिन की उंगली पर नाचेंगे दिग्गज

नितिन मेनन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। वे पैनल में सबसे युवा सदस्य हैं। अब नितिन अपनी उंगलियों पर क्रिकेट के धुरंधरों को नचाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें मौका कब मिलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। नितिन मेनन एशेज सीरीज को सर्वोच्च चुनौती मानते हैं लेकिन उनका कहना है कि मौजूदा हालात में सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ी जानबूझकर या अनजाने में गेंद पर लार नहीं लगाएं। 22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना छोड़ने वाले 36 साल के मेनन इसके बाद अंपायरिंग से जुड़े जिसका हिस्सा उनके परिवार में कई सदस्य हैं। मेनन ने तीन साल पहले अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया और सोमवार को 12 सदस्यीय एलीट पैनल में उनका प्रवेश सोने पर सुहागा रहा।

कोविड-19 महामारी के बीच एलीट पैनल का हिस्सा बने मेनन को नहीं पता कि उन्हें कब अंपायरिंग का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें पता है कि आईसीसी के मौजूदा दिशानिर्देशों को लागू करना बड़ी चुनौती होगी। मेनन ने पीटीआई से कहा, मुख्य चुनौती गेंद को संभालना होगा, यह चुनौती टेस्ट मैचों में अधिक होगी। शुरुआत में नियमों को लागू करने से पहले हम खिलाड़ियों को चेतावनी देंगे, जैसा कि हम तब करते हैं जब कोई खिलाड़ी खतरनाक तरीके से पिच पर दौड़ता है।

इंदौर के रहने वाले इस अंपायर ने कहा, खिलाड़ियों के जानबूझकर की जगह गलती से लार लगाने की संभावना अधिक है, इसलिए हम इसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। इंग्लैंड में सीरीज (अगले महीने शुरू होने वाली) के बाद खेलने के हालात को लेकर विस्तृत नियम आएंगे जिसके बाद हमें बेहतर पता चलेगा कि खेल में हाल में किए गए बदलावों को कैसे लागू करना है। स्थिति सामान्य होने पर मेनन को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज का हिस्सा बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने एशेज में अंपायरिंग का सपना देखा है। यह एकमात्र सीरीज है जो मैं टीवी पर देखता हूं। वहां का माहौल, जिस तरह से सीरीज खेली जाती है उसका मैं भी हिस्सा बनना चाहता हूं। यह इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में मैं इसका हिस्सा बनना पसंद करूंगा। और विश्व कप में अंपायरिंग, यह चाहे टी-20 हो या वनडे अंतरराष्ट्रीय। कोरोना वायरस महामारी के कारण यात्रा संबंधी पाबंदियों को देखते हुए आईसीसी ने फैसला किया है कि सीरीजों में केवल स्थानीय अंपायर अंपायरिंग करेंगे। इंग्लैंड में पहुंचने के बाद ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वेस्टइंडीज टीम को जिस तरह पृथकवास में रहना पड़ा अंपायरों को भी वैसा ही करना होगा और मेनन को लगता है कि इसका अंपायरों पर मानसिक प्रभाव पड़ेगा।

खिलाड़ियों का गेंद पर लार नहीं लगाना सुनिश्चित करने के अलावा अंपायरों को यह भी देखना होगा कि खिलाड़ी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें और गेंद के संपर्क में आने के बाद वे हाथ को नियमित रूप से सैनिटाइज करें। अंपायरों को भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा ओर अब उन्हें मैदान पर खिलाड़ी की निजी चीजों को नहीं संभालना होगा। मेनन ने कहा, ग्लव्स पहनना अंपायरों की व्यक्तिगत पसंद होगी लेकिन हमने फैसला किया है कि हम अपनी जेब में सैनिटाइजर रखेंगे। विकेट गिरने के बाद और ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हमें हाथ में गेंद रखी होगी इसलिए सुरक्षित रहना बेहतर है। उन्होंने कहा, च्और अगर खिलाड़ी गेंद पर लार लगा देते हैं तो हमें उसे तुरंत सेनेटाइज करना होगा। यह चौथे अंपायर का काम होगा। वह वाइप्स लेकर आएगा और गेंद को सैनिटाइज करेगा। खेल में हो रहे इन बदलावों का ओवर गति पर असर पड़ सकता है लेकिन मेनन ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

● आशीष नेमा

दिन-रात काम और पैसे के चक्कर में जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं उनसे कहा जाए चलो फुर्सत हो गई अब मर जाओ। तो हो सकता है कि वे आपके पीछे हंटर लेकर दौड़ पड़ें। क्योंकि काम सब बंद हो गए और पैसा आना भी बंद है। ऐसे लोग कसम खा लेंगे कि भूल से भी ये नहीं कहेंगे कि मरने की फुर्सत नहीं। फुर्सत नहीं थी तब कोई जहर खाकर मरने की तैयारी करता, कोई फांसी लगाकर लटकने की सोचता, कोई रेल पटरी पर सोने का मन बनाता। लेकिन कोरोना ने आकर जबसे चपेट में लेना शुरु किया है हर कोई मरने के नाम से ही डरने लगा है।

चलो, फुर्सत हो गई अब मर जाओ

एक समय था, जब आदमी कहता था कि मरने की फुर्सत नहीं है, आदमी का ये जुमला सुनकर ही लगाता है कि कोरोना आदमी के फुर्सत से मरने की व्यवस्था करने आया है। लॉकडाउन लगवाकर सबको फुर्सत करवा दी और कह रहा है- लो मरो, अब फुर्सत है। पर मारना कोई नहीं चाहता हर आदमी जिंदा रहने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। जुगाड़ इसलिए कि मास्क, सैनेटाइजर दोनों हमारे देश में जुगाड़ के चल रहे है। एन-91 का काम हमारे यहां घर पर बनी मुंह पट्टी और गमछा कर रहा है। सैनेटाइजर का काम शहरों में सर्फ का पानी और गांवों में राख कर रही है।

जो दादी रोज ओटले पर बैठकर मोहल्ले के लोगों को सुनाते हुए कहती थी कि 'भगवान मुझे उठा ले- भगवान मुझे उठा ले' वो भी कोरोना के आते ही घर के अंदर घुस गई हैं। चौबीस घंटे मास्क लगाकर रख रही हैं। और दिन-रात घर के दरवाजे की तरफ देखती रहती है, कोई अपरिचित घर में आए तो देहरी के भीतर नहीं आने देती। हर अंजान उसे मौत का दूत लगता है। किसी को अपनी खटिया के करीब भी नहीं आने देती। सैनेटाइजर की बोतल सिरहाने ही रखती है और दिन में चालीस बार अपने हाथों पर लगाती है। और अब तो ये कहना भी छोड़ चुकी है कि भगवान मुझे उठा ले।

दिन-रात काम और पैसे के चक्कर में जो कहते थे कि मरने की फुर्सत नहीं, उनसे कहा जाए चलो फुर्सत हो गई अब मर जाओ। तो हो सकता है कि वे आपके पीछे हंटर लेकर दौड़ पड़ें। क्योंकि काम सब बंद हो गए और पैसा आना भी बंद है। ऐसे लोग कसम खा लेंगे कि भूल से भी ये नहीं कहेंगे कि मरने की फुर्सत नहीं। फुर्सत नहीं थी तब कोई जहर खाकर मरने की तैयारी करता, कोई फांसी लगाकर लटकने की सोचता, कोई रेल पटरी पर सोने का मन बनाता। लेकिन कोरोनावायरस ने आकर जबसे चपेट में लेना शुरू किया है हर कोई मरने के नाम से ही डरने लगा है।

पहले कोई हार्टअटैक से मरता, कोई सांस रुकने से मरता, कोई छाती में गैस चढ़ने से मरता, कोई गंभीर बीमारी से मरता, पर अब तो हर मरने वाला अपनी मौत का इल्जाम इस कोरोना पर ही लगाकर जा रहा है। एक कोरोना ने सारे कारण खत्म कर दिए। सोचिए व्यस्त और त्रस्त जिंदगी के बीच एक स्वस्थ जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घर के लोग कहते थे 'काम का न काज का, दुश्मन अनाज का' यानी असल जिंदगी में इनके पास कोई काम नहीं होता है दिन-रात केवल आभासी काम यानी टिकटॉक, फेसबुक, और वॉट्सएप के अलावा उनको कुछ सूझता ही नहीं है और सोफे और पलंग पर गड्डे जिनकी वजह से पड़ जाते है, जिनको सुबह उठते ही ताने सुनने पड़ते है। और कोई काम घर से बाहर का बताओ तो पड़ोसी के ओटले पर जाकर आधा घंटा वीडियो देखने के बाद काम करके घर आते है। वे अब कोरोना के आने के बाद से अपना जीवन अब बहुत शांति से गुजार रहे हैं।

उनको अब न ताने सुनने पड़ रहे हैं और न ही कोई घर से बाहर जाने को बोलता है। घर के लोग भी सोचते हैं पड़ा रहने दो, घर से बाहर गया तो न जाने कहां से सामान के साथ कोरोना ले आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बाहर जाकर वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, कम से कम घर में रहकर आठ-दस वॉट्सएप ग्रुप तो चला रहा है। इसके अंडर में दो-ढाई हजार लोग तो हैं जो बिना पगार के लोगों को सूचनाएं भेजते है और कोरोना के विकट दौर में लोगों का मनोरंजन करते है। ये स्मार्टफोन में घुसकर ही स्मार्ट बन गया तो ही अपने भाग्य संवर जाएंगे। वैसे भी सरकार 'वर्क फ्रॉम होम' पर ही तो जोर दे रही है। बाहर जा कर मौत ले आए उससे तो अच्छा ही है कि घर में रहे और काम करे तो साल भर में इसकी लुगाई ला देंगे। बस ये फुर्सत में न रहे। इसे मरने की फुर्सत भी न मिले यही सबकी कामना है।

● **संदीप सृजन**

जल ही जीवन है...

बारिश के पानी का संरक्षण करें...

संजय शर्मा

कॉन्ट्रैक्टर

शहडोल, (मप्र)

जल है तो कल है...

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है ...

मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं

मलेरिया बुखार के लक्षण :

- कंपकंपी के साथ तेज बुखार।
- सिरदर्द, उल्टी होना।
- बेचैनी, कमजोरी, सुस्ती।
- रुक-रुककर बुखार आना।
- पसीना आकर बुखार उतर जाना।
- मितली, ठंड, गर्मी या तपन का महसूस होना।

मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर :

- रैपिड किट या माइक्रोस्कोपिक जाँच के द्वारा खून की जाँच अवश्य करायें। मलेरिया की पुष्टि होने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा बताई गई दवाइयों का पूर्ण रूप से सेवन करें।

मलेरिया का उपचार :

- पी.एफ. मलेरिया के उपचार में ए.सी.टी. तीन दिन व प्राइमाक्वीन दूसरे दिन के डोज के साथ ली जाती है।
- पी.वी. मलेरिया के उपचार में क्लोरोक्वीन तीन दिन व प्राइमाक्वीन पहले दिन से चौदहवें दिन तक ली जाती है।
- प्राइमाक्वीन की दवा गर्भवती महिला व 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को नहीं दी जाती है।

मलेरिया की जाँच व उपचार सभी ग्राम आरोग्य केन्द्र, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू. के पास तथा सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पताल में पूर्णत: नि:शुल्क उपलब्ध है।

आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के सरल उपाय

मच्छरदानी के भीतर ही सोयें।

खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगायें। मच्छर निरोधक का प्रयोग करें

हल्के रंग के कपड़े पहनें एवं हाथ पैरों को पूरा ढंकें।

हर सप्ताह कूलर, टंकी और बैरल के पानी को बदलें।

आस-पास पानी को जमा न होने दें

तेज बुखार, उल्टी और बदन दर्द होने पर तुरंत चिकित्सक से सम्पर्क करें

सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2020

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी